4 राजधानी
मेलों और प्रदर्शनियों को मिली हरी झंडी

6 अभिमत
बंदूक की नोक पर सफल नहीं होगी कूटनीति

10 विदेश
तालिबान को मजबूत करने में पाक की अहम भूमिका

11 विविध
सिनेमा जगत में एक नया चेहरा

RNI NO.DELHIN/2012/48369
वर्ष 9 अंक 305
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, 16 सितम्बर, 2021
पृष्ठ 12 मूल्य ₹ 3
नगर संस्करण

नई दिल्ली, लखनऊ, रायपुर और फरीदाबाद से प्रकाशित

पायनियर

www.dailypioneer.com

टी-20 रैंकिंग में विराट चौथे स्थान पर

स्पोर्ट्स-12

दूरसंचार क्षेत्र को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा

- बिना सरकारी मंजूरी के हो सकेगा 100 फीसदी विदेशी निवेश, बकाए भुगतान के लिए चार साल की मोहलत भी मिली
- ऑटो, ड्रोन क्षेत्रों के लिए 26,058 करोड़ रुपये की पीएलआई योजना को भी दी मंजूरी

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

नई दिल्ली में बुधवार को पत्रकारों को संबोधित करते केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव और अनुराग ठाकुर

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को दूरसंचार क्षेत्र के लिए बड़े सुधारों का ऐलान किया। इसके तहत दूरसंचार क्षेत्र में बकाए भुगतान पर चार साल का मोरेटोरियम दिया गया है। साथ ही कैबिनेट ने इस क्षेत्र में स्वत: मंजूर मार्ग 100 फीसदी एफडीआई (विदेशी प्रत्यक्ष निवेश)को भी मंजूरी प्रदान की है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ऑटो, ऑटो कलपुर्जा और ड्रोन उद्योग के लिए 26,058 करोड़ रुपए की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद निर्णय की जानकारी देते हुए दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दूरसंचार क्षेत्र के लिए नौ संरचनात्मक सुधारों को मंजूरी दी गई है। राहत पैकेज में दूरसंचार कंपनियों के ऊपर सांविधिक बकाए के भुगतान पर चार साल के लिए रोक यानी मोहलत दी गई है। सकल समायोजित राजस्व (एजीआर) की परिभाषा को युक्तिसंगत बनाते हुए इसमें से दूरसंचार क्षेत्र से इतर होने वाली आय को हटा दिया गया है। दूरसंचार क्षेत्र में दबाव का एक प्रमुख कारण एजीआर का मुद्दा था। मंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल ने स्वत: मंजूर मार्ग से 100 प्रतिशत एफडीआई की भी अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि अन्य उपायों में बकाया, एजीआर और स्पेक्ट्रम बकाया भुगतान पर चार साल की मोहलत शामिल हैं। इन उपायों से दूरसंचार क्षेत्र में कुछ कंपनियों के समक्ष उत्पन्न नकदी की समस्या दूर होगी।

वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कहा कि पीएलआई योजना भारत में उन्नत ऑटोमोटिव तकनीक की वैश्विक आपूर्ति शृंखला के विकास को प्रोत्साहित करेगी। इस कदम से 7.6 लाख से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिलने का अनुमान है। ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि उद्योग को पांच साल में 26,058 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीएलआई योजना के तहत पांच वर्षों में 42,500 करोड़ रुपए से अधिक का नया निवेश होगा और 2.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का वृद्धिशील उत्पादन होगा। दूरसंचार क्षेत्र के लिए सरकार की घोषणा पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (आरआईएल) के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि सरकार के नए सुधारों और राहत उपायों से दूरसंचार क्षेत्र डिजिटल इंडिया मिशन के तहत निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने में सक्षम होगा। अंबानी ने कहा, दूरसंचार क्षेत्र अर्थव्यवस्था को गति देने वाले प्रमुख कारकों में से एक है और भारत को एक डिजिटल समाज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं भारत सरकार के सुधारों और राहत उपायों की घोषणा का स्वागत करता हूं। यह उद्योग को डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। मैं प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) को इस सहासिक पहल के लिए धन्यवाद देता हूं। आरआईएल की दूरसंचार इकाई जियो ने कहा कि ये सुधार भारत के दूरसंचार क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में समय पर उठाया गया कदम हैं। इससे कंपनी ग्राहकों के लिए नए और बेहतर लाभ लाने को लेकर प्रोत्साहित होगी।

वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूरसंचार क्षेत्र से जुड़े केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले को एक ऐतिहासिक क्षण करार देते हुए कहा कि ये सुधार इस क्षेत्र और उपभोक्ताओं दोनों के लिए फायदे का सौदा हैं क्योंकि इससे क्षेत्रीय विकास तथा रोजगार के अवसर सुनिश्चित होंगे। प्रधानमंत्री ने ऑटो और ड्रोन उद्योग से जुड़े मंत्रिमंडल के एक और फैसले को लेकर कहाकि सुधार के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए मंत्रिमंडल ने वाहन उद्योग और ड्रोन उद्योग के लिए एक पीएलआई (उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन) योजना को मंजूरी दी है। इससे विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा और यह क्षेत्र को वैश्विक रुझानों के साथ-साथ सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुकूल बनाएगा। उद्योग संगठन ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया (डीएफआई) ने कहा कि ड्रोन क्षेत्र के लिए उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना से उद्यमियों को वैश्विक बाजार के लिए ड्रोन, कलपुर्जों और सॉफ्टवेयर के निर्माण की दिशा में प्रयास करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

एयर इंडिया के लिए टाटा ने बोली लगाई, स्पाइस जेट भी होड़ में

- 15 सितंबर थी बोली लगाने की आखिरी तारीख, घाटे में चल रही कंपनी

राजेश कुमार। नई दिल्ली

एयर इंडिया के अधिग्रहण के लिए टाटा संस और स्पाइसजेट के अजय सिंह ने बोली लगाई है। यदि टाटा ने एयर इंडिया खरीद लिया तो इतिहास खुद को दोहरायेगा। ग्रुप ने 67 साल पहले एयर इंडिया को शुरू किया था। टाटा समूह के जे.आर.डी. टाटा इसके संस्थापक थे। वे खुद पायलट थे। तब इसका नाम टाटा एयर सर्विस रखा गया। 1938 तक कंपनी ने अपनी घरेलू उड़ानें शुरू कर दी थीं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसे सरकारी कंपनी बना दिया गया। आजादी के बाद सरकार ने इसमें 49 फीसदी हिस्सेदारी खरीदी थी। निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडे ने ट्विटर पर लिखा कि लेनदेन सलाहकार को एयर इंडिया के विनिवेश के लिए वित्तीय बोलियां मिली हैं। प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। केंद्र सरकार सरकारी स्वामित्व वाली एयरलाइन में अपनी 100 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचना चाहती है जिसमें एआई एक्सप्रेस लिमिटेड में एयर इंडिया की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी और एयर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में 50 प्रतिशत हिस्सेदारी शामिल हैं। जनवरी, 2020 से शुरू हुई विनिवेश की प्रक्रिया में कोविड-19 महामारी के कारण देरी हुई है।

सरकार ने अप्रैल, 2021 में संभावित बोलीदाताओं को वित्तीय बोली सौंपने के लिए कहा था। रिपोर्टों के मुताबिक टाटा संस के एक प्रवक्ता ने टाटा ने एयर इंडिया के लिए बोली लगाई है। हालांकि टाटा संस ने बोली में अपनी भागीदारी की पुष्टि की है लेकिन सूत्रों ने बताया कि घरेलू कैरियर स्पाइस जेट के अजय सिंह ने भी एयर इंडिया के विनिवेश के लिए बोली लगाई है। इससे पहले नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस बात की पुष्टि की थी एयर इंडिया की बोली के लिए 15 सितंबर ही अंतिम तिथि रहेगी। एयर इंडिया की रणनीतिक बिक्री के लिए फरवरी 2019 में आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने हरी झंडी दी थी। कोविड महामारी के के कारण एयर लाइन की प्रस्तावित बिक्री में विलंब हुआ।

जनवरी, 2020 में दीपम द्वारा जारी एयर इंडिया के ईओआई के अनुसार, 31 मार्च, 2019 तक एयरलाइन के कुल 60,074 करोड़ रुपए के ऋण में, खरीदार को 23,286.5 करोड़ रुपए के ऋण की जिम्मेदारी लेनी होगी। बाकी ऋण एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) को हस्तांतरित किया जाएगा, जो एक विशेष इकाई (एसपीवी) है।एयरलाइन के लिए सफल बोली लगाने वाली कंपनी को घरेलू हवाई अड्डों पर 4,400 घरेलू और 1,800 अंतरराष्ट्रीय लैंडिंग एवं पार्किंग स्लॉट के साथ-साथ विदेशी हवाई अड्डों पर 900 स्लॉट का नियंत्रण हासिल होगा। इसके अलावा, कंपनी को एयरलाइन की कम लागत वाली सेवा एयर इंडिया एक्सप्रेस का 100 प्रतिशत और एआईएसएटीएस का 50 प्रतिशत स्वामित्व मिलेगा। एआईएसएटीएस प्रमुख भारतीय हवाई अड्डों पर कार्गो और ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करती है।

दिल्ली में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक

- प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने किया फैसला

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

दीवाली के समय राष्ट्रीय राजधानी के प्रदूषण की खतरनाक स्थिति को देखते हुए पिछले साल की तरह इस बार भी हर प्रकार के पटाखों के भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंधी रहेगी। प्रदूषण पर लगाम लगाने के मकसद से दिल्ली सरकार ने यह अहम फैसला किया है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी व्यापारियों से अपील है कि इस बार पूर्ण प्रतिबंध को देखते हुए पटाखों का किसी भी तरह का भंडारण न करें। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हम सभी को जिम्मेदारी लेनी होगी। इस बीच एनजीटी ने भी जहां पर हवा की गुणवत्ता खराब या बहुत खराब की श्रेणी में है, वहां कोरोना के दौरान पटाखों के भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को ट्वीट कर कहा पिछले 3 साल से दीवाली के समय दिल्ली की हवा जहरीली हो जाती है।

इस खतरनाक स्थिति को देखते हुए सभी तरह के पटाखों के भंडारण, बिक्री और जलाने पर रोक लगा दी गई है। जिससे लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। मुख्यमंत्री ने एक अन्य ट्वीट में कहा पिछले साल व्यापारियों द्वारा (शेष पेज 9)

तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद अर्पिता घोष ने दिया त्यागपत्र

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

तृणमूल कांग्रेस सांसद अर्पिता घोष ने राज्यसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है और सभापति एम वेंकैया नायडू ने इसे स्वीकार कर लिया है। यह जानकारी राज्यसभा सचिवालय से बुधवार को जारी अधिसूचना में दी गई। घोष के इस्तीफा से उनके पार्टी के ही अन्य सदस्य चकित हैं। अधिसूचना में कहा, राज्यों की परिषद (राज्यसभा) की निर्वाचित सदस्य श्रीमती अर्पिता घोष, जो पश्चिम बंगाल राज्य का प्रतिनिधित्व करती हैं, ने राज्यसभा की अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया है और उनका इस्तीफा 15 सितंबर 2021 को सभापति ने स्वीकार कर लिया है। घोष हाल में संपन्न मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में हुए हंगामे के कारण निलंबित सदस्यों में शामिल थीं। इस हंगामे के दौरान सांसद और मार्शल कथित तौर पर घायल हुए थे। सूत्रों ने संकेत दिया कि उनकी पार्टी ने उन्हें इस्तीफा देने को कहा था। उन्होंने कहा कि पार्टी उनके कामकाज से प्रसन्न नहीं थी और उन्हें इस्तीफा देने के लिए (शेष पेज 9)

न्यायाधिकरणों में पसंदीदा लोगों की नियुक्तियों पर सुप्रीम कोर्ट नाखुश

- रिक्त पद न भरे जाने पर भी शीर्ष अदालत ने जताई नाराजगी

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने देश भर के न्यायाधिकरणों में रिक्त पद नहीं भरे जाने पर बुधवार को नाराजगी व्यक्त की और कहा कि जिस तरह से नियुक्तियां की गई हैं, वे अपनी पसंद के लोगों का चयन किए जाने का स्पष्ट संकेत देती हैं। न्यायालय ने केंद्र को दो सप्ताह के भीतर उन न्यायाधिकरणों में नियुक्तियां करने का निर्देश दिया है, जहां पीठासीन अधिकारियों के साथ-साथ न्यायिक एवं तकनीकी सदस्यों की भारी कमी है।

न्यायालय ने केंद्र से यह भी कहा कि यदि अनुशंसित सूची में शामिल व्यक्तियों को नियुक्त नहीं किया जाता है, तो वह इसका कारण बताए। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव की पीठ ने कहा कि न्यायाधिकरणों में रिक्तियों के कारण स्थिति दयनीय है और वादियों को अधर में नहीं छोड़ा जा सकता। पीठ ने अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल से कहा, जारी किए गए नियुक्ति पत्र इस ओर स्पष्ट इशारा करते हैं कि उन्होंने चयन सूची से अपनी पसंद से तीन लोगों और प्रतीक्षा सूची से अन्य लोगों को चुना तथा चयन सूची में अन्य नामों को नजरअंदाज किया। सेवा कानून में आप चयन सूची को नजरअंदाज करके प्रतीक्षा सूची से नियुक्ति नहीं कर सकते। यह किस प्रकार का चयन एवं नियुक्ति है? वेणुगोपाल ने पीठ को आश्वासन दिया कि केंद्र खोज और चयन समिति द्वारा अनुशंसित व्यक्तियों की सूची से दो सप्ताह में न्यायाधिकरणों में नियुक्तियां करेगा। वरिष्ठ वकील अरविंद दातार ने कहा कि आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी) के लिए खोज एवं चयन समिति ने 41 लोगों की सिफारिश की, लेकिन केवल 13 लोगों को चुना गया और यह चयन किस आधार किया गया, यह हम नहीं जानते।

पीठ ने कहा, यह कोई नई बात नहीं है। हर बार की यही कहानी है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों ने कोविड-19 के दौरान नामों का चयन करने के लिए व्यापक प्रक्रिया का पालन किया और सभी प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। उन्होंने कहा, हमने देशभर की यात्रा की। हमने इसमें बहुत समय दिया। कोविड-19 के दौरान आपकी सरकार ने हमसे जल्द से जल्द साक्षात्कार लेने का अनुरोध किया। हमने समय व्यर्थ नहीं किया। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि ताजा नियुक्ति (शेष पेज 9)

पाकिस्तान को कश्मीर का मुद्दा उठाना पड़ा भारी

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में उठाया था मसला, भारत ने कहा-ज्ञान न दें, इस्लामिक सहयोग संगठन को भी लताड़

भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) में कश्मीर मुद्दा उठाने पर पाकिस्तान और इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) की बुधवार को आलोचना की। भारत ने कहा कि ओआईसी ने लाचार होकर खुद पर पाकिस्तान को हावी हो जाने दिया। यूएनएचआरसी के 48 वें सत्र में भारत ने कहा कि पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर एक ऐसा देश करार दिया गया है जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आतंकवादियों सहित अन्य आतंकवादियों को राजकीय नीति के तहत खुल कर समर्थन करता है, प्रशिक्षण देता है, वित्त पोषण करता है और हथियार मुहैया करता है।

जिनेवा में भारत के स्थाई मिशन के प्रथम सचिव पवन बाधे ने भारत की ओर से यह कहा। उन्होंने पाकिस्तान और ओआईसी द्वारा कश्मीर पर की गई टिप्पणी का जवाब देने के भारत के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए कहा कि उसे (भारत को) पाकिस्तान जैसे नाकाम मुल्क से सबक सीखने की जरूरत नहीं है, जो आतंकवाद का केंद्र है और मानविधकारों का घोर हनन करता है।

बाधे ने कहा कि भारत के खिलाफ अपने झूठे और दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार का यूएनएचआरसी के मंच का दुरूपयोग करने की पाकिस्तान की आदत सी हो गई है। उन्होंने कहा, परिषद पाक के कब्जे वाले क्षेत्रों सहित पाकिस्तान के अन्य इलाकों में उसकी सरकार द्वारा किए जा रहे मानवाधिकारों के घोर हनन की ओर से ध्यान (शेष पेज 9)

बाजार

सेंसेक्स	58,723	↑	476	
निफ्टी	17,519	↑	139	
सोना	46,214	↑	438	/10g
चांदी	62,140	↑	633	/kg

क्विक न्यूज

जेईई-मेन में 100 उम्मीदवारों ने 100 परसेंटाइल प्राप्त किए

नई दिल्ली। इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए इस वर्ष जेईई-मेन प्रवेश परीक्षा में रिकार्ड 44 उम्मीदवारों ने 100 परसेंटाइल प्राप्त किया और 18 उम्मीदवारों ने शीर्ष रैंक साझा की। जेईई मेन परीक्षा में प्रथम रैंक प्राप्त करने वालों में गौरव दास (कर्नाटक), वैभव विशाल (बिहार), डी वेंकट पनीश (आंध्र प्रदेश) शामिल है। शीर्ष रैंक प्राप्त करने वालों में सिद्धांत मुखर्जी, अंशुल वर्मा और मृदुल अग्रवाल (राजस्थान), रुचिर बंसल एवं काव्या चोपड़ा (दिल्ली), अमिया सिंघल और पाल अग्रवाल (उत्तर प्रदेश), कोम्मा शरण्या एवं ज्वायसुला वेंकट आदित्य (तेलंगाना), पी वीर शिवा, कामम लोकेश और के राहुल नायडु (आंध्र प्रदेश), पुलकित गोयल (पंजाब) तथा गुरमीत सिंह (चंडीगढ़) शामिल है।

सोनू सूद के दफ्तर पहुंची आयकर विभाग की टीम

- मुंबई और लखनऊ के कम से कम आधा दर्जन ठिकानों पर की गई कार्रवाई

पायनियर समाचार सेवा। मुंबई, नई दिल्ली

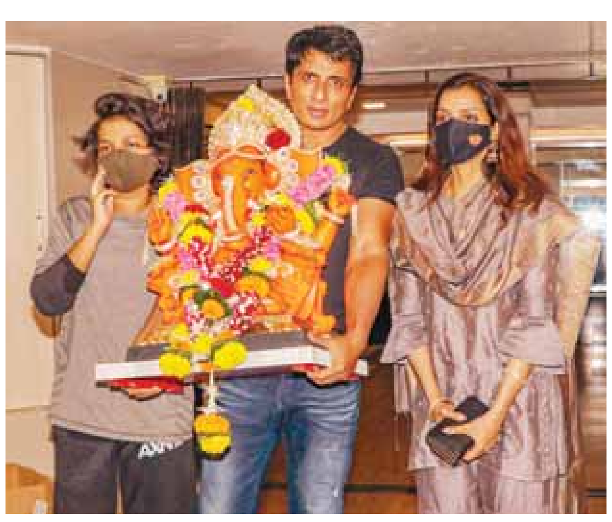

मुंबई में भगवान गणेश की मूर्ति को विसर्जन के लिए ले जाते अभिनेता सोनू सूद

आयकर विभाग के अधिकारी कथित कर चोरी मामले की जांच के सिलसिले में बुधवार को अभिनेता सोनू सूद से जुड़े मुंबई और कुछ अन्य स्थानों के ठिकानों पर पहुंचे। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जांच की यह कार्रवाई मुंबई और लखनऊ के कम से कम आधा दर्जन ठिकानों पर की गई। सूत्रों के अकाउंट बुक में गड़बड़ी को जांचने के लिए यह कार्रवाई की गयी है।

अभी तक स्पष्ट नहीं है कि क्या आयकर विभाग के अधिकारी सूद के आवास पर भी पहुंचे हैं। सूत्रों ने बताया कि संपत्ति की खरीद आयकर विभाग की नजर में है। गौरतलब है कि अभिनेता सूद पिछले साल कोविड-19 की वजह से लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन में प्रवासी कामगरों को उनके घर पहुंचने में मदद कर राष्ट्रीय चर्चा में आए थे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने हाल में 48 वर्षीय सूद को देश का मेंटर कार्यक्रम के तहत आम आदमी पार्टी सरकार का ब्रांड एंबेसडर घोषित किया है। इस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों का उनके करियर को लेकर मार्गदर्शन दिया (शेष पेज 9)

देश में बढ़ रहे हैं साइबर अपराध के मामले

- वर्ष 2020 में 50, 035 केस दर्ज किए गए जो 2019 के मुकाबले 11.8 फीसदी ज्यादा थे

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

भारत में 2020 में साइबर अपराध के 50,035 केस दर्ज किए गए जो 2019 के मुकाबले 11.8 फीसदी ज्यादा थे। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा बुधवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक सोशल मीडिया पर फेक न्यूज के 578 मामले आए।

एनसीआरबी आंकड़ों के अनुसार साइबर अपराध की दर (प्रति लाख आबादी पर) जो 2019 में 3.3 फीसदी थी, वह 2020 में बढ़कर 3.7 फीसदी हो गई। 2019 में साइबर अपराध के 44,735 मामले सामने आए थे जबकि 2018 में यह आंकड़ा 27, 248 था। 2020 में ऑन लाइन बैंकिंग धोखाधड़ी के 4,047, ओटीपी धोखाधड़ी के 1,093 तथा क्रेडिट और डेबिट कार्ड फ्रॉड के 1,194 केस दर्ज किए गए। इसके अलावा 2020 में एटीएम से जुड़े धोखाधड़ी के 2160 मामले हुए।

आंकड़ों के मुताबिक 2020 में सोशल मीडिया में फेक न्यूज के 578 मामले, साइबर स्टाकिंग या महिलाओं और बच्चों को बुलिंग के 972, फेक प्रोफाइल के 149 तथा डाटा चोरी के 98 केस दर्ज किए गए। 2020 में साइबर अपराध के 60.2 फीसदी केस (50,035 में से 30,142 मामले) दर्ज किए गए। यौन उत्पीड़न के 6.6 (3,293 केस) और वसूली के 4.9 (2,440) केस दर्ज किए गए। आंकड़ों के मुताबिक साइबर क्राइम के उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 11,097 मामले, इसके बाद कर्नाटक (10,741), महाराष्ट्र (5,496), तेलंगाना (5,024) तथा असम (3,530) का स्थान है।

भारत में 2020 में प्रतिदिन औसतन 80 हत्याएं हुईं: एनसीआरबी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, भारत में 2020 में प्रतिदिन औसतन 80 हत्याएं हुईं और कुल 29,193 लोगों का कत्ल किया गया। इस मामले में राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश अव्वल स्थान पर है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक, पूरे देश में 2020 में बलात्कार के प्रतिदिन औसतन करीब 77 मामले दर्ज किए गए। पिछले साल दुष्कर्म के कुल 28,046 मामले दर्ज किए गए। देश में ऐसे सबसे अधिक मामले राजस्थान में और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए। एनसीआरबी के अनुसार, वर्ष 2020 में दर्ज किए गए कुल अपराधों में काफी संख्या भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188 के तहत लोक सेवकों द्वारा लागू व्यवस्था का उल्लंघन करने के खिलाफ दर्ज मामले शामिल हैं। आंकड़ों के अनुसार, 2020 में उत्तर प्रदेश में हत्या के 3779 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद बिहार में हत्या के 3,150, महाराष्ट्र में 2,163, मध्य प्रदेश में 2,101 और पश्चिम बंगाल में (शेष पेज 9)

6 जिले के 1189 गांवों में ड्रोन से आबादी का सर्वे

यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की 71वीं बोर्ड बैठक में गया फैसला

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की 71वीं बोर्ड बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में यमुना प्राधिकरण ने अपने इलाके के 1189 गांवों के लिए बड़ा फैसला लिया है।

अथॉरिटी 6 जिलों के इन गांवों में ड्रोन के जरिए सर्वे करवाएगी। यह सर्वे गांवों की आबादी का होगा। इसके बाद गांवों में घरों, अहातों और दूसरी प्रॉपर्टी के दस्तावेज बनाकर निवासियों को दिए जाएंगे। इन दस्तावेजों के आधार पर गांव वाले कृषि भूमि और शहरी संपत्ति की तरह लाभ उठा सकेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के दायरे में छह जिलों गौतमबुद्ध नगर बुलंदशहर अलीगढ़ हाथरस मथुरा और आगरा के 1,189 गांव शामिल हैं। ये सारे गांव गौतमबुद्ध नगर की जेवर और सदर तहसील, बुलंदशहर जिले की खुर्जा और सिकंदराबाद तहसील अलीगढ़ की खैर तहसील हाथरस की सादाबाद हाथरस और सासनी तहसील मथुरा जिले की सदर मांट और महावन तहसील और आगरा जिले की एत्मादपुर व सदर तहसील में पड़ते हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार गांवों की आबादी को रजिस्ट्रीकृत कर रही है।

इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिलों को गांवों का सर्वे करके आबादी की संपत्तियों इमारतों और जमीनों के दस्तावेज तैयार करने का आदेश दिया है। यमुना अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि बोर्ड बैठक में राज्य सरकार के आदेशों पर अमल करते हुए सभी 6 जिलों में 1189 गांवों की आबादी का ड्रोन से सर्वे करवाने का फैसला लिया गया है। इस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जिला अधिकारी संपत्तियों के दस्तावेज ग्रामीणों को उपलब्ध करवाएंगे। यह दस्तावेज मिलने के बाद लोगों को बड़ा फायदा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि गांव वालों को अपने घरों और गांव की हद में मौजूद दूसरी संपत्तियों पर दस्तावेजी मालिकाना हक मिल जाएगा।

ग्रामीणों को होंगे 4 बड़े फायदे

- अभी गांव की आबादी का कोई स्वामित्व नहीं रहता है। जिससे आबादी की भूमि पर विवाद रहते हैं। कानून.व्यवस्था लागू करने में प्रशासन और पुलिस को परेशानी होती है। इससे विवाद खत्म हो जाएंगे और गांवों में सामाजिक एकता बढ़ेगी।
- आबादी की संपत्तियों का स्वामित्व निर्धारण होने के बाद किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्था से इस प्रॉपर्टी का मूल्यांकन करवाया जा सकता है। जरूरत पड़ने पर अपनी संपत्ति पर बैंकों से ऋण ले सकते हैं।
- आबादी की जमीनों के दस्तावेज बन जाने से गांव वालों को न्यायिक प्रक्रिया में फायदा मिलेगा। मसलन, इस संपत्ति के दस्तावेज के आधार पर अदालत से जमानत ली जा सकेंगी।
- राज्य सरकार और जिला प्रशासन को भविष्य में सभी योजनाएं लागू करने में आसानी होगी।

बोर्ड बैठक में जेवर एयरपोर्ट, मेट्रो, फिल्म सिटी व पॉड टैक्सी की प्रगति रिपोर्ट रखी

- महत्वपूर्ण चर्चा के बाद कई प्रस्तावों पर लगी मुहर

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की 71वीं बोर्ड बैठक में जेवर एयरपोर्ट, मेट्रो, फिल्म सिटी पॉड टैक्सी की प्रगति रिपोर्ट रखी गई। इसके साथ ही राया हेरिटेज सिटी और टप्पल लाजिस्टिक हब की परियोजना में अब तक हुए कामों को बताया गया।

जेवर एयरपोर्ट की साइट पर 23 अगस्त से विकासकर्ता कंपनी ने काम शुरू कर दिया है। बोर्ड ने सभी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। इसके अलावा फिल्म सिटी के लिए सेक्टर-21 के लेआउट प्लान को पुनरीक्षित किया गया है। यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ अरुणवीर सिंह ने जेवर एयरपोर्ट परियोजना की प्रगति से बोर्ड को अवगत कराया।

विकासकर्ता कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को 31 जुलाई को 1334 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा दे दिया गया। 23 अगस्त से कंपनी ने साइट पर समतलीकरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया है। ग्रेटर नोएडा के नालेज पार्क से जेवर एयरपोर्ट तक एयरपोर्ट मेट्रो परियोजना को जोड़ने के लिए डीएमआरसी को डीपीआर तैयार करने के लिए और ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क से नई दिल्ली तक मेट्रो परियोजना की फिजिबिलिटी स्टडी तैयार करने के लिए वर्क आर्डर जारी करने का अनुमोदन यमुना बोर्ड ने दे दिया। प्राधिकरण के सेक्टर-21 में स्थापित की जाने वाली फिल्म सिटी के बारे में बताया गया कि डीपीआर बनाने वाली कंपनी सीबीआरई को ग्लोबल टेंडर निकालने के लिए काम दिया गया है। इस पर बोर्ड ने अपनी सहमति जता दी है।

इस एजेंसी ने सुझाव दिया कि सेक्टर-21 में एक्सप्रेसवे के निकट के वाणिज्यिक भूखण्ड के 220 एकड़ की भूमि को फिल्म सिटी के लिए चिन्हित किया जाए। फिल्म सिटी की परियोजना के लिए सेक्टर 21 के ले-आउट प्लान को वर्तमान फिल्म सिटी के विकास की आवश्यकता के तहत पुनरीक्षित किया गया है।

यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में पॉड टैक्सी की परियोजना की रिपोर्ट रखी गई। इसके लिए इण्डियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कारपोरेशन लिमिटेड ने डीपीआर बनाई है। पॉड टैक्सी एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के बीच चलाई जाएगी।

प्राधिकरण ने 11 बिल्डर प्रोजेक्ट के खिलाफ की आरसी जारी, छह आवंटन किए निरस्त

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

नोएडा प्राधिकरण ने बकाया नहीं देने पर व्यावसायिक परियोजनाओं से जुड़े बिल्डरों के खिलाफ बीते जुलाई.अगस्त महीने में सख्त कार्रवाई की है। बकाए का भुगतान नहीं करने की वजह से 11 बिल्डर परियोजनाओं के खिलाफ आरसी जारी की गई है। जबकि 6 भूखंडों का आवंटन निरस्त किया गया है।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऋतु माहेश्वरी ने आदेश देते हुए कहा है कि डिफॉल्टर बिल्डरों के खिलाफ इस तरह की कड़ी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जानकारी के मुताबिक ई-1ए सेक्टर.52 में स्थित एमएमआर साहा इंफ्रास्टक्चर प्राइवेट लिमिटेड पर 869 करोड़ 43 लाख 86 हजार 76 रुपए सेक्टर-98 स्थित ग्रेनाइट हिल्स प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड पर 350 करोड़ रुपए सी.1, सेक्टर.16 स्थित ईटी इन्फ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड पर 63 करोड़ 1 लाख 12 हजार 462 रुपए और सी.134 बी, सेक्टर.61 स्थित सुपरटेक पर 26 करोड़ 98 लाख 52 हजार 52 रुपए बकाया है। इसके लिए जिलाधिकारी सुहास एलवाई को पत्र भेज दिया गया है।

नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी संजय कुमार ने बताया कि इनके अलावा जुलाई.अगस्त में ही मैसर्स लॉजिक्स बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड के सेक्टर.124 स्थित भूखंड पर 796 करोड़ 49 लाख 20 हजार 89 रुपए बकाया होने और इसी बिल्डर के सेक्टर-105 स्थित भूखंड पर 588 करोड़ 53 हजार 78 रुपए बकाया होने पर उनका आवंटन निरस्त कर दिया गया है।

विद्युत निगम के 11 जेई और 6 एसडीओ हटाए गए

नोएडा। ग्रेटर नोएडा और जेवर के इलाकों में निर्माण कार्यों के लिए अस्थाई कनेक्शन देने के मामले में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है।

प्राथमिक जांच के बाद पॉवर कॉरपोरेशन ने 23 अभियंताओं को जिम्मेदार माना है और उन्हें पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम से हटाकर दूसरे डिस्कॉम में भेजा गया है। इन सभी के ट्रांसफर का ऑर्डर मुख्य अभियंता कार्यालय को मिल गया था।

बताते चलें कि इन सभी के खिलाफ विभागीय जांच भी चल रही है। जिले के कई सेक्शन में विद्युत विभाग की तरफ से बड़ी गड़बड़ियां सामने आई थीं। इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों से की गई थी।

350 एकड़ में बनेगा मेडिकल डिवाइस पार्क

- दो पार्क बनेंगे, विकसित होगा डाटा सेंटर पार्क

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

यमुना प्राधिकरण के बोर्ड ने आवासीय भूखंड पेट्रोल पंप होटल और व्योस्क की योजना लाने के लिए प्रस्ताव पास कर दिया। इसके साथ ही मेडिकल डिवाइस पार्क और डाटा सेंटर पार्क की योजना का खाका रखा गया, जिसे बोर्ड ने मंजूर कर लिया।

दोनों औद्योगिक योजनाएं भी जल्द निकाली जाएंगी। इसके साथ ही मेडिकल डिवाइस पार्क डाटा सेंटर और फिल्म सिटी के लिए अलग से बिजलीघर बनाने के लिए भी मंजूरी मिल गई। यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में सीईओ डॉ अरुणवीर सिंह ने जानकारी साझा की।

उन्होंने बताया कि सामान्य की सुविधा के लिए नई आवासीय भूखण्ड योजना लाई जाएगी। इसके साथ ही क्योस्क होटल और पेट्रोल पम्प की योजनाएं लाने का निर्णय लिया गया है। ये योजनाएं प्राधिकरण के सेक्टर.18 20 17 22डी 32 29 16 और 22डी में लाई जाएंगी।

दरअसल जेवर एयरपोर्ट आने के बाद इन योजनाओं का लोग इंतजार कर रहे हैं। प्राधिकरण की आवासीय योजनाओं को तो लोगों ने हाथों हाथ लिया है। प्राधिकरण के सेक्टर-28 में 350 एकड क्षेत्र में मेडिकल डिवाइस पार्क की योजना लाई जाएगी। शासन ने मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए यमुना प्राधिकरण को अधिकृत कर दिया है। मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए कलाम इंस्टीट्यूट आफ हेल्थ टेक्नोलाजी हैदराबाद ने डीपीआर तैयार की है। फेज.1 के 90 एकड़ क्षेत्र में यह योजना आएगी। इसमें 1000 वर्ग मीटर 2500 4000 और 10000 वर्गमीटर के लगभग 89 भूखण्ड होंगे। इसके अलावा पार्क व कमर्शियल क्षेत्र भी होगा। इस योजना के लिए ब्रोशर की नियम व शते कलाम इंस्टीट्यूट ने तय की हैं। जल्द ही इस योजना को शुरू किया जाएगा। यमुना प्राधिकरण के सेक्टर.28 में की 100 एकड़ भूमि पर डाटा सेन्टर पार्क की स्थापना की जाएगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश डाटा सेन्टर.2021 नीति को अपनाया गया है। 80 प्रतिशत भाग में 10.10 एकड़ के भूखण्ड और शेष 20 प्रतिशत भाग में 5.5 एकड़ के भूखण्ड होंगे। इस योजना के लिए अभी कुछ जमीन का खरीदना बाकी है।

संक्षिप्त समाचार

गाजियाबाद में पुलिस गिरफ्त में बदमाश।

लूट में शामिल चार बदमाश गिरफ्तार

गाजियाबाद। दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों से चार शातिर लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से अवैध असलाह व लोगों से लूटी गई नकदी बरामद की है। पुलिस क्षेत्राधिकारी लोनी अतुल सोनकर ने बताया कि लोनी पुलिस ने मिठौरा निवासी कशिश द तथा नितिन ठाकुर को गिरफ्तार किया है। ये लोग क्षेत्र में कई अपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। इसी के साथ लोनी बॉर्डर पुलिस ने गौरव व निशांत को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 3200 की नकदी इन दोनों ने लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में चाऊमीन खाने आए युवक से लूटपाट की थी।

भाजपा सरकार के खिलाफ सपा का प्रदर्शन

हापुड़। देश व प्रदेश में बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार व बेरोजगारी के विरोध में बुधवार को सैंकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने पदयात्रा निकालकर जमकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने भाजपा हटाओ देश बचाओ के नारे लगाते हुए राष्ट्रपति को प्रेषित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। बुधवार को देश व प्रदेश में बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार व बेरोजगारी के विरोध में सपा युवजन सभा के सैंकड़ों कार्यकर्ता दिल्ली रोड स्तिथ एसएसवी इंटर कॉलेज के बाहर पदयात्रा के रूप में एकत्रित हुए। पूर्व मंत्री व पूर्व विधायक मदन चौहान ने पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर श्यामसुंदर भुर्जी, संजय गर्ग, आमिर मीर, कुंवरपाल यादव, सुल्तान खान, रविन्द्र यादव, गौरव गोयल, मोहसिन सलमानी, साबिर कसार, परवेज आलम, अनिकेत यादव, माधव शर्मा, सनी त्यागी सहित सैंकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।

एआरटीओ ऑफिस में हंगामे का वीडियो वायरल

नोएडा। नोएडा के आरटीओ ऑफिस में हंगामा हुआ है। इस घटनाक्रम की एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। जिसमें कुछ लोग अपने आप को बजरंग दल के कार्यकर्ता बता रहे हैं। एआरटीओ कार्यालय के अधिकारियों से बहस हो रही है। पूरा मामला नोएडा के थाना सेक्टर-24 क्षेत्र का है। दूसरी तरफमामले को लेकर एआरटीओ कार्यालय लीपापोती में जुटा है। क्या हुआ और क्यों हुआए इस पर कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। हालांकि सूचना मिली है कि एआरटीओ कार्यालय के एक कर्मचारी ने थाने में शिकायत दी है। वीडियो को देखकर पता चलता है कि अपने आप को बजरंग दल से जुडा बताने वाले कुछ लोग आरटीओ ऑफिस में घुस आए। ताला तोड़ने की बात कह रहे हैं और अधिकारी को धमकाने का प्रयास कर रहे हैं।

किसानों ने एसीईओ को सुनाई समस्याएं

नोएडा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रतिनिधिमंडल ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ अमनदीप टूली से भेंट की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने आबादी लीजबैकए लीजबैक के अन्य मामलों, 10 प्रतिशत आबादी प्लॉट तथा स्थानीय युवकों को रोजगार देने संबंधी मुद्दों पर एक ज्ञापन सौंपा। अफसर ने किसानों की सभी समस्याएं गौर से सुनीं। अखिल भारतीय किसान सभा के गौतमबुद्ध नगर के प्रवक्ता डॉ रुपेश वर्मा ने इस बारे में जानकारी दी। संगठन का एक प्रतिनिधिमंडल बालक इंटर कॉलेज में एसीईओ अमनदीप टुली से मिला। किसानों ने ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा।

समस्याओं के निपटारों को लेकर 17 को मंथन

गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश नगर निकाय में कार्यरत कर्मचारियों की समस्याएं कैसे हल हो और उन को हल कराने के लिए सरकार पर इस तरह से दबाव बनाया जाए। इसके लिए आगामी 17 सितंबर को गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है।

इस बैठक में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग से उपाध्यक्ष लाल बाबू बाल्मिकी मुख्य अतिथि होंगे। महासंघ के अध्यक्ष शशि कुमार मिश्रा, महामंत्री राकेश अग्निहोत्री, उपाध्यक्ष नैन सिंह और संयुक्त सचिव सलीम अहमद भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे।

हिन्दी पखवाड़े पर प्रतिभागी हुए पुरस्कृत

- केंद्रीय विद्यालय, क्रमांक-1, एयरफोर्स स्टेशन, हिंडन में कार्यक्रम

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

केन्द्रीय विद्यालय, क्रमांक-1,एयर फोर्स स्टेशन, हिंडन में हिन्दी दिवस के मौके पर प्रतिभागियों को कविता, निबन्ध, स्वच्छता प्रदर्शनी, एकांकी में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया। प्रकृति एवं तस्या को हिन्दी ज्ञान प्रश्नोत्तरी के किए पुरस्कृत किया गया। डा.एन.के.श्रीवास्तव ने विद्यार्थियों को प्रतिभाग हेतु प्रोत्साहित किया। इस मौके पर शोभा शर्मा, (प्राचार्या) शिवा कुमार शर्मा (उपप्राचार्य), वरिष्ठ शिक्षक डा.एन.के. श्रीवास्तव, सी सी ए प्रभारी अंजू बाला, शिक्षक उषा सिंह, अनिता राय, रमाकांत शर्मा, किरण पाल, अर्चना, मुकेश, अपर्णा वाजपेयी, मीनल, ए.एस. पांडेय, मुक्ता पंत, रेशू मलिक, अनुराग, रवीन्द्र सिंह, कुमुद रंजन, चंदा, दिव्या, शुभांगी, सरोहा, आशीष की गरिमामयी उपस्थिति रही।

हिंडन स्थित केंद्रीय विद्यालय क्रमांक-1 में हिन्दी दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में विजेता छात्र व छात्राएं। साथ में विद्यालय की प्राचार्या और शिक्षकगण।

टावर गिराने के लिए विदेशी एजेंसी से लेनी पड़ेगी मदद

नोएडा। नोएडा के सेक्टर-93ए में स्थित सुपरटेक एमरॉल्ड कोर्ट हाऊसिंग सोसाइटी में बने दोनों अवैध टॉवरों को गिराने की कवायद शुरू हो गई है। सोमवार को सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम ने मौके पर आकर टावरों की जांच कर ली है।

नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की। इन बिल्डिंगों को गिराने के लिए तीन केंद्रीय एजेंसियों से मंजूरी लेनी होगी। इमारतों से निकलने वाले मलबे का दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा। सीबीआरई ट्विन्स टॉवर को गिराने के लिए अमेरिका या यूरोप की किसी बड़ी एजेंसी से मदद लेगी।

अपनी शक्तियों को पहचाने महिलाएं: अतुल गर्ग

- एमबी गर्ल्स इंटर कॉलेज में वस्त्र प्रदर्शनी का आयोजन

प्रदर्शनी के दौरान लोगों को संबोधित करते अतुल गर्ग।

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

महिलाएं अपनी शक्तियों को पहचानें और स्वावलम्बी बनें। सिलाई सीखें, कंप्यूटर सीखें या कुछ और रोजगार के काम सीखें मगर सीखें। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य राज्यमंत्री अतुल गर्ग ने बुधवार को यह बात कही। वह अरिहंत चेरिटेबल एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा एमबी गर्ल्स इंटर कॉलेज में आयोजित द्वितीय वस्त्र प्रदर्शनी व पुरस्कार समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सम्बोधित कर रहे थे।

अपने सम्बोधन में उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए 50 से अधिक स्वरोजगार योजनाएं चला रखी हैं, जिसका लाभ लिया जा सकता है। डिजाइनिंग में बहुत स्कोप है। बच्चियां इसका लाभ ले सकती हैं। समारोह की अध्यक्षता कर रहे मेवाड़ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन डॉ. अशोक कुमार गदिया ने कहा कि महिलाएं स्वयं जागृत हों और अपनी शक्ति को पहचानकर पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ें। बिना महिला के स्वावलम्बी हुए आत्मनिर्भर देश बनने का सपना साकार नहीं हो सकता।

भूमाफिया के कब्जे से 150 करोड़ की जमीन मुक्त

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

अतिक्रमण तोड़ता बुलडोजर।

सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने वाले भूमाफिया के खिलाफ योगी सरकार का अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में जिला प्रशासन व जलशक्ति सिंचाई विभाग ने सिंचाई विभाग की 8.89 एकड़ भूमि को भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराया। इस भूमि की कीमत 150 करोड़ से ज्यादा है।

उपजिलाधिकारी देवेंद्र पाल सिंह ने बताया कि जिले के मसूरी पुल के पास सिंचाई विभाग की 8.89 एकड़ भूमि पर भूमाफिया ने अवैध कब्जा कर रखा था। उन्होंने इस जमीन में ढाबा भी बना रखा था। इसी कड़ी में जलशक्ति सिंचाई विभाग के बुलंदशहर खंड गंगा नहर खंड व गाजियाबाद के जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर भूमि को कब्जे मुक्त करा दिया। उन्होंने बताया कि इसी तरह सिंचाई व अन्य सरकारी विभागों की जमीनों पर भी भूमाफिया काबिज है, जिन्हें चिन्हित कर लिए गया है। जल्दी ही इन जमीनों को भी भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराया जाएगा। इस बड़ी कार्रवाई के बाद भूमाफिया में हड़कंप मचा हुआ है।

मंडोला के किसानों ने ली जिंदा समाधि

- पांच साल से चल रहा आंदोनल, प्रशासन मनाने में जुटा, नही बनी बात

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

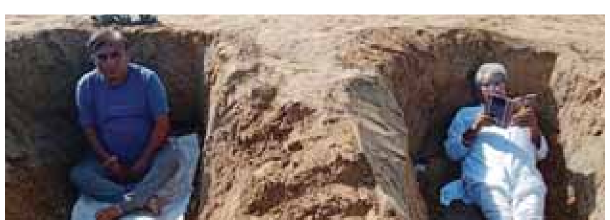
जिंदा समाधि में बैठे किसान

आवास विकास परिषद द्वारा अधिग्रहीत की गई जमीन का उचित मुआवजा अन्य मांगों को लेकर पिछले पांच सालों से आंदोलन कर रहे मंडोला के किसानों ने बुधवार को आमरण अनशन की घोषणा के साथ जिंदा समाधि ले ली।

आंदोलन से जुड़े 17 किसान गहरे गड्ढे खोदकर उनमें बैठकर जिंदा समाधि ले ली। समाधि लेने की खबर मिलने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया और जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने एसडीएम शुभांगी शुक्ला को मौके पर भेजा। शुभांगी शुक्ला ने किसानों को काफी मनाने का प्रयास किया लेकिन देर शाम तक बात नहीं बनी।

दरअसल शुभांगी शुक्ला किसानों से कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी से वार्ता करने की बात कही जबकि किसानों ने कहा कि वे इस स्थिति में नहीं है कि वह कलेक्ट्रेट जाकर वार्ता करें। जिलाधिकारी चाहे तो आवास विकास परिषद के मंडोला स्थित कार्यालय पहुंचकर उनसे वार्ता कर सकते हैं। दरअसल मंडोला विहार के किसान पिछले पांच सालों से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। वह कई बार भूख हड़ताल धरना प्रदर्शन कर चुके हैं लेकिन उनकी मांग आज तक पूरी नहीं हुई, जिस कारण किसानों में सरकार के प्रति रोष बढ़ता जा रहा है।

प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन को दी चेतावनी

किसान नेता नीरज त्यागी, योगेश त्यागी, मास्टर महेंद्र सिंह,मनवीर तेवतिया,बृजेश त्यागी, अमित त्यागी आदि ने सुबह 10:00 बजे पहले तो आमरण अनशन की घोषणा की उसके बाद कब्रनुमा गड्ढा खोदकर उसमें बैठ गए। किसानों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती वह इस समाधि से नहीं निकलेंगे। चाहे उनके प्राण चले जाए। किसान नेता नीरज त्यागी ने बताया कि वह लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगी। उन्होंने कहा यह आंदोलन और तेजी पकड़ेगा।

डीएम-एसपी ने सीएम आगमन की तैयारियों का लिया जायजा

पायनियर समाचार सेवा। हापुड़

निरीक्षण करते हुए अधिकारी।

आगामी 22 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन को दृष्टिगत रखते हुए बुधवार को जिलाधिकारी अनुज सिंह व पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने तैयारियों का निरीक्षण किया। डीएम व एसपी ने अधिकारियों के साथ पिलखुआ क्षेत्र में बनाए जा रहे हेलीपैड उतरने के स्थान से लेकर अन्य स्थानों का स्थलीय निरीक्षण किया।

डीएम ने एक्शन पीडब्ल्यूडी जोध कुमार को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री के हेलीपैड की उतरने तथा सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए सभी आवश्यक तैयारी समय से पूर्ण कर ली जाए तथा जहां-जहां पर बैरिकेडिंग की जानी है वहां का स्थान भी समय से चिन्हित करते हुए बैरिकेडिंग करा दी जाए। उन्होंने कार्यक्रम स्थल की भी जानकारी एक्शन पीडब्ल्यूडी से ली। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी उदय सिंह, अपर जिलाधिकारी जयनाथ यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष उमेश राणा, ब्लाक प्रमुख धौलाना निशांत सिसोदिया, अपर पुलिस अधीक्षक सर्वेश कुमार मिश्र सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

सीएमवाईके प्रिंटेक लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक नरेन्द्र कुमार द्वारा नं. 6, गुलाब भवन के पीछे, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002, दूरभाष: 011-40110455 से प्रकाशित तथा बीएफएल इन्फोटेक लिमिटेड सी-9 सेक्टर-3, नोएडा-201301 (उ.प्र.) से मुद्रित। कार्यकारी संपादक: नवीन उपाध्याय, स्थानीय सम्पादक: प्रदीप तिवारी। पाठकों को सुझाव दिया जाता है कि इस अखबार के किसी भी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया करने से पहले पूरी तरह उसके बारे में दिए गए दावों, शर्तों और तथ्यों की जांच कर लें। पायनियर ग्रुप के मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक या उसका कोई भी कर्मचारी विज्ञापनदाता द्वारा उनके किसी उत्पाद तथा सेवा हेतु किए गए किसी दावे की सच्चाई का आश्वासन या उत्तरदायित्व नहीं लेता है। ऐसे विज्ञापनों के बाद किसी आर्थिक क्षति के लिए वे जिम्मेदार भी नहीं हैं। पत्रवार्ता ऑफिस- एफ-31, सेक्टर 6, नोएडा, गौतमबुद्धनगर-201301, उत्तर प्रदेश, दूरभाष- 120-4879800-4879900।

कोदो, कुटकी, रागी अब बन गए हैं ख़ास
स्वास्थ्य व सुपोषण के साथ करेंगे आर्थिक विकास

धान का कटोरा छत्तीसगढ़
अब बनेगा मिलेट हब

छत्तीसगढ़ का
मिलेट मिशन

- कोदो-कुटकी एवं रागी की उत्पादकता बढ़ाने के प्रयास
- कोदो-कुटकी एवं रागी की उत्पादकता बढ़ाने हेतु तकनीकी जानकारी, उच्च क्वालिटी के बीज व सीड बैंक की स्थापना में मदद के लिए इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, हैदराबाद और 14 जिलों के साथ एमओयू
- लघु वनोपज सहकारी संघ की वन-धन समितियों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोदो-कुटकी एवं रागी की खरीदी
- लघु धान्य उपज की सही कीमत व आदान सहायता देने के साथ समर्थन मूल्य पर खरीदी, प्रोसेसिंग एवं मार्केटिंग की पहल, मिलेट के प्रसंस्करण और गुणवत्ता सुधार से किसानों, महिला समूहों और बेरोजगार युवाओं को मिलेगा रोजगार
- राज्य में दो प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित

लघु धान्य उत्पादकों को 'न्याय'

कोदो-कुटकी पर न्यूनतम समर्थन मूल्य देने वाला देश का पहला राज्य

₹3000 प्रति क्विंटल

राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत देश में सबसे ज्यादा आदान सहायता

कोदो-कुटकी और रागी की फसल लेने वाले किसानों को ₹9,000 प्रति एकड़

धान के बदले कोदो-कुटकी और रागी लेने पर ₹10,000 प्रति एकड़

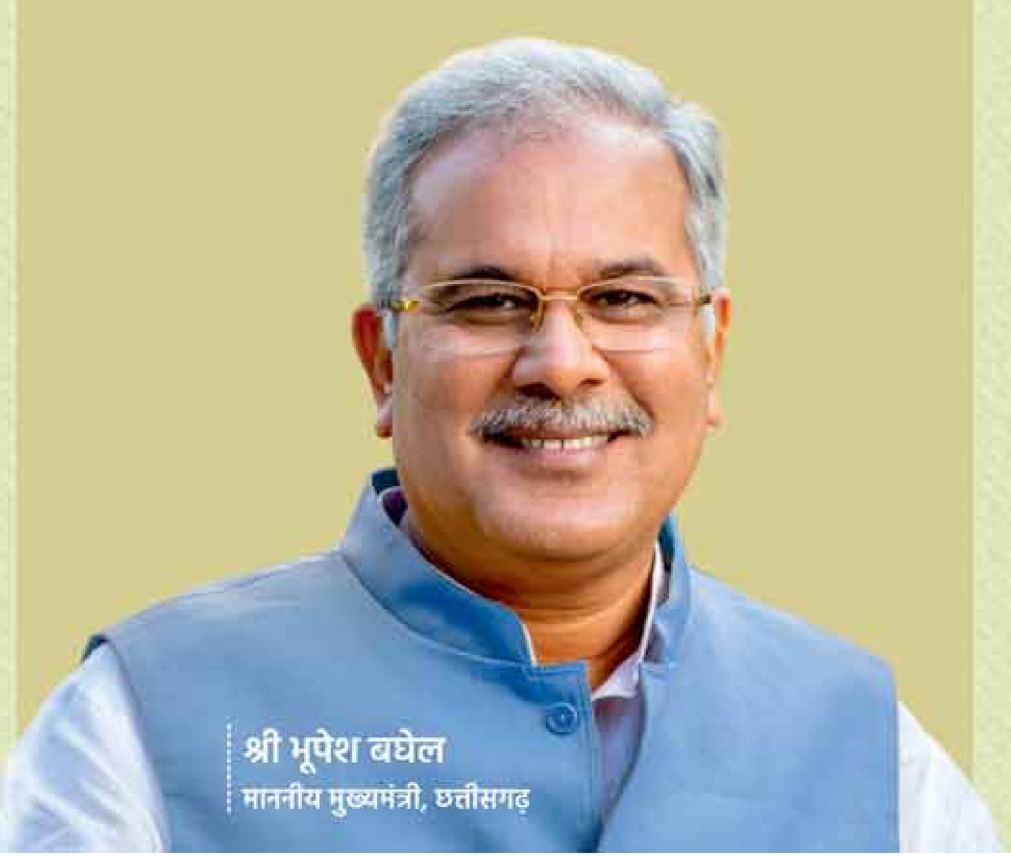

श्री भूपेश बघेल
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

S-298682

पायनियर
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, 16 सितंबर 2021

सार्वजनिक मेलों और प्रदर्शनियों को हरी झंडी

डीडीएमए ने दी इजाजत, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर में रोक लगा दी गई थी

● कक्षा आठ तक के स्कूल अभी बंद रहेंगे

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

राजधानी दिल्ली में मेले और प्रदर्शनियों का आयोजन बृहस्पतिवार हो सकेगा। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बुधवार को आदेश जारी कर सार्वजनिक मेलों और प्रदर्शनियों को हरी झंडी दे दी है।

कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान लगे लॉकडाउन के कारण इनके आयोजनों पर रोक लगा दी गई थी। इस बीच कक्षा 8वीं तक के बच्चों को स्कूल जाने के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। डीडीएमए के मुताबिक आठवीं कक्षा तक के स्कूलों के नहीं खुलने के समय को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही कोरोना महामारी के चलते अन्य कई प्रतिबंधित गतिविधियों के समय को भी आगे बढ़ाया गया है।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आदेश में कहा गया कि मौजूदा समय में कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति का आंकलन किया है। जिसमें पाया गया है कि नए मामले लगातार कम हो रहे हैं। संक्रमण दर भी घट रहा है। कुल मिलाकर स्थिति सुधरी है लेकिन अब भी कोरोना संबंधित नियमों में लापरवाही बरतने पर हालात बिगड़ सकते हैं। लिहाजा सशर्त मंजूरी वाली और प्रतिबंधित गतिविधियों के समय को अब बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दिया गया। बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर प्रदर्शनी को की अनुमति दी गई है।

सरकार ने ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल में 50 फीसदी क्षमता के साथ कार्यक्रम अयोजित करने की भी अनुमति दे दी है। प्राधिकरण ने कहा कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया का सभी हितधारकों द्वारा सख्ती से पालन करने पर ही प्रदर्शनियों और मेलों की अनुमति दी जाएगी।

इसके साथ ही 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं 50 फीसदी क्षमता के साथ चलती रहेगी। रेस्तरां और बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खुल सकेंगे। सिनेमा हॉल और ऑडिटोरियम बैठने की आधी क्षमता के साथ लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। मेट्रो में सभी सीटों पर बैठ सकेंगे। लेकिन किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी। दिल्ली परिवहन निगम की बसों में भी सभी सीटों पर बैठकर यात्रा करने की अनुमति होगी।

राम लीला की अनुमति नहीं

डीडीएमए ने इस बार भी रामलीला जैसे धार्मिक आयोजनों की अनुमति नहीं दी है। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और फेस्टिवल संबंधी भीड़ भाड़ वाले आयोजन करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध जारी रखा गया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के राज्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य सचिव विजय कुमार देव की ओर से बुधवार को नया आदेश जारी किया गया है।

डीयू छात्रों के लिए खुले कॉलेजों के दरवाजे

टीचर से सवाल पूछती छात्रा

कक्षा में जाती छात्राएं

माता सुंदरी कॉलेज में थर्मल स्क्रीनिंग कराली स्टूडेंट: फोटो रंजन डिमरी

नई दिल्ली। डीयू में कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बाद अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए कॉलेजों और तमाम डिपार्टमेंट के दरवाजे बुधवार से खुल गए। दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजों ने छात्रों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही प्रैक्टिकल क्लासेज में आने की मंजूरी दी है। कॉलेजों ने एसओपी के अनुसार इसकी तैयारी भी की है। कॉलेजों ने अपने यहां सेनिटाइज मशीनों के साथ मास्क की व्यवस्था भी की है। इसके अलावा पहले दिन सामाजिक दूरी के पालन को लेकर भी काफी जागरूकता भी देखने को मिली। पहले दिन कॉलेजों और विभागों में छात्रों की संख्या काफी कम देखने को मिली। रामजस कॉलेज के प्राचार्य डॉ. मनोज खन्ना के मुताबिक, सभी छात्रों से कॉलेज आने के लिए सहमति ली गई है। पहले दिन काफी कम संख्या में स्टूडेंट्स कॉलेज पहुंचे। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में छात्रों की संख्या बढ़ेगी। कॉलेज आने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए वैक्सीन की एक डोज लगा होना अनिवार्य है जबकि हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए वैक्सीन की दोनों खुराक जरूरी हैं।

कोविड-19 महामारी से राजस्व वसूली में आई भारी कमी

● अब तक 23 फीसदी कम राजस्व मिला : सिसोदिया

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

मनीष सिसोदिया

कोविड-19 महामारी में दिल्ली सरकार के राजस्व वसूली में भारी कमी आई है। वित्त वर्ष 2020-21 में अनुमानित राजस्व से 41 फीसदी कम राजस्व की प्राप्ति हुई। वर्ष 2021-22 में भी अबतक अनुमानित राजस्व से 23 फीसदी कम राजस्व मिला।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि यह चिंता की बात है। इसकी वजह से कर्मचारियों के वेतन और कोरोना संबंधी खर्चों के अलावा सरकार ने बाकि खर्चों पर पांबंदी लगा दी है। साथ ही बाकि राज्य सरकारों के साथ दिल्ली को भी अगले साल से जीएसटी कंपनसेशन मिलना बंद हो जाएगा, जिससे राजस्व में 8000 करोड़ की कमी आएगी। वर्तमान वित्त वर्ष में जीएसटी कलेक्शन में 23 प्रतिशत, वैट वसूली 25 प्रतिशत, आबकारी वसूली 30 फीसदी, स्टाम्प से 16 प्रतिशत और मोटर व्हीकल टैक्स में 19 फीसदी की कमी दर्ज की गई है। इस बीच नई आबकारी नीति से थोड़ी राहत मिलेगी। नवंबर 2021 से हर साल लगभग 3500 करोड़ रुपयों के अतिरिक्त राजस्व की होगी प्राप्ति साथ ही शराब माफियाओं पर भी शिकंजा कसेगा।

सिसोदिया ने दिल्ली सरकार के खजाने की जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियों के बंद होने से राजस्व प्राप्ति में भरी कमी आई है। दिल्ली के प्रति केंद्र सरकार की उदासीन नीति के कारण केंद्रीय करों में केवल 325 करोड़ रूपये मिलते है जबकि केंद्रीय करों में दिल्ली सरकार की भागीदारी 1 लाख 40 हजार करोड़ रुपयों की होती है। इन वजहों से आने वाले समय में काफी मुश्किलें होंगी क्योंकि केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में उचित हिस्सा नहीं मिलता है। राजस्व प्राप्ति में आई इन गिरावटों के बावजूद उनकी सरकार द्वारा शुरू की गई नई आबकारी नीति से कुछ सफलता मिली है जिससे आने वाले समय में सरकार का खजाना बढ़ेगा। गत 15 अप्रैल 2021 को नई आबकारी नीति को मंजूरी मिली। इसका मकसद आबकारी करों में होने वाली चोरी को रोकना था। इस नीति के तहत सबसे बड़ा बदलाव एक्साइज ड्यूटी और वैट को लाइसेंस फीस में तब्दील कर देना था, क्योंकि यही सबसे ज्यादा कर चोरी होती थी।

महापौर ने नजफगढ़ जोन के सागरपुर का किया दौरा

नई दिल्ली। महापौर मुकेश सुर्यान ने बुधवार को अतिरिक्त आयुक्त रणधीर सहाय के साथ नजफगढ़ जोन के सागरपुर (ईस्ट) का दौरा किया।

महापौर ने उपायुक्त भूपेश चौधरी, नजफगढ़ जोन के अध्यक्ष सत्यपाल मलिक, स्थानीय पार्षद पूनम जिंदल की उपस्थिति में क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में जाकर निगम द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। महापौर ने सागरपुर ईस्ट के विद्यालयों का भी निरीक्षण किया और प्रधानाचार्य को निर्देश दिये कि विद्यालयों में ऑनलाइन क्लास सुचारू रूप से चलाई जा रही है। उन्होंनें कहा कि इस समय विद्यालय बंद है लेकिन उनके रख-रखाव का कार्य जारी रहना चाहिए।

सरकार के सुस्त रवैए से सौ बेड के अस्पताल का निर्माण अधूरा

● कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब देने को कहा

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

उच्च न्यायालय ने कहा कि यह जनता का दुर्भाग्य है कि वन विभाग की मंजूरी देने में दिल्ली सरकार के सुस्त रवैए के साथ शहर के नजफगढ़ इलाके में 100 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने दिल्ली सरकार को याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया और कहा कि कानून के तहत केंद्र द्वारा मांगी गई मंजूरीअनुमति कम से कम समय में दी जाए। उसने मामले की आगे की सुनवाई के लिए आठ नवंबर की तारीख तय की। वकील राजेश कौशिक ने एक जनहित याचिका दायर करके दक्षिण पश्चिम दिल्ली के नजफगढ़ में ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र स्थल पर अस्पताल बनाने का काम पूरा करने के लिए दोनों सरकारों को निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया है।

पीठ ने कहा, निर्माण काम पूरा करने के लिए कुछ कीजिए। आप इनकार भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठिए। आप कानून के अनुसार फैसला कीजिए। उसने कहा, यह जनता का दुर्भाग्य है कि दिल्ली सरकार के सुस्त रवैए के कारण 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है।

दिल्ली-एनसीआर में फिर शुरू होगा बारिश का दौर

● आईएमडी ने जारी किया ओरेंज अलर्ट

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

फाइल फोटो

मानसून दिल्ली एनसीआर समेत देशभर में विदाई की ओर बढ़ रहा लेकिन बारिश का सिलसिला थमा नहीं है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, दिल्ली एनसीआर में पूरे सितंबर महीने में मानसून की बारिश होगी, कभी हल्की तो कभी मध्यम स्तर की। इस दौरान कभी-कभार तेज बारिश का अनुमान भी मौसम विभाग की ओर से जताया गया है।

इसी कड़ी में मौसम विभाग ने बुधवार के साथ-साथ बृहस्पतिवार को भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक, बुधवार मी मध्यम रात्रि से बारिश का दौर शुरू होगा। बृहस्पतिवार को तेज बारिश के चलते आरेंज अलर्ट जारी किया है। एक सप्ताह के दौरान यह तीसरा मौका है जब मौसम विभाग ने आरेंज अलर्ट जारी किया है। गुरुवार को बारिश की गतिविधि सबसे अधिक होगी। इस दिन 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेंगी और तेज बारिश का भी अनुमान है। ऑरेंज अलर्ट अत्यधिक खराब मौसम के लिए चेतावनी के तौर पर जारी किया जाता है जिसमें सड़कों पर जलभराव होने, नालियों के भरने और बिजली आपूर्ति बाधित होने की आशंका होती है।

बुधवार को न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन में तेज हवाएं चलने और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। दिल्ली में अभी तक मानसून के इस मौसम में।,146.4 मिलीमीटर तक बारिश हो चुकी है जो 46 वर्षों में सबसे अधिक है तथा पिछले साल की बारिश की तुलना में लगभग दोगुनी है। वेधशाला ने बताया कि 1975 में मानसून के मौसम में।,150 मिमी बारिश हुई थी। आमतौर पर मानसून के दौरान 653.6 मिमी बारिश दर्ज की जाती है। मानसून शुरू होने पर एक जून से 14 सितंबर के बीच शहर में सामान्यत: 607.7 मिमी बारिश होती है। मानसून से मंगलवार तक इस महीने दिल्ली में 390 मिमी बारिश हुई जो 77 वर्षों में सितंबर में हुई सबसे अधिक वर्षा है।

गैरतपुरबॉस से सटी अरावली में भी फार्म हाउस वन विभाग के निशाने पर

पायनियर समाचार सेवा। सोहना।

वन विभाग गैरतपुरबॉस से लगती अरावली पहाड़ी में बने करीब डेढ़ दर्जन फार्म हाउसों को अवैध निर्माण किए जाने का नोटिस देगा। वन विभाग ने सर्वे प्रक्रिया पूरी करने के बाद नोटिस देने की तैयारी कर ली है।

वन विभाग ने रायसीना और भोंडसी के बाद गैरतपुरबॉस से सटी अरावली पहाड़ी में बने फार्म हाउसों का सर्वे कार्य शुरू किया है। गैरतपुरबॉस का कुछ हिस्सा अरावली अंसल के बाहर आता है। जिसमें 15 से 20 फार्म हाउसों को चिह्नित किया है। वन विभाग कर्मचारियों की टीम सोहना रेंज क्षेत्र में पीएलपीए की जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण की खोज कर रही है। ताकि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को जल्द से जल्द पूरा करने के बाद रिपोर्ट पेश की जा सके।

1970 से पहले बने मकानों पर कानूनी सलाह : वन विभाग सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सोहना शहरी क्षेत्र में 1970 से पहले पीएलपीए की जमीन पर हो रहे निर्माण भवनों को लेकर कानूनी सलाह लेगा। जिससे वन विभाग पर उठ रही आम लोगों की अंगुलियों का जबाव दिया जा सके।

चार याचिकाकर्ता पहुंचे अदालत

वन विभाग के एक खिलाफ निचली अदालत ने सोमवार को याचिका दायरकर्ता को स्टे दे दी है। अब तक शहर के दो लोगों को अदालत से याचिका पर स्टे मिला है। अब तक वन विभाग द्वारा दिए गए अवैध निर्माणों के खिलाफ नोटिसों के खिलाफ कुल चार लोगों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। जिसमें सबसे पहले रायसीना से लगती अरावली पहाड़ी में बने फार्म हाउस मालिकों ने याचिका दायर की थी।

संक्षिप्त समाचार

संपत्ति कर में छूट की अवधि 3 सितंबर तक बढ़ाई

नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने एकमुश्त संपत्ति कर भुगतान पर मिल रही 15 प्रतिशत छूट की अवधि को अगले 15 दिनों के लिए यानी 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया है। अग्रवाल ने कहा है कि कोरोना महामारी के चलते लोगों की समस्या को देखते हुए यूपिक आधारित भुगतान प्रणाली की प्रक्रिया के चलते यह फैसला लिया गया है। महापौर ने बताया कि नए यूपिक के आवेदन के साथ 15 प्रतिशत छूट की अवधि को भी अगले 10 दिनों यानी 25 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया गया है। बिना छूट के नए यूपिक आवेदन 01 अक्टूबर 2021 से स्वीकार किए जाएंगे।

कांति नगर वार्ड का मेयर ने किया निरीक्षण

नई दिल्ली। पूर्वी दिल्ली के महापौर श्याम सुन्दर अग्रवाल ने बुधवार को वार्ड संख्या-26 कांति नगर क्षेत्र का दौरा किया। महापौर के साथ स्थानीय पार्षद कंचन महेश्वरी और वरिष्ठ निगम अधिकारी और डीडीए के अधिकारी भी मौजूद थे। मेयर ने वेस्ट आजाद नगर में नवनिर्मित विद्यालय का दौरा किया और ढांचागत गुणवत्ता का जायजा लिया। महापौर ने कहा कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के प्रति प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि निगम अपने सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके नये प्राथमिक विद्यालय का निर्माण कराया गया है जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों का शिक्षा मिल सके। अग्रवाल ने बताया कि इस नवनिर्मित विद्यालय में जमीन पर लूडो बनाई गई है।

नेहरा खाप ट्रस्ट का सेमिनार 21 सितंबर को रोहतक में

गुरुग्राम। नेहरा खाप ट्रस्ट द्वारा जाट भवन रोहतक में आगामी 21 सितम्बर 2021 को एक सेमिनार का आयोजन किया जायेगा। सेमिनार का विषय है, इंट्री इन डिफेंस फोर्सेज यानी युवा वर्ग भारतीय सशस्त्र सेनाओं में भर्ती कैसे हो सकते हैं। इस सेमिनार में भारतीय सशस्त्र सेनाओं के कर्नल रैंक समेत बड़े-बड़े अधिकारी युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करेंगे। इस कायज्क्रम की अध्यक्षता हरियाणा के पूर्व केबिनेट मंत्री जगदीश नेहरा करेंगे। यह जानकारी नेहरा खाप ट्रस्ट के सहसचिव बलवीर सिंह नेहरा ने दी। उन्होंने बताया कि नेहरा खाप ट्रस्ट एक चेरिटेबल सामाजिक संस्था है जिसमें नेहरा समाज के अनेक गणमान्य व्यक्ति जुड़े हैं। ट्रस्ट समय-समय पर इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करता रहता है। यह प्रोग्राम भारत की तीनों सेनाओं को समर्पित है और युवाओं को सशस्त्र सुरक्षा बलों से जुड़ने का आह्वान किया जायेगा। बलवीर सिंह नेहरा के अनुसार यह प्रोग्राम पूरी तरह से गैर राजनीतिक होगा और सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित किया जाएगा।

शहर में गुंडागर्दी नहीं होने दी जाएगी : विधायक

सोहना। सोहना विधायक संजय सिंह ने कहा कि शहर में किसी प्रकार की बदमाशी नहीं होने दी जाएगी। विवादों का आपसी सहमति और सामाजिक मर्यादाओं के निपटाया जाएगा। शहर के वार्ड-19 के दो गुटों के बीच उपजे विवाद को लेकर गठित की गई 31 सदस्यों की कमेटी बुधवार को सोहना विधायक संजय सिंह से मिली। कमेटी सदस्यों ने विधायक को विवाद की जानकारी दी। विधायक संजय से शहर में बाउंसरों को लेकर आने वाले गुट की शिकायत की। शहरवासियों की गठित कमेटी को विधायक संजय सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि चाहे नेता हो या प्रॉपर्टी डीलर।

अग्रवाल सभा के प्रधान पद को लेकर नौ सौ लोगों ने की सदस्यता ग्रहण

होडल। श्रीवैश्य अग्रवाल सभा के प्रधान पद को लेकर अग्रवाल भवन में चल रहे सदस्यता अभियान में अब तक अग्रवाल समाज के 18वर्ष से ज्यादा महिला-परूषों न सदस्यता ग्रहण कर ली है। सदस्यता अभियान के प्रति अग्रवाल समाज के लोगों में उत्साह बना हुआ है। अग्रवाल समाज द्वारा बनाई गई चुनाव कमेटी ने प्रधान पद के चुनाव को लेकर कुछ नियम भी लागू किए है।

चुनाव अधिकारी डा. जेके मित्तल व राजकपूर बंसल ने जानकारी देते हुए बताया कि श्रीवैश्य अग्रवाल सभा के प्रधान पद को लेकर चल सदस्यता अभियान में अब तक नौ सौ महिला-पुरूष व युवाओं ने सदस्यता ग्रहण की है। सभा का यह सदस्यता अभियान 19 सितंबर तक चलेगा और 20 व 21 सितंबर को प्रधान पद के लिए नामांकन भरे जाएंगे। 22 सितंबर को फार्म वापिस व चुनाव चिन्ह वितरित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि को अग्रवाल सभा का मतों के द्वारा चुनाव कराया जाएगा। अग्रवाल समाज की ओर से चुनाव को लेकर चुनाव अधिकारी राजकपूर बंसल, हृदय राम गर्ग, कृष्ण चंद सिंगला गए है।

हरियाणा में भी अब नर्सिंग ऑफिसर कहलाएंगीं स्टाफ नर्स

गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिया यह तोहफा

प्रदेश में स्टाफ नर्सों ने मनाया इस जीत का जश्न

संजय कुमार मेहरा। गुरुग्राम

हरियाणा में अब स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर कहलाएंगीं। लंबे समय से स्टाफ नर्सों की यह मांग थी, जिसे अब जाकर सरकार ने पूरा किया है। इस जीत पर प्रदेशभर में स्टाफ नर्सों ने जश्न मनाया। व्यक्तिगत रूप से भी और सोशल मीडिया पर भी नर्सिंग ऑफिसर एक-दूसरे को बधाई देने में लगीं रही।

नर्सों की मुख्यत: तीन श्रेणियां स्टाफ नर्स, नर्सिंग सिस्टर और मैटर्न हैं। इन तीनों श्रेणियों का ही अब नाम बदल गया है। स्टाफ नर्स नर्सिंग ऑफिसर कहलाएंगी। नर्सिंग सिस्टर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और मैटर्न स्टाफ चीफ नर्सिंग ऑफिसर कहलाएंगी। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा इस मांग को पूरा किये जाने की घोषणा के साथ ही वित्त विभाग की ओर से इस बाबत पत्र भी जारी कर दिया गया।

हमने लड़ाई जारी रखी और जीत हुई : कमलेश सिवाच

हरियाणा में नर्सों को नर्सिंग ऑफिसर का दर्ज मिलने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नर्सिंग एसोसिएशन गुरुग्राम की प्रेजीडेंट कमलेश सिवाच ने कहा कि इस दर्ज के लिए पिछले चार साल से लड़ाई लड़ रहे थे। सरकार से आश्वासन ही मिलते थे। बीच में दो साल कोरोना की वजह से काम प्रभावित रहे। अब फिर से हमने सक्रियता बढ़ाई तो सरकार को हमारी मांग माननी पड़ी। हमारी जीत हुई और अब हरियाणा में स्टाफ नर्सों को नर्सिंग ऑफिसर का दर्जा मिल गया है।

लंबे समय का था सपना, पूरा हुआ : रितु मलिक

नर्सिंग ऑफिसर रितु मलिक कहतीं हैं कि यह बहुत ही सम्मान का दिन है। इस दिन की सभी नर्सिंग स्टाफ को बेसब्री से इंतजार था। उनका यह एक तरह से सपना पूरा हुआ है। उन्हें खुशी है कि देर से ही सही, सरकार ने उनकी मांगों को पूरा करके नर्सिंग ऑफिसर का तोहफा दिया है। उन्होंने कहा कि घर-परिवार व कार्यस्थल के बीच सामंजस्य बिठाकर जिस तरह से विपरीत परिस्थितियों में नर्सिंग ऑफिसर काम करती हैं, वह बहुत ही चुनौती भरा होता है। मरीजों का स्वास्थ्य सही करने को नर्सिंग ऑफिसर जिस जुनून के साथ तरह से काम करती हैं, वह किसी कलम से नहीं लिया जा सकता। उन्होंने नर्सिंग एसोसिएशन गुड़गांव की प्रेजीडेंट कमलेश सिवाच व अन्य पदाधिकारियों द्वारा इस काम के लिए किए गए संघर्ष का फल बताया।

परिवार की तरह रखते हैं मरीजों का ख्याल: पूनम सहराय

अपना नया टाइटल मिलने पर जश्न मना रहीं नर्सिंग ऑफिसर पूनम सहराय बोलीं कि लंबे समय से उनकी यह मांग थी। जिसे सरकार ने अब पूरा किया है। इसके लिए नर्सिंग एसोसिएशन गुड़गांव की प्रेजीडेंट कमलेश सिवाच समेत सभी पदाधिकारियों को पूरा श्रेय जाता है। सभी ने कड़ी मेहनत की। पूनम सहराय ने कहा कि दिल्ली के एम्स समेत अन्य कई राज्यों में नर्सिंग स्टाफ को नर्सिंग ऑफिसर का दर्जा पहले से ही मिला हुआ है। चिकित्सा का सबसे अधिक जिम्मा नर्सिंग ऑफिसर कंधों पर होता है। अपने परिवार की तरह वे मरीजों का ख्याल रखती हैं। उनके लिए ना कोई छोटा होता है और ना कोई बड़ा। अस्पताल में उनके लिए हर मरीज के लिए सकारात्मकता रहती है। नर्सिंग पेशा अपने आप में ही एक समर्पण और त्याग का है।

निष्पक्षता से करते हैं काम: जपिन्द्र

नर्सिंग ऑफिसर जपिन्द्र का कहना है कि नया नाम मिलना बहुत ही खुशी की बात है। इस नाम के लिए प्रयास करने वाली नर्सिंग एसोसिएशन का भी धन्यवाद। एसोसिएशन ने लगातार इस पर काम किया। सरकार से बार-बार इस बारे में आग्रह किया। आखिर में नर्सिंग ऑफिसर का नाम हमें मिला है। उन्होंने कहा कि नर्सिंग ऑफिसर कभी भी अपने काम में कोई कमी नहीं छोड़तीं। ड्यूटी पर निष्पक्षता से काम करते हुए वे मरीजों को उपचार देती हैं। बहुत बार अपने परिवार की समस्याओं को नजरअंदाज करके ड्यूटी निभानी पड़ती है। ऐसी जुझारू स्टाफ नर्सों को सरकार ने नर्सिंग ऑफिसर का दर्जा देकर सम्मान बढ़ाया है।

पायनियर
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, 16 सितंबर, 2021

एक्सीडेंट : तीन साल में हुए 1481 हादसों में 584 जान गईं

कविता। फरीदाबाद

वाहन चालकों की लापरवाही और खस्ता हाल सड़कें दुर्घटनाओं का बड़ा कारण हैं। सड़कों को दुरूस्त करने के दावों के बाद भी हादसों का न रुक पाना बड़ा सवाल है। इन हादसों में सैकड़ों लोग अपनी जान गवां रहे हैं। पिछले तीन वर्षों में 1481 सड़क हादसों में अगस्त 2021 तक 584 लोग अपनी जान गवां चुके हैं और 1323 लोग घायल हो चुके हैं।

हाइवे पर ही नहीं शहर की अंदरूनी सड़कों पर भी हादसे हो रहे हैं। जगह-जगह दिशासूचक पट्ट और अलर्ट करने वाले बोर्ड लगाने के बावजूद पिछले साल तीन सालों में अंदरूनी सड़कों पर हादसे बढ़ गए हैं। वर्ष 2019 में जिले में 689 सड़क हादसों में 264 मौत और 635 लोग

नेशनल हाईवे के बजाय अन्य सड़कों पर अधिक हुए हादसे

घायल हुए। वहीं वर्ष 2020 में जिले में 489 सड़क हादसों में 195 मौत और 421 लोग घायल हुए। जबकि वर्ष 2021 में अगस्त माह तक 303 सड़क दुर्घटनाओं में 125 लोगों की मौत और 267 लोग घायल हुए थे। इन आंकड़ों से ही पता चल रहा है कि इस वर्ष के आंकड़े वर्ष 2020 के आंकड़ों को छू रहे हैं।

हाइवे पर कम हादसे

नेशनल हाइवे पर पिछले तीन वर्षों में सड़क हादसे कम हो गए हैं। लेकिन वर्ष 2021 में सामान्य सड़क हादसों में तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही है। आंकड़ों के मुताबिक हाइवे पर जहां

तीन वर्षों में 398 सड़क हादसों में 184 मौत और 334 लोग घायल हुए।

वहीं अंदुरूनी सड़कों पर 1077 एक्सीडेंट में 383 मौत और 998 लोग घायल हो गए। इसमें हाइवे पर वर्ष 2019 में 205 हादसों में 94 मौत और 172 घायल हुए हैं। अन्य सड़कों पर 483 हादसों में मौत और 484 लोग घायल हुए। वर्ष 2020 में हाइवे पर 122 हादसों में 60 मौत और 98 लोग घायल हुए। अन्य सड़कों पर 362 हादसों में 134 मौत और 311 लोग घायल हो गए। 2021 में नेशनल हाइवे पर 71 हादसों में 30 मौत और 64 घायल हुए। अन्य सड़कों पर 232 हादसों में 95 मौत और 203 लोग घायल हुए हैं।

हादसों में कमी लाने का प्रयास

रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष एसके शर्मा ने कहा कि लोग यातायात नियमों का पालन करें। हालांकि एक बैठक में सड़क हादसों के प्वॉइंट उजागर करके उनमें कमी लाने के लिए प्रयास किया जा रहे हैं, लेकिन सड़कों की खस्ता हालत के कारण थोड़ी परेशानी आ सकती है। आने वाले समय में सड़क हादसों में कमी के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।

जेसी बोस का स्थापना दिवस आज

फरीदाबाद। जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, वाईएमसीए आज अपना स्थापना दिवस मनाएगा। विश्वविद्यालय द्वारा 25 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने पर सम्मानित कर्मचारियों और उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में हरियाणा केंद्रीय विवि महेंद्रगढ़ के कुलपति प्रो. टंकेश्वर कुमार मुख्य अतिथि होंगे। कुलपति प्रो. दिनेश कुमार अध्यक्षता करेंगे। हरियाणा केंद्रीय विवि के साथ शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जेसी बोस विवि एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर करेगा। जेसी विश्वविद्यालय जोकि वर्ष 1969 में एक इंडो-जर्मन डिप्लोमा संस्थान के रूप में अस्तित्व में आया था, को पहले वाईएमसीए इंस्टीट्यूट संस्थान के रूप में जाना जाता था।

संक्षिप्त समाचार

इनर व्हील क्लब ने बच्चों को दिए बैग और यूनिफार्म

फरीदाबाद। सोशल मीडिया के माध्यम से इनरव्हील क्लब की अध्यक्ष मंजू बंसल को जब पता चला मिशन जागृति की पाठशाला के बच्चों को यूनिफॉर्म और बैग की जरूरत है तो उन्होंने तुरंत अपने साथियों से बात की और पहुंच गई पाठशाला में। इनर व्हील क्लब द्वारा फरीदाबाद शहर की अग्रणी सामाजिक संस्था मिशन जागृति द्वारा एनआईटी दशहरा ग्राउंड के पीछे राहुल कॉलोनी में चलाई जा रही एक पाठशाला में 100 बच्चों को यूनिफॉर्म और बैग बांटे। मंजू बंसल ने कहा कि हम अधिकतर मिशन जागृति के कार्यों को देखते रहते हैं उनका यह प्रयास बहुत ही प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि समाज में बच्चों को पढ़ाने से बेहतर कोई काम नहीं हो सकता वह भी ऐसी स्लम एरिया में खुद से जाकर। मिशन जागृति पाठशाला की संयोजक संतोष अरोड़ा, लता सिंगला, अरुणा चौधरी, सुष्मिता भौमिक, रेनू शर्मा, गीता सिंह ने क्लब की सभी सदस्यों को माला और चुन्नी पहना कर स्वागत किया। इनर व्हील क्लब की तरफ से शेलली गोयल, मनीता सिंघला, अंजु महाना, रजनी, संदीपिका उपस्थित रहे। रिंकू बनर्जी, दीपा, मोनिका, अनुवा आर्य, ज्योति कपूर, राजेश भूटिया, अशोक भटेजा, कपिल कपूर, महेश आर्या, दिनेश राघव, संजय पाल, उपस्थित रहे। संस्थापक प्रवेश मलिक ने सभी का शुक्रिया किया।

करोड़ों की लागत से तीन सड़कों का निर्माण करेगा एफएमडीए

फरीदाबाद। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा 4487.45 लाख रुपये की लागत से फरीदाबाद के 5930 मीटर लंबे तीन मार्गों का निर्माण किया जाएगा। फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधीर राजपाल ने इन तीन मुख्य मार्गों के निर्माण की प्रशासनिक अनुमति प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि यातायात की सुचारु व्यवस्था के लिए इन सड़कों का निर्माण फरीदाबाद नगर निगम की बजाए महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। उन्होंने इन सड़कों के निर्माण की प्रशासनिक अनुमति प्रदान की। सेक्टर 11/12, 10/12, 9/12 के बीच की मुख्य सड़क, जोकि धर्मा ढाबा से लेकर इंडियन आयल कारपोरेशन तक 1575 मीटर है। चार लेन सड़क की अनुमानित लागत 1055.91 लाख रुपये है। सुधीर राजपाल ने बताया कि इन सड़कों का कंक्रीट से पुनर्निर्माण किया जाएगा। सड़कों के दोनों तरफ सात सात मीटर चौड़ा मुख्य मार्ग होगा और दोनों तरफ दो मीटर का साइकिल ट्रैक और दो मीटर का पैदल पथ भी बनाया जाएगा। दूसरी मुख्य सड़क हार्डवेयर चौक से गोंछी ड्रेन और गोंछी ड्रेन से पेट्रोल पंप तक बनाई जाएगी जिसकी अनुमानित लागत 1209.31 लाख रुपये है। तीसरी मुख्य सड़क व्यापार मंडल से सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल से ईएसआई चौक, ईएसआई चौक से चिमनी बाई चौक, चिमनी बाई चौक से मीट मार्केट नेशनल हाईवे 5 फरीदाबाद तक बनाई जाएगी। इसकी अनुमानित लागत 2222.23 लाखों रुपये है। 3030 मीटर लंबी, 4 लेन सड़क बनाई जाएगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट फरीदाबाद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी गरिमा मित्तल ने बताया कि सुगम व्यवस्था एवं आवागमन के लिए स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स, सोलर लाइट्स और लैंडस्कैपिंग फरीदाबाद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत की जाएगी।

हिंसा को रोकने की मांग को लेकर डीसी दफ्तर पर प्रदर्शन

फरीदाबाद। सीपीआईएम और सीपीआई के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बुधवार को त्रिपुरा में सत्तारूढ़ दल भाजपा के द्वारा माकपा और वाम मोर्चे के खिलाफ की जा रही बर्बर हिंसा को रोकने की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन उपायुक्त कार्यालय के अधीक्षक कुंदन लाल को सौंपा। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व सीपीएम के जिला सचिव शिवप्रसाद और सीपीआई के जिला सचिव बेचू गिरी ने संयुक्त रूप से किया। संचालन सीपीएम के जिला कमेटी सदस्य लाल बाबू शर्मा कर रहे थे। यह जानकारी सीपीएम के जिला कमेटी सदस्य वीरेंद्र सिंह डंगवाल ने एक बयान में दी। विरोध कार्रवाई को सीपीआई के नेता कामरेड बैजू सिंह, सीपीएम नेता निरंतर पाराशर, विजय झा, कामेश्वर ठाकुर आदि ने भी संबोधित किया।

भाजपा सरकार जनआकांक्षाओं पर हुई पूरी तरह से फेल

फरीदाबाद। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 74वें जन्मदिवस के मौके पर बुधवार को लखन कुमार सिंगला अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ दिल्ली स्थित उनके निवास पर जाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मुंह मीठा कराया और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और उनकी दीर्घायु की कामना की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रदेश की मनोहर सरकार सात साल में जनआकांक्षाओं पर पूरी तरह से फेल साबित हुई है। पत्रकारों द्वारा हुड्डा से भाजपा हाईकामन द्वारा कई राज्यों में बदले जा रहे मुख्यमंत्रियों के पूछे प्रश्न पर उन्होंने कहा कि यह भाजपा का अंदरूनी मामला है, लेकिन देखा गया है कि जिस राज्य में जनता मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली से खुश नहीं है। उसी राज्य में यह बदलाव किए जा रहे हैं और जहां तक रही हरियाणा की बात तो यहां की जनता भी मौजूदा मुख्यमंत्री की कारगुजारियों से पूरी तरह से परेशान है। लखन सिंगला ने हुड्डा को विश्वास दिलाते हुए कहा कि फरीदाबाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता भाजपा सरकार की नाकामियों को जनता के समक्ष उजागर करके जनविरोधी सरकार का असली चेहरा जनता के सामने लाएंगे ताकि लोगों को इस सरकार से छुटकारा दिलाया जा सके। सिंगला के साथ रेनू चौहान, पूर्व पार्षद अनिल शर्मा, रोहित सिंगला, युवा कांग्रेस अध्यक्ष नितिन सिंगला, कर्मवीर खटाना, महिला जिलाध्यक्ष खुशबू खान, राजू धारीवाल, लाला शर्मा, नरेंद्र ठाकुर, अमित बंसल, चंद्रपाल, दीपक रावत, उस्मान ठेकेदार हाजी इरफान आदि कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे।

पुलिस रिमांड में कुख्यात गैंगस्टर काला जेठेड़ी ने खोले कई राज

हरियाणा सहित चार राज्यों में हत्या डकैती स्नेचिंग आर्म्स एक्ट सहित 35 मुकदमे दर्ज

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

क्राइम ब्रांच सेक्टर 48 द्वारा ट्रांजिट रिमांड पर लिए गए कुख्यात काला जठेड़ी ने कई राज उजागर किए हैं। आरोपी को आठ सितंबर को अदालत में पेश कर सात दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया था। आरोपी के खिलाफ हरियाणा सहित राजस्थान, पंजाब, दिल्ली में हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती, स्नेचिंग और अवैध हथियार सहित करीब 35 मुकदमे दर्ज हैं। जिसमें छह मुकदमे फरीदाबाद के शामिल हैं।

एक फरवरी 2020 को गुरुग्राम पुलिस द्वारा मोस्ट वांटेड इनामी बदमाश संदीप उर्फ काला जठेड़ी को फरीदाबाद कोर्ट से गुरुग्राम ले जाया जा रहा था। रास्ते में गुरुग्राम फरीदाबाद रोड पर हनुमान मंदिर के पास आरोपी संदीप के साथियों ने मिलकर कैदी वैन पर फायरिंग करते हुये संदीप को छुड़ाकर ले गए थे। जिसमें एक पुलिसकर्मी को गोली भी लगी थी। मामले में क्राइम ब्रांच की टीम ने संदीप उर्फ काला जेठडी को पुलिस से छुड़ाने में शामिल आरोपी कपिल उर्फ निन्नी, नरेश उर्फ सेठी, धन सिंह, जोगिंदर, आशु, राजेश, प्रदीप उर्फ भोला, विकास उर्फ मिता उर्फ पहलवान, अंशुल, अरुण, मनजीत, ओम प्रकाश, कप्तान और रवि उर्फ भोला को गिरफ्तार कर लिया है।

गुर्गे करते थे वारदात

पुलिस हिरासत से भागने के पश्चात आरोपी ने कई वारदातों को अपने गुर्गों के माध्यम से अंजाम दिलवाया। जिसमें सोनीपत में हत्या की दो, यमुनानगर और पंजाब के कोटकपूरा की एक-एक वारदात और सिरसा के गांव चौटाला में शराब ठेकेदार की हत्या की एक वारदात शामिल है। जिसमें आरोपी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल था। आरोपी ने कई लोगों को मारने की कोशिश भी की। जिसमें दिल्ली के छावला और नरेला में दो व्यक्तियों के घर पर गोलीबारी की गई। पंजाब के कोटकपूरा में मनप्रीत की हत्या करने की कोशिश की गई। जिसमें मुठभेड़ के दौरान आरोपी का साथी पलवल का रहने वाला कृष्ण मारा गया था।

झपटमारी से मोस्ट वॉटेड बना

दुबई और मलेशिया में बैठकर गैंग ऑपरेट करने वाला जठेड़ी 12वीं पास है। उसने पहले केबल ऑपरेटर का काम शुरू किया। लेकिन जल्द ही जुर्म की दुनिया की तरफ मुड़ गया। साल 2004 में जठेड़ी के खिलाफ झपटमारी का केस दर्ज हुआ था। कुछ साल बाद ही हरियाणा के सांपला और फिर गोहाना में हुई हत्याओं में उसका नाम आ गया।

सात लाख का इनामी

पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि आरोपी सात लाख का इनामी बदमाश है। लंबे समय से जुर्म की दुनिया में सक्रिय काला जठेड़ी का नाम दिल्ली में हुई पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के बाद अचानक से सुर्खियों में आया था। सोनीपत जिले के जठेड़ी गांव के निवासी काला ने पिछले करीब 15-16 साल के दौरान आपराधिक दुनिया में तेजी से कदम बढ़ाया।

नौकरी के नाम पर ठगी करने वाला गिरोह गिरफ्तार

देश के कई राज्यों में 300 से अधिक धोखाधड़ी की वारदातों को दे चुके हैं अंजाम

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक महिला सहित गिरोह के तीन सदस्यों को फरीदाबाद के थाना साइबर अपराध की टीम ने 10 सितंबर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में अभिषेक हिमांशु और आरोही (बदला हुआ नाम) का नाम शामिल है।

आरोपियों को अदालत में पेश कर चार दिन के पुलिस रिमांड पर लिया। quikr.com एक ऐसी वेबसाइट है जो लोगों को नौकरी दिलाने में सहायता करती है। जहां पर नौकरी की तलाश में कोई भी व्यक्ति अपना बायोडाटा उस वेबसाइट पर अपलोड कर सकता है। आरोपियों ने भी इसी वेबसाइट का फायदा उठाकर उन व्यक्तियों की जानकारी एकत्रित करते थे। वर्ष 2020 में लॉकडाउन के पश्चात इन्होंने इस प्रकार की वारदातों को अंजाम देना शुरू किया था। आरोपियों ने दिल्ली के गाजापुरी एरिया में अपना एक कॉल सेंटर खोल रखा था। आरोपी अभिषेक प्रतिदिन 50 लोगों को कॉल कर धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम देता था। महिला आरोपी आरोही इस कंपनी में मैनेजमेंट का कार्य करती थी। वहीं इस गैंग का मुखिया, चौथा साथी कंपनी का मालिक है, जो इन्हें हर आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराता है। नौकरी के लिए आवेदनकर्ताओं की जानकारी प्राप्त करने के बाद आरोपी आवेदनकर्ता से संपर्क करते और उन्हें बड़ी-बड़ी कंपनियों में नौकरी लगवाने के बड़े-बड़े सपने दिखाते। आवेदनकर्ता से रजिस्ट्रेशन के नाम पर 2500 रुपये चार्ज करते और बाद में आरोपी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल करियर सर्विस या डिजिटल करियर सर्विस के नाम से बनाई फर्जी ईमेल आईडी से आवेदनकर्ता को ई-मेल भेजकर रजिस्ट्रेशन फीस, ऑनलाइन इंटरव्यू, अप्वाइंटमेंट लेटर व अन्य सेवाओं के नाम पर अलग-अलग रकम अपने फर्जी बैंक खातों में डलवाते थे। इसी प्रकार से धोखाधड़ी करते हुए आरोपियों ने फरीदाबाद के सेक्टर 58 निवासी संजना से भी 88600 रुपये ऐंठ लिए थे।

टूटी सड़कों को लेकर आप ने सौंपा ज्ञापन

फरीदाबाद। आम आदमी पार्टी ने बुधवार को अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जिला अध्यक्ष धर्मबीर भड़ाना के नेतृत्व में नगर निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और टूटी हुई सड़कों एवं जलभराव की समस्या को लेकर निगमायुक्त को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन के माध्यम से आम आदमी पार्टी ने प्रशासन को अवगत कराया कि किस प्रकार बारिश ने प्रशासन के कार्यों एवं भाजपा सरकार के विकास के दावों की पोल खोलकर रख दी है। निगमायुक्त ने आम आदमी पार्टी द्वारा सौंपे गए ज्ञापन को गंभीरता से लेते हुए जल्द ही शहर को जल निकासी एवं टूटी सड़कों से निजात दिलाने की बात की। आज फरीदाबाद की सभी विधानसभाओं में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और भाजपा को वोट देने के अपने फैसले पर पछता रहे हैं। जिलाध्यक्ष धर्मबीर भड़ाना ने कहा कि आज पूरे फरीदाबाद की स्थिति बद से बदत्तर है। करोड़ों रुपया विकास कार्यों पर खर्च करने के बावजूद शहर के हालात दयनीय हैं। आम आदमी पार्टी सदैव शहर में विकास के मुद्दों और समस्याओं को उठाती रही है। ज्ञापन में बताया गया कि एनआईटी विधानसभा क्षेत्र की प्रमुख सड़कें डबुआ रोड, जवाहर कॉलोनी, 60 फुट रोड, 45 फुट रोड, पर्वतीया कालोनी के अलावा यहां की अधिकतर सड़कों की हालत इन दिनों बद से बदत्तर है, यहां की सड़कें पूरी तरह से टूटी हुई है और उनमें कई-कई फुट पानी भरा हुआ है।

विद्यासागर स्कूल में लगाया गया कोविड वेक्सीनेशन कैंप

फरीदाबाद। विद्यासागर इंटरनेशनल स्कूल, सेक्टर 2 में रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद इंडस्ट्रीयल टाउन के साथ मिलकर मेगा वैक्सीन कैंप का आयोजन किया। लोगों का प्रोत्साहित करने के लिए भाजपा नेता टीपरचंद शर्मा मौजूद थे। कैंप स्कूल के चेयरमैन धर्मपाल यादव, स्कूल डायरेक्टर दीपक यादव व रोटरी क्लब ऑफ इंडस्ट्रीयल टाउन के प्रेजिडेंट अतुल सर्राफ के मार्गदर्शन में संचालित किया। कैम्प में उपस्थित लोगों को सम्बोधत करते हुए टीपरचंद शर्मा ने कहा कि फरीदाबाद की जनता को बिना किसी डर के वैक्सीनेशन कराना चाहिए। स्कूल के डायरेक्टर दीपक यादव ने बताया कि पहली वैक्शीनेशन के बाद दूसरी वैक्शीनेशन 12 से 16 सप्ताह में लगवाने पर इम्युनिटी पावर ओर भी बेहतर कारगर साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में वे और कैंप लगवाने का प्रयास करेंगे ताकि इसका लाभ सीधे तौर पर जनता को मिल सके।

आज 52 सरकारी और 14 निजी शिविरों में लगेगा टीका

मैगा वैक्सीनेशन शिविरों में 50034 लोगों को लगा टीका

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

जिले में बुधवार को मैगा वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें 50034 लोगों को टीका लगाया गया। इस दौरान सरकारी केन्द्रों में 18 प्लस आयुवर्ग में प्रथम डोज 28177 को और दुसरी डोज 3630 को लगाई गई।

वहीं 45 प्लस आयुवर्ग में प्रथम डोज 5477 को और द्वितीय डोज 3470 लोगों ने टीका लगवाया। वहीं 60 प्लस आयुवर्ग में प्रथम डोज 375 को और द्वितीय डोज 843 को लगाई गई। वहीं निजी अस्पतालों में 18 प्लस आयुर्ग में प्रथम डोज 515 को, द्वितीय डोज 774 को लगाई गई। वहीं 45 प्लस आयुवर्ग में प्रथम डोज 75 और द्वितीय डोज 86 को लगाई गई। वहीं 60 प्लस आयुवर्ग में सात को प्रथम डोज और पांच लोगों ने द्वितीय डोज लगाई गई। इस दौरान सरकारी में प्रथम डोज कुल 34629 ने और निजी में 597 लोगों को डोज लगी। वहीं द्वितीय डोज सरकारी में 13943 को और निजी में 865 लोगों को डोज लगाई गई।

जिला वैक्सीनेशन अधिकारी डॉ. मान सिंह ने बताया कि जिले में लगाए जा रहे मैगा वैक्सीनेशन कैम्पों के बारे में एक जूम मिटिंग का आयोजन किया गया। इस बैठक में एनएचएम के डायरेक्टर डॉ. आरएस पूनिया और जिला सिविल सर्जन डॉ. विनय गुप्ता के अलावा अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। डॉ. मान सिंह ने बताया कि जिले में बृहस्पतिवार को 43 सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों के जरिये 52 कैम्प लगेंगे और 14 निजी अस्पतालों में कैम्प लगाये जाऐंगे। वहीं जिले में कोरोना के दो मरीज नए सामने आए है। जिससे जिले फिलहाल 5 एक्टिव केस ही मौजूद है। वहीं जिले में बुधवार को 2445 सैम्पल जांच किए गए। जिसमें फिलहाल सरकारी में 1497 और निजी में 416 लोगों की रिपोर्ट आनी शेष है।

आजादी के महोत्सव अभियान के रथ को किया रवाना

ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को किया जाएगा स्वच्छता के लिए प्रेरित

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

स्थानीय लघु सचिवालय के बैठक कक्ष में ग्रामीण स्वच्छता अभियान को जोर शोर से चलाने के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि स्वर्ण पदक विजेता, टोक्यो पैरालिंपिकस, शूटिंग 50 मीटर एस.एच.1 कैटेगरी मनीष नरवाल रहे। जबकि अध्यक्षता सीईओ जिला परिषद कम सीटीएम पुलकित मल्होत्रा ने की। गोल्ड मेडल विजेता मनीष नरवाल ने स्वच्छता के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले स्वच्छता सेना, प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

पैरालंपिक गोल्ड मेडल विजेता मनीष नरवाल के द्वारा सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह रथ यात्रा को झंडी दिखाई। गांव-गांव में स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरुक करने के लिए रवाना भी किया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद कम नगराधीश पुलकित मलहोत्रा ने कार्यक्रम का सम्बोधित करते हुए कहा कि महोत्सव की शुरुआत आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में की गयी है। इस अभियान को मुख्यत: चार भागों में बांटा गया है। हमारा प्रयास है कि उपायुक्त जितेंद्र यादव के कुशल मार्गदर्शन में जिला के प्रत्येक गांव में जन मानस तक स्वच्छता की आवाज पहुचाएं।

स्वच्छता अभियान से जुड़े सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह स्थ यात्रा बुधवार 15 सितम्बर से शुरू होकर आगामी दो अक्टूबर तक चलाई जाएगी। इस दौरान गांव-गांव में स्वच्छता रथ के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के मूल मंत्र, खाने से पहले शौच के बाद साबुन से धोए हाथ, खुले में शौच न जाए न जाने दें। शौचालय का प्रयोग करें, कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए समय-समय पर साबुन एवं पानी से हाथ धोते रहें, मास्क का प्रयोग करें, समय से टीकाकरण कराएं, दो गज की दूरी बनाकर रखें। इसके साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए सिगंल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें। कपड़े के थैलों का प्रयोग करें। गांव के सार्वजनिक स्थानों की मिलजुल कर साफ-सफाई करें और इन व्यवहारों को अपनाकर अपने जिला को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 में भी सर्वश्रेष्ठ स्थान दिलाने में अपना योगदान दें। इस दौराना जनभागिता से गांवों एवं उनके सार्वजनिक स्थानों की साफ-सफाई की जाएगी।

गांवों से प्लास्टिक को श्रमदान के माध्यम से इकट्ठा कर ऐजेंसी को दिया जाएगा। जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत निर्मित सड़कों में प्रयोग होगी। ज्यादा से ज्यादों गांवों में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन एवं उसके प्रबधन जाएगा। इस अभियान के तहत गांववासियों को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण-2021 के प्रति भी जागरूक किया जाएगा।

पोषण माह के तहत वेबिनार का आयोजन

फरीदाबाद। सेक्टर-16ए स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय के महिला प्रकोष्ठ एवं गृह विज्ञान विभाग के संयुक्त तत्वावधान में पोषण माह के तहत गर्भवती महिलाओं एवं स्वस्थ बच्चों के लिए पोष्टिक आहार विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया। न्यूट्रीशियन हेल्थ विभाग की इंचार्ज डॉ. मोनिका गर्ग मुख्य वक्ता रही। उन्होंने छात्राओं को स्वस्थ रहने के लिए पोष्टिक आहार लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे देश में गरीबी के साथ जागरुकता की भी कमी है, जिसके चलते अधिकतर बच्चे एवं महिलाएं कुपोषण का शिकार होते हैं। प्राचार्य डॉ. सुनिधि ने वेबिनार का शुभारंभ करते हुए कहा कि स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक भोजन के साथ बेहतर दिनचर्या का होना भी जरूरी है, कई बार दिनचर्या ठीक न होने पर भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मुख्य वक्ता ने कहा कि गर्भावस्था में महिला एवं शिशु के विकास के लिए पोष्टिक आहार बेहद जरूरी होता है।

भाजपा ने फूंके राहुल गांधी और कैप्टन अमरिंद्र सिंह के पुतले

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के किसान आंदोलन पर दिए बयान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी फरीदाबाद के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष पंकज सिंगला और किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुखबीर मलेरना के नेतृत्व में युवा व किसान मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अम्बेडकर चौक बल्लभगढ़ में राहुल गांधी और कै. अमरिंद्र सिंह का पुतला फूंककर विरोध दर्ज करवाया।

सुखबीर मलेरना ने उस अलोकतांत्रिक और गैर जिम्मेदाराना बयान की घोर भर्त्सना की। जिसमें कैप्टन अमरिंद्र सिंह ने किसान संगठनों से कहा कि वे अपना आंदोलन हरियाणा और दिल्ली में करें। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान से साफ हो गया है कि यह पूरा आंदोलन कांग्रेस और उनके नेताओं द्वारा प्रायोजित है। कांग्रेस के कार्यकर्ता आन्दोलन को संचालित कर रहे हैं। कांग्रेसी नेताओं राहुल गांधी, कैप्टन अमरिंद्र सिंह आदि के किसान आंदोलन को भड़काने वाले बयान अशोभनीय हैं, निंदनीय हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने शैलजा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और सुरजेवाला से पूछा कि वो हरियाणा में विकास के साथ हैं या विनाश के साथ और अपने मुख्यमंत्री कैप्टन अरविंद्र सिंह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करें। सुखबीर मलेरना ने कैप्टन साहब को नसीहत देते हुए कहा कि राजस्थान में आपकी सरकार है किसान हित में बाजरे के भाव क्यों नहीं बढ़वा लेते।

पंकज सिंगला ने कहा कि किसान आंदोलन को लेकर भारतीय जनता पार्टी और भाजपा नेता पहले दिन से कह रहे हैं कि ये आंदोलन किसानों का कम और सियासी दलों का ज्यादा है।

सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

मानवीय दृष्टिकोण

सर्वोच्च न्यायालय ने उचित ही आत्महत्या करने वाले कोविड-19 रोगियों का पक्ष लेते हुए इसे चिकित्सकीय मौत माना है। कोविड-19 से पीड़ित लोगों के पुनर्वास पर नजर रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को केन्द्र से कोविड-19 मरीजों की आत्महत्या को कोविड-19 से हुई मौत मानने का निर्देश दिया है ताकि उनके परिवारों को भी मुआवजा मिल सके। अदालत ने कहा कि संक्रमण के कारण होने वाले अत्यधिक कष्ट के कारण ही रोगियों ने आत्महत्या की। जस्टिस एम.आर. शाह व जस्टिस ए.एस. बोपन्ना की पीठ ने ये टिप्पणियां केंद्र के दिशानिर्देशों पर गौर करते हुए कीं जिसमें जहर देने, आत्महत्या, हत्या या दुर्घटना से होने वाली मौतों को कोविड-19 मौतें नहीं माना गया है, भले ही इसके साथ संक्रमण भी एक कारण हो। सरकार द्वारा मामले की पुन: समीक्षा के आश्वासन से अदालत संतुष्ट थी। अदालत का प्रस्ताव निश्चित रूप से एक मानवीय दृष्टिकोण है, पर सरकार तथा न्यायपालिका को पहले पूरे मामले को समग्रता से देखना चाहिए क्योंकि इसमें अनेक चीजें शामिल हैं। पीड़ित द्वारा की जाने वाली कोई भी आत्महत्या अत्यधिक निराशाजनक व परेशान करने वाली परिस्थितियों में होती है। आत्महत्या के कारण परिवारी सदस्यों को उस स्थिति में कमाऊ व्यक्ति से हाथ धोना पड़ता है जब एकमात्र पीड़ित ही नौकरी कर रहा हो। गरीब और वंचित लोगों की स्थिति इससे और खराब हो जाती है। तकनीकी रूप से कहें तो यह सिद्ध करना सरकार के लिए

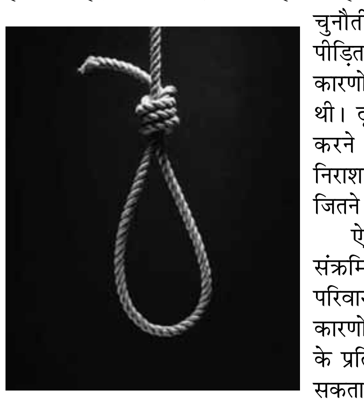

चुनौती होगी कि कोविड-19 पीड़ित रोगी की आत्महत्या अन्य कारणों के बजाय संक्रमण के कारण थी। दूसरे, आत्महत्या को मजबूर करने वाले अनेक अन्य निराशाजनक कारण कोविड-19 जितने ही प्रभावी हो सकते हैं।

ऐसे में केवल कोविड-19 संक्रमित रोगियों की आत्महत्या पर परिवारों को मुआवजा देने को अन्य कारणों से आत्महत्या करने वालों के प्रति भेदभाव की तरह देखा जा सकता है जो समान रूप से भयानक हो सकते हैं। तीसरे, सरकार तथा अदालतों को उन लोगों को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है जो आत्महत्या को केवल अपराध मानते हैं और पीड़ित के प्रति उनका दृष्टिकोण विकृत हो सकता है। आत्महत्या भारतीय दंड संहिता की पुरानी पड़ चुकी धारा 309 के अंतर्गत अपराध है। हालांकि, मानसिक स्वास्थ्यरक्षा कानून, 2017 से इसका आयाम घटा दिया गया है, पर इस धारा को वापस नहीं लिया गया है। इस कानून के अनुसार आत्महत्या का प्रयास करने किसी व्यक्ति को 'गंभीर तनाव से पीड़ित मानते हुए उसे सुनवाई व दंड से अलग रखने' की बात करते हुए सरकार से आह्वान किया गया है कि वह ऐसे व्यक्ति की 'समुचित देखभाल, इलाज व पुनर्वास' करे ताकि ऐसे प्रयास 'के पुन: होने की जोखिम घट सके।' कानून के इस मानवीय आयाम को लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए ताकि उन परिस्थितियों में कमी आ सके जिनके कारण आत्महत्या को मजबूर होना पड़ता है। इससे पीड़ितों के परिवारों या प्रयास में विफल रहने वालों का पुनर्वास प्रोत्साहित होगा। दीवालियापन, कर्जदारी तथा फसल खराब होने पर भारत में हजारों किसान आत्महत्या कर लेते हैं। उनको मुआवजा देने की योजना है, हालांकि जमीन का स्वामित्व न रखने वाले किसान अभी इस मुआवजे के हकदार नहीं हैं जिनमें अधिकांशत: महिला किसान शामिल हैं। मामले के प्रति तार्किक दृष्टिकोण संभवत: इस सवाल में छिपा है कि क्या कर्जदारी के कारण आत्महत्या करने वाले उस स्वस्थ किसान को भी मुआवजे का अधिकार होगा जो कोविड-19 लाकडाउन के कारण अपनी फसल नहीं बचा सका।

बंदूक की नोक पर सफल नहीं होगी कूटनीति

संयुक्त राष्ट्र की आतंकवादी सूची में अभी भी एक संगठन के साथ शांति समझौता गंभीर चिंता का एक उदाहरण है जो विश्व समुदाय के लिए जटिलताओं का पिटारा खोलने वाला है।

निष्ठा कौशिकी
(लेखक पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय भटिंडा में सह प्रोफेसर हैं)

अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने पिछले तीन हफ्तों के दौरान वैश्विक सुरक्षा और भू-राजनीति में एक आदर्श बदलाव देखा है। अमेरिका और तालिबान के बीच समझौते और बाद में काबुल्टो पर कब्जा करने के साथ, कुछ राज्यों और तालिबान के बीच बढ़ते अभिसरण, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति फिर कभी पहले जैसी नहीं होगी। जिस तरह से कूटनीति और अंतर-राज्यीय संबंधों को आगे बढ़ाया जाएगा, उसमें गहरा बदलाव होगा।

सबसे तात्कालिक सवाल यह है कि क्या राज्य के प्रतिनिधि शांति समझौतों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और आतंकवादी संगठनों के साथ सौदा कर सकते हैं, जो हिंसा और आतंकी तंत्र के माध्यम से क्षेत्रों को जब्त करने के इरादे को जानते हैं? संयुक्त राष्ट्र की आतंकवादी सूची में एक संगठन के साथ शांति समझौता गंभीर चिंता का एक उदाहरण है जो विश्व समुदाय के लिए भानुमती का पिटारा खोलता है।

आज, कतर और पाकिस्तान जैसे विभिन्न स्रोतों के माध्यम से, तालिबान संदेश भेज रहा है कि अगर दुनिया नहीं चाहती कि अफगानिस्तान आतंकी केंद्र बन जाए तो बातचीत और जुड़ाव शुरू होना चाहिए। इस तरह के बयान निश्चित रूप से अनुरोध के रूप में नहीं हैं और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों में घुसपैठ के छिपे मकसद से मान्यता और वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए सामरिक ब्लैकमेल की राशि नहीं है। पाकिस्तान के उदाहरण ने साबित कर दिया है कि वित्तीय प्रवाह अभिनेताओं (राज्य और गैर-राज्य दोनों) को दूर नहीं करता है, जिससे जिहाद जैसे उनके भयावह एजेंडे में मदद मिलती है। भेड़िये को भेड़ के कपड़े पहनने की जरूरत महसूस होती है। दुनिया जिस दुविधा का सामना कर रही है, वह यह है कि तालिबान ने अवैध रूप से और जबरन इस क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया है, और एक वैध वारिस के रूप में कार्य करने के लिए, उसे खुद को एक कानूनी इकाई के रूप में दुनिया के सामने पेश करना होगा। चीन, पाकिस्तान, रूस, ईरान और अन्य को सरकार गठन प्रक्रिया के लिए एक आमंत्रण भेजा गया है जिसमें कम से कम मंत्रियों में से आधे कट्टरपंथी इस्लाम और जिहाद के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले आतंकवादी हैं। तालिबान के साथ कूटनीति, सहायता और व्यापार शुरू करने और उनके कार्यों पर उनका आकलन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से भारत और जापान जैसे दाता देशों पर दबाव केवल 'खरगोशों के साथ दौड़ने और शिकारी कुत्तों के साथ शिकार' की रणनीति को मजबूत करेगा। देशों को इस क्षेत्र में स्थिरता की उम्मीद में अफगानिस्तान में तालिबान जैसे पाकिस्तान और हिंसक गैर-राज्य अभिनेताओं (वीएनएसए) जैसे विफल राज्यों के वित्तपोषण और सहायता की विरोधाभासीता से बाहर आना चाहिए। जबकि अमेरिका यह निष्कर्ष निकालता है कि भविष्य के कार्यों को तय करने में बल प्रमुख कारक नहीं है, बल की समान शक्ति को प्रोत्साहित किया जाएगा यदि ऐसा वीएनएसए या तो लगा हुआ या सहायता प्राप्त है।

ब्लैकमेल की स्वीकृति, जैसा कि इस मामले में है, प्रमुखता प्राप्त करने वाली बहुराजकीय प्रवृत्तियों का दीर्घकालिक समाधान नहीं है। यह केवल उस व्यवहार को प्रोत्साहित करेगा जिसे गनपॉइंट डिप्लोमेसी कहा जा सकता है, जो गनबोट डिप्लोमेसी की चीनी रणनीति के समान है, जिसमें ब्लैकमेलिंग का उपयोग सामरिक और रणनीतिक गतिशीलता के लिए किया जाता है। इसी तरह, तालिबान के साथ बातचीत, यहां तक कि अन्य देशों द्वारा भी, अंतरराष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में नई मिसाल कायम करते हैं, जिसके परिणाम इस सदी के बाकी हिस्सों में दुनिया को भुगतने पड़ सकते हैं।

तालिबान अफगान को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुपालन में उनके कार्यों के प्रदर्शन के बदले में मान्यता या सहयोग का मुद्दा इस प्रकार मुश्किल है। भारत जो अपेक्षा करता है और अन्य ताकतें तालिबान से जो अपेक्षा करती हैं, उसमें अंतर है। हम मुख्य रूप से खुद को बचाने के लिए छोड़े गए हैं। यहां तक कि सामान्य स्थिति या कूटनीति का मामूली प्रदर्शन भी भारत को प्रभावित करेगा। अब से एक या दो साल बाद जो होगा वह अज्ञात के दायरे में है। यहां तक कि कुछ शर्तों पर, तालिबान के साथ एक सगाई को इसके लिए एक राजनयिक मान्यता के रूप में लिया जाएगा, जिसके घरेलू परिणाम होंगे और गलत मिसालें पैदा होंगी। मान लीजिए कि भारत तालिबान के साथ बातचीत का विकल्प चुनता है, कुछ महीनों के बाद, हम तालिबान को यूएनजीए या अन्य क्षेत्रीय संगठनों में टेबल के पार बैठे अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व करते हुए हमारे आंतरिक मामलों पर टिप्पणी कर सकते हैं। क्या भारत को चीन और पाकिस्तान द्वारा उसी में बरगलाया नहीं जाएगा। जिस तरह से अमेरिका को नीचा दिखाया गया था? कभी-कभी, जबरदस्ती के तहत तुरंत निर्णय लेने की तुलना में निर्णय न लेना अधिक वांछनीय होता है, क्योंकि बाद के समय शायद ही कभी उन्हें उलट सकते हैं।

दूसरा, अमेरिकी सहयोगियों की ओर से छोड़े जाने की भावना भविष्य के गठबंधनों को प्रभावित करेगी। वर्तमान समस्या में, भारत के तत्काल हितों को तब दरकिनार कर दिया गया जब अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ दिया, हथियारों का एक जखीरा छोड़ दिया, जिसे पहले ही पाकिस्तान ले जाया जा सकता था, जिसका इस्तेमाल केवल पाकिस्तान की सीमा से लगे क्षेत्रों में भारतीय हितों के खिलाफ किया जा सकता था। चूंकि चीन और पाकिस्तान के निहित स्वार्थ ईरान और रूस के समर्थन से खिल रहे हैं, इसलिए एक प्रासंगिक सवाल यह है कि भारत इस मुद्दे से कैसे निपटेगा। अंतिम भारतीय नागरिक अफगानिस्तान से बाहर निकलने तक कुछ पिछले दरवाजे संचार चैनलों (कूटनीति नहीं) को मौलिक स्तर पर बनाए रखा जाना चाहिए। हमें निकासी के लिए बातचीत और सरकार के रूप को पहचानने के बीच अंतर करना सीखना चाहिए। तीसरा, जैसा कि अमेरिका अपनी नीतियों का आत्मनिरीक्षण करता है, संभावना है कि वह लोकतांत्रिक यथार्थवाद के दृष्टिकोण को अपना सकता है, जिसे चार्ल्स क्राउथमर ने 2004 में सुझाया था जो केवल रणनीतिक आवश्यकता के स्थानों पर अपना खून और खजाना देता है। ऐसे में, भारत के प्रति अमेरिका की कौन-सी सामरिक और सामरिक प्रतिबद्धताओं को प्रदर्शित करने की आवश्यकता है? यदि भारत को एक सहयोगी माना जाता है, तो खुद को एक विश्वसनीय भागीदार साबित करने की जिम्मेदारी अमेरिका पर है। रूस के लिए भी यही मानक लागू हैं।

इसके अलावा, राजनयिक जुड़ाव अब किसी भी दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं से रहित एक नए प्रकार के शक्ति संबंधों की ओर मुड़ते दिख रहे हैं। इस तरह की प्रवृत्तियों में, देश वीएनएसए के माध्यम से अपनी पहुंच बढ़ाने में संकोच नहीं करते हैं। इसके अलावा, प्रतिकूल शक्तियां भी अल्पकालिक या दीर्घकालिक लाभ के लिए मिलकर काम करती हैं, और इस प्रक्रिया में, अपने मौजूदा मुद्दों को या तो किनारे कर देती हैं या हल कर लेती हैं। जब चीन और पाकिस्तान ने अपने ढोंग का पर्दाफाश कर दिया है, और अमेरिका लोकतंत्र की वकालत करने के लिए अपनी पिछली पुलिसिंग भूमिका के साथ आगे नहीं बढ़ रहा है, तो नई दिल्ली को इस नए महान खेल के समाधान के रूप में भारत-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

भारत के दृष्टिकोण से, हमें यह सवाल करना चाहिए कि क्या अफगानिस्तान छद्म संगठनों के विभिन्न गुटों का एक आतंकी केंद्र बन गया है या क्या यह केवल भारत के खिलाफ काम करने वाले एक विशेष आईएसआई विस्तार के रूप में काम करेगा? भू-राजनीति के कारण हक्कानियों को तथाकथित सरकार में शामिल किया गया है। इसमें कोई शक नहीं कि इससे भारत के हित प्रभावित होंगे। तालिबान के प्रवक्ता सुहैल शाहीन पहले ही कह चुके हैं कि कश्मीर अगला है। तालिबान ने कहा कि वह कुछ दिनों बाद पाकिस्तान और भारत के बीच हस्तक्षेप नहीं करेगा। एक सप्ताह के भीतर जारी किए गए दो बयानों की कोई विश्वसनीयता नहीं है। भारत किस कथन पर भरोसा कर सकता है? इसके अलावा, भारत को तालिबान पर भरोसा क्यों करना चाहिए यदि पाकिस्तान की सक्रिय भूमिका पहले से ही प्रमाणित है?

अफगान समस्या के मंथन के परिणाम संभवत- तब दिखाई देने लगेंगे जब यह उभरती प्रतिद्वंद्विता और साझेदारियों का नया केंद्र बन जाएगा। दुनिया और अधिक अराजकता और आतंक देख सकती है, लेकिन लंबे समय तक नहीं जब तक कि ऐसी प्रवृत्तियों के खिलाफ प्रतिरोध नहीं होगा। वे गठबंधन, साझेदारी या अंतरराष्ट्रीय मंच पर हो सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से, बंदूक की नोक पर कूटनीति लंबे समय तक जारी नहीं रहेगी।

अमेरिकी राष्ट्रपति का गैरजिम्मेदाराना रवैया

भूपिंदर सिंह
(लेखक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी एवं पूर्व उपराज्यपाल हैं)

जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं, पर वे उन 29 राष्ट्रपतियों में शामिल नहीं हैं जिन्होंने किसी क्षमता में सेना में काम किया था। उन्होंने पांच बार वियतनाम जाना स्थगित करने में सफलता पाई तथा राजनीतिक रूप से रिचर्ड निक्सन के युद्ध प्रयासों का विरोध किया। बाइडेन का यह दुविधा भरा दृष्टिकोण उस समय भी सामने आया था जब उन्होंने 2002 में ईराक युद्ध को अनुमति देने पर असहमति प्रकट की थी। वे संभवत: इसे शुरू किए जाने के समय से ही इसके खिलाफ हो गए थे। लेकिन उन्होंने सिनेट संबंध समिति के अध्यक्ष के रूप में अपने दृष्टिकोण के उलट हमले के लिए सैनिक शक्ति प्रयोग करने का अधिकार-एयूएमएफ दिया।

लेकिन बाद में संयोग से एक निर्णायक रूप से नस्लवादी, यौनवादी व नस्ली घृणा के शिकार डोनाल्ड ट्रंप से मुकाबले ने बाइडेन का राष्ट्रपति कार्यालय पहुंच कर शपथ लेना सुनिश्चित कर दिया और इस प्रकार वे सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ बन गए। ट्रंप ने हास्यास्पद और खतरनाक ढंग से अमेरिकी सेना की छवि पर कब्जे का प्रयास किया था। स्पष्ट रूप से ऐसे में परंपरागत तरीके से ज्यादा दक्षिणपंथी रिपब्लिकन पार्टी का समर्थन करने वाले अनेक सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए दो बुरी पंसदों की तुलना में बाइडेन ज्यादा अच्छे लगे।

लगातार युद्धों में संलिप्त रहने वाले देश तथा सेवानिवृत्त सैनिक मामलों के विभाग के अनुसार 19 मिलियन सेवानिवृत्त सैनिकों वाले देश में 'बावर्दी' बिरादरी की राय अर्थवान है जो अमेरिका की कुल वयस्क जनसंख्या में लगभग 10 प्रतिशत हैं। बाइडेन ने अक्सर राष्ट्रपति चुनाव अभियान में अपने स्वर्गीय बेटे ब्यू बाइडेन की याद की जिसने सेना में काम किया तथा मेजर के पद से जज एडवोकेट जनरल कार्पस तक पदोन्नति प्राप्त की। ब्यू ने 2008 से 2009 तक ईराक युद्ध में भाग लिया था और उसे उसकी सेवाओं के लिए ब्रोंज स्टार से सम्मानित किया गया था। प्रचार अभियान में बाइडेन की 'पवित्र जिम्मेदारी' सैनिक परिवारों के प्रति सामने आई। उन्होंने 'सेना सदस्य के माता-पिता की भावनायें' व्यक्त कीं 'जिनकी तैनाती ईराक में हुई थी।' कहा गया कि 'उप-राष्ट्रपति जो बाइडेन तथा डा. जिल बाइडेन समझते हैं कि यह केवल हमारे देश की सेवा करने के लिए सेना में भर्ती होने वालों का नहीं, बल्कि उनके परिवारों की भी भावना' है।

इस बीच ट्रंप के मूर्खतापूर्ण दृष्टिकोण के कारण न केवल ज्वाइंट चीफआफस्टाफजनरल मार्क मिली व्यथित थे, बल्कि सम्मानित सेवानिवृत्त जनरल जेम्स मैटिस व एच.आर. मैक्मास्टर ने भी बाइडेन के पक्ष में भावनायें बनाईं। इसमें ट्रंप की लफ्फाजी तथा बेतुकी बातों ने भी अपनी भूमिका निभाई।

आज राष्ट्रपति कार्यालय में आठ महीने तक जिम्मेदारी संभालने के बाद बाइडेन ने सैन्यवादी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला लिया है और इससे उनकी रेटिंग तेजी से गिरी है। हालांकि, अफगानिस्तान में 20 साल से जारी युद्ध समाप्त करने की मांग लंबे समय से हो रही थी, लेकिन पराजित नायक की तरह जल्दबाजी में पलायन से देश के भीतर और बाहर उनकी तथा अमेरिकी सेना की छवि गिरी है। इसमें आईएसआईएल-के हमले में मारे गए सैनिक भी शामिल हैं। ऐसे में अपरिहार्य रूप से वियतनाम से तुलना हो रही है और इस बार भी इस अपमान का खामियाजा सेवानिवृत्त सैनिकों को भुगतना पड़ रहा है। निराशा की भावना इस कटु यथार्थ से और गहरी हुई है कि तेजी से पतन का कारण उचित आपरेशनल योजना का अभाव तथा 'दुश्मन', यानी 'तालिबान' से 'सुरक्षित रूप से बाहर निकलने' की अनुमति लेना था। एक निरुत्साही सेना तथा गैर-प्रतिबद्ध राजनेताओं के उलट अमेरिकी सैनिक को एक अतिरिक्त व अकल्पनीय नैतिक चोट पहुंची है जिसे उसकी किस्मत पर पीछे छोड़ दिया गया था। इनमें अनेक सहयोगी अनुवादक, ड्राइवर तथा सहायक कर्मचारी शामिल हैं। अफरातफरी तथा कुप्रबंधन से भरे पलायन ने बावर्दी बिरादरी को भारी कष्ट, निराशा और शर्म में डुबो दिया है जिसका दोषी निश्चित रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यालय है। निश्चित रूप से जो बाइडेन की भावनायें 'बावर्दी' लोगों के साथ जुड़ी नहीं हैं जो अपमानजनक रूप से उस समय अपनी घड़ी देख रहे थे जब काबुल हवाईअड्डे पर मारे गए 13 शहीद अमेरिकी सैनिकों के ताबूत दु:खद 'गौरवपूर्ण हस्तांतरण' के लिए उतारे जा रहे थे।

बहुत से लोगों ने राष्ट्रपति द्वारा बार-बार अपने स्वर्गीय बेटे का नाम लेने की अनुपयुक्तता की ओर संकेत किया है, जबकि उन्होंने उन शहीदों का नाम नहीं लिया जो उनके नेतृत्व में वीरगति को प्राप्त हुए। अनेक शहीद जवानों के परिवारों ने राष्ट्रपति से मिलने से इनकार कर दिया, जबकि ऐसा करने वाले कुछ लोगों ने उनके मुंह पर खरी-खरी बातें कहीं। एक शहीद की मां ने बाइडेन को 'भुलक्कड़पन से पीड़ित ऐसा व्यक्ति कहा जो यह भी नहीं जानता कि वह व्हाइट हाउस में है।'

महत्वपूर्ण है कि यह कोई पक्षपाती विभाजन नहीं है क्योंकि इनमें से अनेक परिवारों ने समान रूप से डोनाल्ड ट्रंप की भी निन्दा की थी जो गलत समय पर सैनिकों की मौतों का राजनीतीकरण कर रहे थे। इसे बहुत से लोगों ने 'अपमानजनक', 'घृणित' तथा 'भयानक गलती' कहा था। ट्रंप ने अपनी खास चालाकी के चलते पीड़ित परिवारों को निशाना बनाते हुए उनको खतरनाक क्षेत्र में धकेल दिया था। उनका समर्थन केवल ऐसे लोगों के लिए था जो उनका राजनीतिक रूप से समर्थन करते। इनमें कैप्टेन हुमायूं खान की गोल्ड स्टार फैमिली की निन्दा भी शामिल है जो उनको पसंद नहीं करती थी। दुनिया भर के लोकतंत्रों में सेना के प्रति राजनीतिक व्यवहार लगातार असहनीय होता जा रहा है। इसके कारण चुनावी फसल काटने हेतु विमर्श को भावनायें भड़काने वाला बनाया जा रहा है। यह प्रवृत्ति अमेरिका जैसे परिपक्व लोकतंत्रों में भी देखी जा रही है।

अपरिहार्य व तुलनात्मक रूप से अधिकांश सेवानिवृत्त सैनिक जानते हैं कि कमांडर इन चीफ को संवैधानिकता, आत्मसंयम, चारित्रिक दृढ़ता तथा सैद्धान्तिक नेतृत्व के प्रति निस्वार्थ प्रतिबद्धता प्रकट करनी चाहिए। इसी कारण उन्होंने ट्रंप के बजाय बाइडेन का समर्थन किया था। लेकिन अफगानिस्तान में घटी हालिया घटनाओं से से बिना किसी पक्षपात के बाइडेन पर सवाल उठने लगे हैं। पेशेवर 'बावर्दी' लोगों की दुनिया में 'न्यायोचित युद्ध' जीतना महत्वपूर्ण है और यदि ऐसा न हो तो वीरता और गरिमा के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त होना एकमात्र विकल्प है। अफगानिस्तान में इन दोनों में से कोई भी प्राप्त नहीं हुआ है और इसके कारण बावर्दी बिरादरी में बाइडेन का सम्मान निश्चित रूप से घटा है। किसी पक्षपात के बिना उनसे निश्चित रूप से सवाल पूछे जाने चाहिए।

आप की बात

पर्चे लीक होना गंभीर मुद्दा

प्रतियोगी या कॉलेजों की परीक्षाओं के पर्चे लीक होना आज की नियामक संस्थाओं के लिए एक गंभीर मुद्दा होना चाहिए। हाल ही में जेईई मेंस एवं हरियाणा पुलिस भर्ती की परीक्षाओं के पेपर लीक होने का मामला सामने आया है। पूर्व में भी भारत के कई राज्यों में इस प्रकार की घटनाएं घटित हो चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस संबंध में गहरी चिंता जताते हुए कहा है कि इस अनैतिक व्यापार से परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर एक प्रश्न चिन्ह लगता जा रहा है। परीक्षाओं के पेपर लीक होने के कारण मेहनत करने वाले विद्यार्थियों का सबसे ज्यादा नुकसान होता है। उनका भविष्य दांव पर लग जाता है। इस संबंध में मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत बनाया जाना चाहिए। ज्यादातर मामलों में परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं के स्टाफ का कोई व्यक्ति ही इस गोरखधंधे में शामिल पाया जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर छपने की पूरी प्रक्रिया पर कड़ी नजर रखने के लिए सिस्टम बनाने की भी आवश्यकता है। अलग-अलग स्टेट के लिए पेपर में विविधतापूर्ण प्रश्न प्रणाली अपना कर भी इस समस्या से एक हद तक निपटा जा सकता है। मेधावी विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखना राज व्यवस्था की जिम्मेदारी है।

– **ललित महालकरी**, इंदौर

प्रबल जनसुनवाई तंत्र

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बीते तीन माह जनसुनवाई पोर्टल और हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों की वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की। जिसमें शिकायतों के समाधान में शिथिलता बरती गई। शिकायतों के निस्तारण से जनता सन्तुष्ट नही थी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर तन्त्र अपनी कार्य शैली और मानसिकता बदलने को तैयार नही है। जबकि योगी ने अब तक एक हजार से अधिक नकारा और भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई और कुछ को समय से पूर्व सेवा निवृत्त कर दिया। जिला स्तरीय अधिकारियों का रवैया सुधर नही रहा है। इस लिये मुख्यमंत्री ने प्रतिदिन जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को प्रतिदिन एक घण्टे जनसुनवाई करने का निर्देश दिया। 18 जुलाई 21 को उन्नाव जिले आयोजित सम्पूर्ण समाधन दिवस में सिने और टीवी अभिनेता अतुल तिवारी खतौनी में नाम संशोधन कराने तहसील उन्नाव गए जहां अधिकारियों ने खतौनी में नाम संशोधन कर संसोधित खतौनी भी उपलब्ध करा दी। फ़िल्म कलाकार ने त्वरित समस्या समाधान होने पर प्रशासन की तत्परता और सम्पूर्ण समाधान दिवस की सोच की सराहना की। यही नीति आम लोगो के लिये भी अपनाई जा सकती है।

– **कुलदीप मोहन त्रिवेदी**, जरगांव, उन्नाव

महामारी की मार

एक साल से अधिक का समय बीत चुका है महामारी की मार खाते और इसकी तीव्रता को काबू करते हुए। दरअसल पापी कोरोना ने कुछ आयामो को इस हद तक प्रभावित किया है की उससे जुड़े लोगो का जीना और जीविका कमाना दोनो मुश्किल हो गया है। बीते महीनो में कोरोना महामारी ने ऐसी बेदर्दी दिखाई है की छोटे उद्योगों का वापस मुख्यधारा में आना कठिन हो गया है। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट के एक सर्वेक्षण के अनुसार 82 प्रतिशत से अधिक छोटे व्यवसायों ने महामारी के दौरान नकारात्मक प्रभावो का अनुभव किया है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा कई कदम भी उठाए गए है जैसे 15 राहत उपायों में से 6 का उद्देश्य भारत के छोटे उद्योगों को वापस मुख्यधारा में लाना, जोकि काबिले तारीफ है, लेकिन जहां तक वर्तमान की बात करें तो इस नीति के तहत कितना काम हुआ है यह तस्वीर साफ नहीं है। इसके अलावा, देशवासियो का भी दायित्व बनता है कि वे छोटे उद्योगों को बढ़ावा दे। अत: इस कठिन घड़ी में सरकार और जनता को एक साथ मिलकर इस संकट से निपटने की जरूरत है।

– **निखिल रस्तोगी**, कुरुक्षेत्र विवि

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते हैं।

फरमाया

ईडी ने अभिषेक बनर्जी से 9 घंटे पूछताछ की। हमें धमकाया नहीं जा सकता। हम कांग्रेस, अथवा अखिलेश यादव या शरद पवार की तरह नहीं हैं।

– **ममता बनर्जी**
मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल

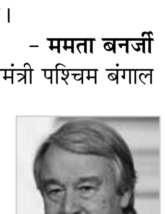

अफ़गानिस्तान के लोगों को जीवन रेखा की जरूरत है। कई दशकों से युद्ध, वेदनाओं एवं असुरक्षा से जूझने के बाद वे सर्वाधिक संकटकालीन दशा में हैं।

– **एटोनियो गुटरेस**
संरा महासचिव

तेलंगाना दलित बंधु योजना को सफल बनाने के बाद हम दलितों के विकास के लिए नया रास्ते खोलने वाला राज्य बन गए हैं।

– **के चंद्रशेखर राव**
तेलंगाना के मुख्यमंत्री

पूर्ववर्ती सरकारों ने तुष्टीकरण की राजनीति की: राधा मोहन

● मोदी-योगी के नेतृत्व में यूपी ने अपनी खोई सांस्कृतिक विरासत को पुनः प्राप्त किया: प्रदेश प्रभारी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने गौतमबुद्ध नगर दादरी विधानसभा के आईआईएमटी कॉलेज में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश लंबे समय तक भ्रष्टाचार, माफिया, आतंक व तुष्टिकरण आदि अनेक प्रकार के समस्याओं से ग्रस्त था। पूर्व की सरकारों ने प्रदेश के विकास पर ध्यान न देकर केवल अपने वोट बैंक के विकास के लिए तुष्टीकरण की राजनीति की, जिसके फलस्वरूप भारतीय संस्कृति व आदर्श का केंद्र रहा उत्तर प्रदेश प्रश्न प्रदेश बनकर रह गया। मोदी-योगी की सरकार आने के बाद प्रदेश में न सिर्फ अपनी खोई सांस्कृतिक विरासत को पुनः प्राप्त किया बल्कि विकास के नए स्तंभ भी स्थापित किए। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने उत्तर प्रदेश को हर तरह से सामर्थ्यवान और समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में काम किया। उन्होंने कहा कि मत मजहब की राजनीति का खात्मा करना और उत्तर प्रदेश को संकीर्ण राजनीति से मुक्त करने का संकल्प लिया। आज प्रत्यक्ष रुप से दिखाई देता है कि जो चुनौतियां उन्हें विरासत में मिली थी योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उन समस्त चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत किया है। राधा मोहन सिंह ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की उत्कृष्ट कार्यशैली का ही परिणाम है विरासत में मिली लचर कानून व्यवस्था अब सुदृढ़ कानून व्यवस्था में परिवर्तित हो गई है। जिस उत्तर प्रदेश में पहले अपराधियों, माफियाओं का बोलबाला था आज उसी उत्तर प्रदेश में अपराधी और माफिया थरथर कांपते हैं, माताएं और बहनें कभी भी कहीं भी आने-जाने से अब नहीं डरती हैं। यह सब योगी आदित्यनाथ के अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के कारण ही संभव हो पाया है।

कुछ नया करने के लिये हमेशा प्रयत्नशील रहें: केशव

● उपमुख्यमंत्री ने अभियन्ता दिवस पर विश्वेश्वरैया द्वार का किया लोकार्पण

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को लोक निर्माण विभाग में 1 करोड़ 08 लाख 96 हजार रुपया की लागत से यूपी राजकीय निर्माण निगम द्वारा बनाये गये भव्य और आकर्षक विश्वेश्वरैया द्वार का उद्घाटन किया। अभियन्ता दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विश्वेश्वरैया के जीवन दर्शन, उनके सुकृत्यों व तकनीकी ज्ञान पर प्रकाश डालते हुये अभियन्ताओं को जहां उनके जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया, वहीं उन्होने अभियन्ताओं को अपनी पूरी क्षमता से कार्य करने हेतु उनमें नयी उर्जा और नये उत्साह का संचार किया। विश्वेश्वरैया जयन्ती का शुभारम्भ केशव प्रसाद मौर्य ने दीप प्रज्वलित कर व विश्वेश्वरैया के चित्र पर माल्यार्पण कर किया।

विश्वेश्वरैया सभागार में भारत रत्न मोक्षगुण्डम विश्वेश्वरैया की जयन्ती पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बहुत ही सराहनीय कार्य करके लोक निर्माण विभाग में नये आयाम स्थापित किये हैं। उन्होंने कहा कि अभियन्तागण कुछ नया करने के लिये हमेशा प्रयत्नशील रहें उनके स्तर से हरसम्भव सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। विश्वेश्वरैया जी को अपनी आत्मिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुये उन्होने उनके द्वारा किये गये कार्यों की याद ताजा की। उन्होने कहा कि अपने कार्य और व्यवहार से अभियन्तागण विभाग को नयी उचाईयों पर ले जाएं यही विश्वेश्वरैया के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष अभियन्ता दिवस के अवसर पर विश्वेश्वरैया द्वार बनाये जाने की घोषणा की गयी थी और अभियन्ताओं ने कड़ी मेहनत करके निर्धारित समय सीमा के अन्दर भव्य और आकर्षक द्वार तैयार किया, इसके लिये निःसन्देह सभी अधिकारी बधाई के पात्र हैं।

श्री मौर्य ने कहा कि आज से गड्ढामुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, इसको पूरी शक्ति और इमानदारी के साथ चलाया जाय, गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जायेगा। उन्होने कहा कि गड्ढामुक्ति अभियान की लगातार समीक्षा की जाय, अनुश्रवण किया जाय तथा निरीक्षण किया जाय और नियोजित तरीके से क्रासचेकिंग व औचक निरीक्षण भी किया जाय।

आम आदमी पार्टी ने 100 सीटों पर जारी की संभावित प्रत्याशियों की पहली सूची

लखनऊ। आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए 100 विधानसभा प्रभारी ध्संभावित प्रत्याशियों की पहली सूची बुधवार को जारी की। प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेसवार्ता कर विधानसभा प्रभारियों के नाम घोषित करते हुए बताया कि ये साथी पार्टी के अभियान को सफलतापूर्वक संचालित करने का काम करेंगे, इनका काम सही रहा तो इनको ही पार्टी वहां अपना प्रत्याशी बनाएगी। इस सूची में पिछड़े वर्ग से 35 प्रभारी बनाकर उन्हें बड़ा प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। वहीं आप की इस सूची में 20 ब्राह्मण 16 दलित और 5 मुस्लिम नेताओं को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। संजय सिंह ने बताया कि सूची में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है।

सूची में डॉक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट से लेकर नौजवान, किसान हर वर्ग से लोगों को शामिल किया गया है। लखनऊ मध्य से नदीम अशरफ जायसी, उत्तर से अमित श्रीवास्तव, पश्चिम से राजीव बक्शी, कैंट से दुर्गेश सिंह, सरोजनी नगर से रोहित श्रीवास्तव, बख्शी का तालाब से बलीराम वर्मा और मोहनलालगंज से सूरज कुमार प्रत्याशी बनाए गए।

केरल व आंध्रा से लौटे दो सीआरपीएफ जवान कोरोना संक्रमित

लखनऊ। केरल और आंध्र प्रदेश से लौटे दो सीआरपीएफ जवानों में कोरोना के लक्षण मिले है। ऐसे में इन जवानों को आइसोलेशन में रखने के साथ ही इनकी जीनोम सिक्रेंसिंग केजीएमयू से कराई जा रही है। वहीं एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग ने इनके सम्पर्क में आने वाले 115 लोगों की कांटेक्ट ट्रेसिंग कराई है। राहत की बात यह है कि सभी की एंटीजेन रिपोर्ट निगेटिव आई है। डिप्टी सीएमओ डॉ मिलिंद वर्धन के मुताबिक दोनों जवान सरोजनी नगर स्थित सीआरपीएफ कैंप में अलग-अलग आइसोलेशन में है। दोनों में कोई लक्षण नहीं है। संक्रमित जवानों के नमूने जीनोम सीक्रेसिंग के लिए केजीएमयू भेजे गए हैं। डॉ मिलिंद के मुताबिक बुधवार देर शाम तक 115 जवानों के नमूने लिए जा चुके हैं। इन सभी की पहले एंटीजेन जांच कराई गई। एंटीजेन में कोई भी पॉजिटिव नहीं आया है। एहतियात के तौर पर आरटी पीसीआर जांच भी कराई जाएगी। दोनों जवानों की यात्रा का इतिहास भी निकाला जा रहा है। ताकि संबंधित लोगों को आगाह किया जा सके।

समाज कल्याण के निदेशक को अवमानना की नोटिस जारी

लखनऊ(विसं)। करीब 21 माह से एक छात्र की छात्रवृति के संदर्भ में आदेश के बावजूद कोई निर्णय नहीं लेने पर हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने स त रुख अख्तियार किया है। पीठ ने समाज कल्याण निदेशालय के निदेशक राकेश कुमार के विरुद्ध अवमानना की नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। पूछा है कि क्यों न उन्हें अदालत के आदेश की अवहेलना करने के लिए दंडित किया जाए। मामले की अगली सुनवाई नवंबर माह में होगी। जस्टिस विवेक चौधरी की एकल पीठ ने यह आदेश छात्र आशुतोष शुक्ला की अवमानना याचिका पर दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील चन्दन श्रीवास्तव ने बहस की। इनका कहना था कि 21 नवंबर 2019 को हाईकोर्ट ने समाज कल्याण के निदेशक को आदेश दिया था कि इस छात्र की छात्रवृत्ति के संदर्भ में उसके सभी आवश्यक दस्तावेजों के मद्देनजर विधिस मत निर्णय लिया जाए।

रेप पीड़िता के आत्मदाह मामले में एएसपी के खिलाफ जांच के आदेश

● एडीसीपी को कारण बताओ नोटिस जारी, 15 दिन में देना होगा जवाब

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रदेश की घोसी लोकसभा से बसपा सांसद अतुल राय पर रेप का आरोप लगाने के बावजूद कोई कार्रवाई ना होने से क्षुब्ध होकर अपने साथी के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मदाह करने वाली युवती के मामले में अब पुलिस अफसरों पर कार्रवाई शुरू हो गई है।

इस मामले में वाराणसी के तत्कालीन एएसपी सिटी और एडीसीपी काशी जोन रहे विकास चंद्र त्रिपाठी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है। वहीं वाराणसी के तत्कालीन एडीसीपी वरुणा जोन विनय कुमार सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिन में स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया गया है। विकास चंद्र त्रिपाठी को पहले ही वाराणसी से हटाकर डीजीपी मुख्यालय से अटैच किया गया था।

आत्मदाह का प्रयास करने के पहले पीड़िता ने घोषी सांसद अतुल रायए पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुरए वाराणसी पुलिस समेत कई अन्य अधिकारियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का वीडियो वायरल कर दिया था। जिसके बाद शासन ने पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था।

मऊ की घोसी सीट से सांसद अतुल राय पर बलिया की रहने वाली युवती ने दुष्पर्कम का आरोप लगाया था। वाराणसी के लंका थाने में अतुल राय पर पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद सांसद अतुल राय ने भी पीड़िता और उसके मित्र के खिलाफ ब्लैकमेल कर वसूली करने का मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़ता के खिलाफ पुलिस ने न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट भी जारी करा लिया था।

जलशक्ति मंत्री ने अभियंता दिवस पर भारत रत्न विश्वश्वरैया की प्रतिमा का किया अनावरण

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

जलशक्ति मंत्री डॉ. महेन्द्र सिंह ने बुधवार को अभियंता दिवस के अवसर पर सिंचाई भवन के परिसर में स्थापित भारत रत्न, सर इं. मोक्षगुण्डम विश्वेश्वरैया की आदमकद प्रतिमा का अनावरण करते हुए राष्ट्र के प्रति उनके द्वारा किये गये योगदान का स्मरण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि देश के निर्माण में विश्वेश्वरैया का महान योगदान है, इसलिए उनकी सेवाओं का सम्मान करते हुए भारत सरकार ने उन्हें भारत रत्न और ब्रिटिश इण्डिया सरकार के दौरान नाइट हुड की उपाधि से सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि श्री विश्वेश्वरैया अभियंताओं के लिए सदैव प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे।

जलशक्ति मंत्री सिंचाई मुख्यालय के प्रांगण में अभियंता दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विश्वेश्वरैया जब तक जीवित थे, उन्होंने अपने जीवन के एक एक पल का सदुपयोग करते हुए राष्ट्र निर्माण में लगाया। अभियंता दिवस पर सभी अभियंताओं को संकल्प लेकर उनके पदचिन्हों पर चलते हुए यूपी को नम्बर एक प्रदेश बनाने के लिए कार्य करना चाहिए। विश्वेश्वरैया ने देश की विभिन्न योजनाओं को स्वरूप देने के साथ ही मैसूर एवं पटना के लिए जो कार्य किया वह आज भी मील का पत्थर है। उनकी सादगी, शालीनता, कर्मठता तथा समर्पण से प्रेरणा लेकर अभियंताओं को राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं को पूरा करना चाहिए। डॉ. महेन्द्र सिंह ने इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव सिंचाई टी.वेंकटेश, प्रमुख सचिव सिंचाई अनिल गर्ग, विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख अभियंता वीके निरंजन, प्रमुख अभियंता यांत्रिक देवेन्द्र अग्रवाल, प्रमुख अभियंता परिकल्प एवं नियोजन एके सिंह, विशेष सचिव सिंचाई मुश्ताक अहमद, मुख्य अभियंता डीके मिश्रा आदि अधिकारियों की सराहना की।

युवाओं को पौधरोपण कार्यक्रम से जोड़ने की जरूरत: दारा सिंह चौहान

● वन मंत्री ने जैवविविधिता दिवस के अवसर पर आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को किया पुरस्कृत

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

पर्यावरण, वन एवं जंतु उद्यान मंत्री दारा सिंह चौहान ने बुधवार को वृक्षारोपण जन आन्दोलन 2021 प्रतियोगिता एवं अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधिता दिवस 2021 के अवसर पर प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि सरकार द्वारा एक व्यक्ति एक वृक्ष का संकल्प लिया गया था, जिसमें प्रदेश में जनमानस की सहभागिता से एक दिन में 25 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को हरा भरा बनाने के लिए बच्चों में पर्यावरण संरक्षण का संस्कार विकसित करने और युवाओं को वृक्षारोपण कार्यक्रम में सक्रिय रुप से जोड़ने आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 हेतु पौधरोपण का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु अभी से तैयारियां शुरू कर दी जाये।

कार्यक्रम में मेरा पेड़ मेरा साथी वीडियो प्रतियोगिता में गोरखपुर के डॉक्टर विनय शंकर को प्रथम, झांसी के गौरव गर्ग को द्वितीय, वाराणसी की श्रृष्टि सिंह को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसी प्रकार मेरा घर मेरा बगीचा फोटो प्रतियोगिता में लखनऊ की रिचा दीक्षित प्रथम, झांसी की नीतू रविकुल द्वितीय, आगरा की अनीता अग्रवाल तृतीय स्थान पर रही। इनके अतिरिक्त मेरा शहर हरा भरा फोटो प्रतियोगिता में श्री धरम सुतानविन को प्रथम, लखनऊ की काव्या शुक्ला को द्वितीय, आगरा के डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा को तृतीय पुरस्कार मिला। साथ ही मेरा पेड़ मेरा साथी सेल्फी प्रतियोगिता में अलीगढ़ के प्रकाश सक्सेना को प्रथम, वाराणसी के महेश्वर नाथ त्रिपाठी को द्वितीय, अलीगढ़ के अब्दुल जलील सिद्दीकी को तृतीय, मेरा पेड़ मेरा साथी ड्राइंग प्रतियोगिता में ललितपुर के अचल सिंह को प्रथम, मुरादाबाद के तुषार गुप्ता को द्वितीय, वाराणसी की शिवांगी कश्यप को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। जैवविविधता उत्सव 2021 के अंतर्गत आयोजित जैव विविधता संरक्षण में हमारी भूमिका विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता में कक्षा चार से आठ वर्ग की श्रेणी में सेंट्रल अकादमी इंदिरा नगर लखनऊ की नवधा मुद्गल को प्रथम, नव्या सिंह को द्वितीय, अक्षय दयाल को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। कक्षा 9 से 12 वर्ग में सौम्य श्रीवास्तव को प्रथम, सुदीक्षा वर्मा को द्वितीय, यशर्थ राव को तृतीय पुरस्कार तथा स्नातक एवं परास्नातक वर्ग में वैभवी श्रीवास्तव को प्रथम, अनुष्का द्विवेदी को द्वितीय, लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रज्ञा तिवारी को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। पोस्टर प्रतियोगिता में कक्षा चार से 8 वर्ग तक में आगरा पब्लिक स्कूल की सजल जैन को प्रथम, सीएमएस लखनऊ की अनुदिता श्रीवास्तव को द्वितीय, अर्पित सिंह को तृतीय पुरस्कार, स्नातक एवं परास्नातक वर्ग में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के आकाश दीप को प्रथम, राजकुमार को द्वितीय तथा लखनऊ विश्वविद्यालय की अक्षरा सक्सेना को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसी प्रकार कोलाज प्रतियोगिता में कक्षा 4 से 8 वर्ष वर्ग की श्रेणी में सोनाक्षी उपाध्याय को प्रथम, सीएमएस की अनुष्का सिंह को द्वितीय, सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंदिरा नगर की हबीबा नदीम को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। कक्षा 9 से 12 वर्ग में आन्या गुप्ता को प्रथम, शांति पटेल को द्वितीय, रोशनी उपाध्याय को तृतीय पुरस्कार मिला। स्नातक एवं परास्नातक वर्ग में लखनऊ विश्वविद्यालय के आसिफ जाफरी को प्रथम, सहारनपुर की रसिका वत्स को द्वितीय तथा अभिषेक रस्तोगी को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ । इसी प्रकार स्लोगन प्रतियोगिता में कक्षा 4 से 8 वर्ग में आर्यन राजेंद्र जाधव को प्रथम पुरस्कारए कक्षा 9 से कक्षा 12 वर्ग में शक्ति सिंह को प्रथम, जान्हवी पंजवानी को द्वितीय, मानसी रंजन को तृतीय पुरस्कार, परास्नातक तथा स्नातक वर्ग में पूजा अग्रवाल को प्रथम तथा आसिफजाफरी को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।

इस अवसर पर प्रमुख सचिव वन, पर्यावरण एवं जंतु उद्यान विभाग मनोज कुमार सिंह ने कहा कि प्रत्येक वर्ष इन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इसका उद्देश्य पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में हो रहे बदलाव से होने वाले नुकसान को दूर करना है।

कांग्रेस के प्रशिक्षण से पराक्रम अभियान का दूसरा चरण शुरू

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रशिक्षण से पराक्रम अभियान के दूसरे चरण की शुरूआत हो गयी। 15 से 30 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत विभिन्न ज़िलों में 100 ट्रेनिंग कैंप आयोजित किये जाएंगे जिनमें 30 हज़ार कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी, प्रिंट मीडिया विभाग के संयोजक अशोक सिंह ने बताया कि देश पर छाये संकट और तमाम वैचारिक राजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए मुख्यालय स्तर पर विशेष ट्रेनिंग टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जो पूरे प्रदेश में लागातार प्रशिक्षण दे रही है। पहले चरण में हर ज़िला मुख्यालय पर प्रशिक्षण शिविर लगाये गये थे जिसमें लगभग 25 हजार कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कि गया था। 11 दिनों तक चले इस अभियान के सात मास्टर ट्रेनर टीमों के 40 सदस्यों ने यूपी के सभी जिलों में जिला और शहर कमेटियों के पदाधिकारियों के साथ साथ ब्लॉक अध्यक्षों, वार्ड अध्यक्षों और न्याय पंचायत अध्यक्षों को प्रशिक्षित किया था। अभियान का दूसरा चरण आज से विधानसभावार शुरू कर किया गया है। सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण से पराक्रम अभियानष् के चार चरणों में 700 प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से दो लाख पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है। प्रशिक्षण शिविरों में पांच विभिन्न विषयों पर ट्रेनिग दी जा रही है। कांग्रेस की विचारधारा, भाजपा व आरएसएस का सच और किसने बिगाड़ा उत्तर प्रदेश नाम से तीन अलग अलग कार्यशालाएं आयोजित हो रही हैं।

भाजपा अपनी साख खो चुकी है: अखिलेश

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा अपनी साख खो चुकी है। वह झूठ का प्रशिक्षण केन्द्र बन गई है। जनता से वादे करके भूल जाना भाजपा का चरित्र हो गया है। यह जनता को धोखा देना है। डॉ राममनोहर लोहिया मानते थे कि वादाखिलाफी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। इस हिसाब से भाजपा बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है जिसने अपने संकल्प पत्र में किए गए वादे भी भुला दिए हैं।

आखिर भाजपा अपने संकल्प पत्र को क्यों नहीं पूरा किया है, किसानों, नौजवानों के लिए जो वादे किए गए क्यों भुला दिए गए, किसान की न तो कर्जमाफी हुई, न उसे फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिला और न ही किसान की आय दुगनी हुई, गन्ना किसान आज भी अपने बकाया के लिए परेशान घूम रहा है। 10 हजार करोड़ रूपए से ज्यादा उसका बकाया हैं मिल मालिकों को ही भाजपा सरकार में राहत मिल रही है। गन्ना किसान को तो लागत मूल्य भी नहीं दिया जा रहा है। गन्ना बकाया का ब्याज क्यों नहीं दिया जा रहा है। नौजवान परेशान है उनसे 70 लाख नौकरियों का वादा किया गया वह सिर्फ वादा ही रहा है। प्रदेश में न नौकरियां हैं न नए उद्योग आ रहे हैं कि रोजगार पैदा हो। बल्कि जो उद्योग लगे हैंए वे भी बंद होने के कगार पर है। नौकरियां मांगने पर युवाओं पर लाठी पड़ती है। नोटबंदी, जीएसटी से व्यापार चौपट है। व्यापारी कर्ज में दब गए गए हैं। बुनकरों का धंधा चौपट है। भाजपा सरकार ने खुद तो एक यूनिट बिजली का उत्पादन किया नहीं, उपभोक्ताओं के लिए उसे मंहगी कर दिया। जन सामान्य पर पेट्रोल, डीजल के अलावा ईंधन गैस का भी बोझ लाद दिया है।

भाजपा सरकार विकास का झूठा भ्रमजाल फैला रही है। उसने शौचालय बनाएं जिनमें पानी की व्यवस्था नहीं है। उज्ज्वला योजना का लाभार्थी गरीब मंहगी ईंधन गैस कहां से खरीदेगा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली ध्वस्त है। स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है। कोरोना महामारी के संकट के बाद अब डेंग, मलेरिया के मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। बच्चे अकाल मृत्यु के शिकार हो रहे हैं। जिस भाजपा ने अपने संकल्प पत्र को कूड़े दान में फेंक दिया, जनता को उसे फिर क्यों समर्थन देना चाहिए, समाजवादी सरकार का काम पहले भी बोल रहा था, काम आगे भी बोलेगा।

बीजेपी किसान मोर्चा 18 को आयोजित करेगा सम्मेलन

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

किसानों के मसले पर विपक्ष को जवाब देने के लिए बीजेपी किसान मोर्चा ने 18 सितंबर को लखनऊ में स्मृति उपवन में किसान सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है। किसाना मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रदेश की योगी सरकार ने 2017 से जो निर्णय लिए हैं उससे किसानों का व्यापक हित हुआ है। किसान मोर्चा ने भी पूरे प्रदेश किसानों को सरकार की योजनाओं के बारे में बताया है। अगस्त में गन्ना बाहुल्य 95 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर 298 स्थानों पर भाजपा किसान मोर्चा द्वारा किसान संवाद स्थापित किया गया था। जिसमें लगभग 60 हजार किसानों की उपस्थिति दर्ज हुई थी। किसानों का पूरा समर्थन बीजेपी की सरकारों को है। देश के कुछ विरोधी दलों के लोग जो मुद्दों के अभाव में कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं कर पा रहे है वैसे ही लोग देश के किसानों को गुमराह करने का कुत्सित प्रयास कर रहे है। वह लोग अनर्गल दुष्प्रचार के माध्यम से पीएम मोदी को बदनाम करने का प्रयास कर रहे है। श्री सिंह ने बताया कि 17 सितम्बर को पीएम मोदी के जन्मदिवस पर किसान मोर्चा सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में सभी जिला केन्द्रों पर किसान-जवान-सम्मान दिवस के रूप में मनाएगा। इस दिन भाजपा किसान मोर्चा प्रत्येक जिला केन्द्रों पर 71 किसान व जवानों को सम्मानित करेगा। प्रदेश के किसान सरकार द्वारा किये गए कार्यों के प्रति आभार ज्ञापित करने के लिए किसान सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के समस्त विधानसभा क्षेत्रों से पचास-पचास किसान आएगें व लगभग 20 हजार किसान उपस्थित होकर समस्त प्रदेश के किसानों की तरफ से मुख्यमंत्री के प्रति आभार ज्ञापित करेंगे।

श्री सिंह ने बताया कि केन्द्रीय मंत्रि मण्डल ने 2022-23 में लिए रवी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य अभूतपूर्व वृद्धि की घोषणा कर दी है। जिसके अन्तर्गत गेहूं, सरसों, मसूर, चना, जौ और कुसुम के फूल के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में किसान की लागत के सापेक्ष 60 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है। मोदी-योगी के ऐतिहासिक निर्णय को लेकर किसान मोर्चा 18 सितम्बर को योगी जी को सम्मानित कर आभार ज्ञापित करेगें।

सड़कों की खराब हालत पर मायावती ने सरकार को घेरा

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

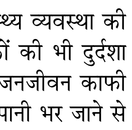

बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार पर हमला बोला है। इस बार उन्होंने खराब सड़कों की हालत पर सरकार को घेरा है। मायावती ने प्रदेश की सड़कों की खराब हालत और गड्ढों पर सरकार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने बुधवार को कहा कि यूपी की सड़कों की हालत फिर से इतनी ज्यादा खराब हो गई हैं कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सड़कों में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। बुधवार को ट्वीट करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने लिखा कि यूपी में कानून व स्वास्थ्य व्यवस्था की तरह ही यहाँ के सड़कों की भी दुर्दशा व ख़स्ताहाली से आमजनजीवन काफी बेहाल है तथा गड्ढों में पानी भर जाने से सड़क हादसों व इसमें होने वाली दर्दनाक मौतों की ख़बरों से अख़बार भरे पड़े हैं, यह अति.दुःखद।

संसद में सिर्फ राजनीति नहीं है, नीति भी है: मोदी

भाषा। नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि संसद में सिर्फ राजनीति नहीं होती है, बल्कि नीति भी होती है। साथ ही उन्होंने कंटेंट (विषय वस्तु) को कनेक्ट (संपर्क) करार दिया और कहा कि यह बात जितनी मीडिया पर लागू होती है, उतनी ही संसदीय व्यवस्था पर भी लागू होती है।

प्रधानमंत्री ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर बनाए गए संसद टीवी की शुरुआत के मौके पर यह बात कही। उन्होंने उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ संयुक्त रूप से संसद टीवी की शुरुआत की। अपने अनुभव का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मीडिया जगत में आम तौर पर कंटेंट सर्वोपरि होता है लेकिन उनके मुताबिक कन्टेंट इज कनेक्ट।

उन्होंने कहा कि यानी, जब आपके पास बेहतर कन्टेंट होगा तो लोग खुद ही आपके साथ जुड़ते जाते हैं। ए बात जितनी मीडिया पर लागू होती है, उतनी ही हमारी संसदीय व्यवस्था पर भी लागू होती हैड क्योंकि संसद में सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है, पॉलिसी भी है। वास्तव में पॉलिसी है।

संसद टीवी की शुरुआत को भारतीय संसदीय व्यवस्था में एक और महत्वपूर्ण अध्याय बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, आज देश को संसद टीवी के रूप में संचार और संवाद का एक ऐसा माध्यम मिल रहा है, जो देश के लोकतंत्र और जनप्रतिनिधियों की नई आवाज के रूप में काम करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि तेजी से बदलते समय में मीडिया और टीवी चैनलों की भूमिका भी बहुत तेजी से बदल रही है तथा 21वीं सदी तो विशेष रूप से संचार और संवाद के जरिए क्रांति ला रही है। उन्होंने कहा, ऐसे में स्वाभाविक हो जाता है कि संसद से जुड़े चैनल भी इन आधुनिक व्यवस्थाओं के हिसाब से खुद को बदलें। मुझे खुशी है कि संसद टीवी के तौर पर आज एक नई शुरुआत हो रही है। अपने नए अवतार में यह सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी रहेगा। इसका अपना एक एप भी होगा। अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब लोकतंत्र की बात होती है तो भारत की जिम्मेदारी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि भारत लोकतंत्र की जननी है।

उन्होंने कहा कि भारत के लिए लोकतंत्र केवल एक व्यवस्था नहीं है बल्कि एक विचार है। भारत में लोकतंत्र सिर्फ संवैधानिक ढांचा ही नहीं है बल्कि एक भावना है। भारत में लोकतंत्र संविधान की धाराओं का संग्रह ही नहीं है, यह तो हमारी जीवनधारा है।

इसलिए, अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के दिन संसद टीवी का लॉन्च होना अपने आप में बहुत प्रासंगिक हो जाता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने संसद और विधानसभाओं में लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप सार्थक चर्चा पर बल देते हुए कहा कि शोरगुल और व्यवधान में जनता की आवाज नहीं दबनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि चर्चाओं में चिंताओं का विवरण, आशंकाओं का निवारण और विषयों की गहरी जानकारी परिलक्षित होनी चाहिए।

नायडू ने कहा कि विधायिकाओं में चर्चा से समस्याओं का समाधान निकलता है लेकिन व्यवधान सामूहिक ऊर्जा की बर्बादी करता है और नए भारत के निर्माण के काम को प्रभावित करता है। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि भारत में मीडिया, खासकर टेलीविजन का विस्तार अद्भुत रहा है। नायडू ने कहा कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया के तेज विस्तार ने वास्तविक समय (रियल टाइम) में संवाद और सूचनाओं के आदान प्रदान में एक और आयाम जोड़ा है।

एससीओ शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई करेंगे मोदी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में 17 सितंबर को होने वाली शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की वार्षिक शिखर बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का डिजिटल माध्यम से नेतृत्व करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर एससीओ बैठकों के लिए दुशांबे जाएंगे। एससीओ की बैठकों में अफगान संकट, इसके आंतरिक और वाहरी असर पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने यह बताया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, एससीओ परिषद के सदस्य देशों के प्रमुखों की 21वीं बैठक हाइब्रिड प्रारूप में दुशांबे में 17 सितंबर को होगी। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे और वीडियो लिंक के जरिए शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे।

केंद्र सरकार ने सांसद अर्जुन सिंह का सुरक्षा घेरा बढ़ाकर जेड श्रेणी का किया

भाषा। नई दिल्ली (कोलकाता)

केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद अर्जुन सिंह के घर पर हाल में बम फेंकने की घटनाओं के मद्देनजर उन्हें मिली सुरक्षा का स्तर बढ़ाकर जेड श्रेणी का कर दिया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। पश्चिम बंगाल की बैरकपुर सीट से लोकसभा सदस्य 59 वर्षीय सिंह के उत्तर 24 परगना जिले में स्थित आवास पर हाल में बम फेंके गए थे।

अधिकारियों ने बताया कि सिंह को वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी लेकिन हाल में उनके और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ हिंसक घटनाओं को देखते हुए इसे बढ़ाकर जेड श्रेणी का कर दिया गया है। उनकी सुरक्षा का जिम्मा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के सशस्त्र कमांडो संभालेंगे। सिंह के घर पर कुछ बदमाशों ने बम फेंके थे जिसके कुछ दिन बाद ही मंगलवार सुबह उनके घर के बाहर इस तरह के धमाके फिर हुए। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस उनकी हत्या कराने की कोशिश कर रही है।

देश में कोविड-19 के 27,176 नए मामले

भाषा। नई दिल्ली

भारत में एक दिन में कोविड-19 के 27,176 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,33,16,755 हो गई। वहीं, 284 और लोगों की संक्रमण से मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 4,43,497 हो गई। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह आठ बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी कम होकर 3,51,087 हो गई है, जो कुल मामलों का 1.05 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में कुल 11,120 कमी दर्ज की गई। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 97.62 प्रतिशत है।

आंकड़ों के अनुसार, देश में अभी तक कुल 54,60,55,796 नमूनों की कोविड-19 संबंधी जांच की गई है, जिनमें से 16,10,829 नमूनों की जांच मंगलवार को की गई। दैनिक संक्रमण दर 1.69 प्रतिशत है, जो पिछले 16 दिन से तीन प्रतिशत से कम बनी है। वहीं, साप्ताहिक संक्रमण दर दो प्रतिशत है, जो पिछले 82 दिन से तीन प्रतिशत से कम है। देश में अभी तक कुल 3,25,22,171 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और कोविड-19 मृत्यु दर 1.33 प्रतिशत है। आंकड़ों के अनुसार, देश में अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की कुल 75.89 करोड़ खुराक दी जा चुकी हैं।

देश में पिछले साल सात अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और पांच सितंबर को 40 लाख से अधिक हो गई थी। वहीं, संक्रमण के कुल मामले 16 सितंबर को 50 लाख, 28 सितंबर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख और 20 नवंबर को 90 लाख के पार चले गए। देश में 19 दिसंबर को ए मामले एक करोड़ के पार, चार मई को दो करोड़ के पार और 23 जून को तीन करोड़ के पार चले गए थे।

मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देश में पिछले 24 घंटे में जिन 284 लोगों की संक्रमण से मौत हुई, उनमें से केरल के 129 और महाराष्ट्र के 52 लोग थे। देश में संक्रमण से अभी तक कुल 4,43,497 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है, जिनमें से महाराष्ट्र 1,38,221, कर्नाटक के 37,529 , तमिलनाडु के 35,217, दिल्ली के 25,083, उत्तर प्रदेश के 22,884, केरल के 22,779 और पश्चिम बंगाल के 18,599 लोग थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अभी तक जिन लोगों की मौत हुई है, उनमें से 70 प्रतिशत से ज्यादा मरीजों को अन्य बीमारियां भी थीं। मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि उसके आंकड़ों का भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के आंकड़ों के साथ मिलान किया जा रहा है।

जावेद ने फिर की तालिबान व आरएसएस की तुलना

भाषा। मुंबई

जाने-माने पटकथा लेखक एवं गीतकार जावेद अख्तर ने कहा है कि वह मुस्लिम पुरातनपंथियों के उतना ही विरोधी हैं जितना वह हिंदू चरमपंथियों के हैं। उन्होंने कहा कि अपनी इसी मुखरता के कारण उन्हें मुसलमानों से जान से मारने तक की धमकियां मिल चुकी हैं। जावेद अख्तर ने अपने उस हालिया साक्षात्कार का बचाव किया जिसमें उन्होंने तालिबान और हिंदू चरमपंथियों के बीच तुलना की थी। उन्होंने कहा कि हिंदू दुनिया में सबसे सभ्य और सहिष्णु लोग हैं, लेकिन जहां अफगानिस्तान में तालिबान को खुली छूट हासिल है, भारत में धर्मनिरपेक्षता उसके संविधान और अदालतों द्वारा संरक्षित है। उन्होंने यह विचार को जारी एक बयान में व्यक्त किए। उनहोंने हाल ही में एक टेलीविजन चैनल से कहा था कि तालिबान बर्बर हैं, वहीं भारत में हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों का समर्थन करने वाले भी उसी तरह हैं। उन्होंने ईमेल किए गए बयान में कहा, भारत कभी भी अफगानिस्तान जैसा नहीं बन सकता क्योंकि भारतीय, स्वभाव से

●कहा, मुस्लिम पुरातनपंथियों और हिंदू चरमपंथियों का विरोधी हूं

चरमपंथी नहीं हैं, उदारवादी होना उनके डीएनए में हैं। उन्होंने कहा कि हां, इस साक्षात्कार में मैंने संघ परिवार से जुड़े संगठनों के खिलाफ अपनी आपत्ति व्यक्त की था। मैं ऐसे किसी भी विचारधारा का विरोध करता हूं जो लोगों को धर्म, जाति और पंथ के आधार पर बांटता है और मैं उन सभी लोगों के साथ खड़ा हूं जो इस तरह के किसी भी भेदभाव के खिलाफ हैं। जाने माने पटकथा लेखक और गीतकार अख्तर ने कहा कि वह तालिबान और हिंदू दक्षिणपंथी की मानसिकता के बीच कई समानताएं पाते हैं। अख्तर ने कहा कि मेरे आलोचक भी इस बात से नाराज हैं कि मैं तालिबान और हिंदू दक्षिणपंथी मानसिकता के बीच बहुत सी समानताएं देखता हूं। वास्तव में, बहुत समानताएं हैं। तालिबान धर्म के आधार पर एक इस्लामी सरकार बना रहा है, हिंदू दक्षिणपंथी एक हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। उन्होंने कहा कि तालिबान महिलाओं के अधिकारों पर अंकुश लगाना चाहता है और उन्हें हाशिए पर रखना चाहता है, हिंदू दक्षिणपंथी ने भी यह स्पष्ट कर दिया है कि उसे महिलाओं और लड़कियों की स्वतंत्रता पसंद नहीं है। उत्तर प्रदेश, गुजरात से लेकर कर्नाटक तक एक रेस्तरां या बगीचे या किसी सार्वजनिक स्थान पर एक साथ बैठने पर युवक-युवतियों को बेरहमी से पीटा गया है।

आतंकवाद के शिकार कश्मीरी पंडितों की याद में स्मारक की नींव रखी गई

जम्मू (भाषा)। कश्मीरी पंडितों के एक समूह ने अपने समुदाय के उन सदस्यों की याद में यहां तवी नदी के तट पर एक स्मारक की आधारशिला रखी है जो पिछले तीन दशक के दौरान जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के शिकार बने। उन्होंने कहा कि सेना के युद्ध स्मारक की तरह बनने वाला 'शहीद स्मारकें जम्मू में सबसे बड़ा नागरिक स्मारक होगा। माता भद्रकाली स्थापन ट्रस्ट के अध्यक्ष दिलीप पंडित ने यहां संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के कारण घाटी से कश्मीरी हिंदुओं के पलायन के 31 साल पूरे होने पर माता भद्रकाली ट्रस्ट ने 1990 से आतंकवादियों द्वारा मारे गए कश्मीरी पंडितों की याद में पहले ऐसे स्मारक की नींव रखी है। उन्होंने कहा कि मंगलवार को नींव रखे जाने के साथ ही परियोजना पर काम शुरू कर दिया गया है। परियोजना के प्रभारी राज कुमार ने बताया कि यह तवी नदी के तट पर थलवाल में तीन एकड़ भूमि पर बन रहा है और स्मारक में मृतकों के नाम और तारीख का जिक्र किया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्मारक में समुदाय के उन सदस्यों के भी नाम होंगे जो 1947 में पहले भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद से मारे गए थे।कुमार ने कहा कि इसमें प्राचीन पांडुलिपियों और पुस्तकों, चित्रों सहित साहित्यिक विरासत को संरक्षित करने के लिए एक संग्रहालय और पुस्तकालय भी होगा।

THE PIONEER CLASSIFIEDS

CHANGE OF NAME

I, RITAMBHARA SINGH D/o Virendra Sengar R/o T-2,303, Parswanath Srishti Sec-93A, Noida Gautam Budh Nagar UP. 2010301 I have Changed my name from RITAMBHARA S to RITAMBHARA Singh for all future purposes.
PD(9078)C

पंजीकरण के लिए 736 अफगानों के नाम दर्ज

भाषा। नई दिल्ली

संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी यूएनएचसीआर ने यहां कहा कि एक अगस्त से 11 सितंबर तक कुल 736 अफगान नागरिकों के नाम नए पंजीकरण के लिए दर्ज किए गए। एजेंसी ने साथ ही कहा कि वह भारत में अफगान नागरिकों के पंजीकरण और सहायता के बढ़ते अनुरोधों को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता बढ़ा रही है।

संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने कहा कि वह वीजा जारी करने और अवधि बढ़ाने, सहायता और समाधान सहित अफगान नागरिकों से संबंधित मामलों पर सरकार के साथ लगातार सम्पर्क में है। आंकड़ों के अनुसार भारत में यूएनएचसीआर के लिए पर्सन्स ऑफ कन्सर्न की कुल संख्या 43,157 है। इनमें 15,559 शरणार्थी और शरण के इच्छुक लोग अफगानिस्तान के हैं। यूएनएचसीआर के लिए पर्सन्स ऑफ कन्सर्न का मतलब ऐसे व्यक्तियों से है जिन्हें

●24 घंटे सवालों के जवाब देने के लिए अतिरिक्त हेल्पलाइन की स्थापना

एजेंसी आंतरिक रूप से विस्थापित, शरण मांगने वाला, या बिना देश वाला व्यक्ति मानती है।संयुक्त राष्ट्र निकाय ने एक बयान में कहा, एक अगस्त से 11 सितंबर तक यूएनएचसीआर द्वारा नए पंजीकरण के लिए 736 अफगानों के नाम दर्ज किए गए हैं।

जिन लोगों ने यूएनएचसीआर से संपर्क किया है, उनमें वे अफगान शामिल हैं जो 2021 में आए हैं, जो पहले से वंद, शरण के मामलों को फिर से खोलने की मांग कर रहे हैं, छात्र, व्यवसाई, या चिकित्सीय या अन्य प्रकार के वीजा पर रह रहे हैं और जो अफगानिस्तान में वर्तमान स्थिति के कारण वापस जाने में असमर्थ हैं।

यूएनएचसीआर ने कहा कि वह भारत में अफगानों के पंजीकरण और सहायता के बढ़ते अनुरोधों को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। संयुक्त राष्ट्र निकाय ने कहा, यूएनएचसीआर अफगानिस्तान से आ रहे नए लोगों के वास्ते असुरक्षितों के लिए, मानवीय सहायता कार्यक्रम का दायरा बढ़ा रहा है। अफगानिस्तान से आ रहे सबसे असुरक्षित नए लोगों और भारत में पहले से रह रहे लोगों को भोजन, नकद आधारित सहायता जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जा रही है। यूएनएचसीआर ने कहा कि उसने एक अफगानिस्तान आपातकालीन प्रकोष्ठ और अफगान लोगों के लिए एक समर्पित सहायता इकाई भी स्थापित की है जिसमें पंजीकरण और सहायता के बारे में व्यापक जानकारी उपलब्ध है।

इसमें कहा गया है, 24 घंटे सवालों के जवाब देने के लिए अतिरिक्त हेल्पलाइन स्थापना की गई हैं और अफगान समुदायों के साथ सीधे जुड़ाव बढ़ाया गया है। प्रतिदिन 130 से अधिक कॉल प्राप्त होती हैं, मुख्य रूप से सहायता और पंजीकरण के बारे में पूछताछ की जाती है। यूएनएचसीआर ने कहा कि वह अपने साझेदारों, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों और वृहद दानकर्ता समुदाय से और सहायता की अपील कर रहा है ताकि भारत में रह रहे अफगानों की मदद के लिए बढ़ती जरूरतों और सहायता को पूरा किया जा सके।

एजेंसी ने कहा कि तत्काल छह हजार लोगों को भोजन संबंधी सहायता, तीन हजार महिलाओं और लड़कियों को सैनिटरी वस्तुओं की सहायता, 500 अति असुरक्षित लोगों को नकद सहायता और करीब 1000 अति असुरक्षित लोगों को सर्दियों में रहने के लिए सहायता की जरूरत है। तालिबान ने इस महीने पूरे अफगानिस्तान पर नियंत्रण कर लिया। भारत ने पिछले महीने ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत भारतीय वायुसेना के सैन्य परिवहन विमानों के जरिए लोगों को निकाला है।

नई दिल्ली में महिला कांग्रेस के 38वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शिरकत करते राहुल गांधी

गगनयान को 2023 में अंतरिक्ष में भेजे जाने की संभावना

नई दिल्ली। भारत के गगनयान अभियान को 2022 तक या 2023 की शुरुआत में अंतरिक्ष में भेजे जाने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को यह जानकारी दी।

यह अभियान मूल रूप से 2022 के अंत तक भेजे जाने का कार्यक्रम था, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के चलते इसमें देर हुई है। इसका लक्ष्य पृथ्वी की निचली कक्षा में मानव युक्त अभियान (अंतरिक्ष यात्री) भेजना है। उन्होंने कहा कि हम इसे असल में 2022 तक कर सकते हैं। हमने भारत की स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ के साथ इसे करने की योजना बनाई थी, लेकिन कोविड-19 के कारण इसमें देर होने से ऐसा नहीं हो सकेगा।

मंत्री ने कहा कि लेकिन मैं आश्वस्त हूं कि अगले साल के अंत तक या 2023 की शुरूआत में, हम इसे बखूबी कर सकेंगे। अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री ने फ्यूचर ऑफ इंडिया-ओसियानिया स्पेस टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर आयोजित एक वेबिनार को संबोधित करते हुए यह कहा। इसका आयोजन यहां फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री (फिक्की) ने किया था। उन्होंने कहा कि अंतरिक्षण प्रौद्योगिकी ने हर क्षेत्र में भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि यह आपदा प्रबंधन में मददगार है।

कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन करने जातीं अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी

वैज्ञानिकों ने ओडिशा के काले बाघों के रहस्य से उठाया पर्दा

भाषा। नई दिल्ली

ओडिशा के सिमलिपाल में काले बाघों के पीछे के रहस्य से पर्दा उठ सकता है। अनुसंधानकर्ताओं ने एक जीन में ऐसे परिवर्तन की पहचान की है जिससे उनके शरीर पर विशिष्ट धारियां चौड़ी हो जाती हैं और पीले रंग की खाल तक फैल जाती है जिससे कई बार वे पूरे तरह काले नजर आते हैं। सदियों से पौराणिक माने जाने वाले काले बाघ लंबे समय से आकर्षण का केंद्र रहे हैं। राष्ट्रीय जीव विज्ञान केंद्र में परिस्थिति वैज्ञानिक उमा रामकृष्णन और उनके छात्र विनय सागर, बेंगलूरू ने बाघ की खाल के रंगों और प्रवृत्तियों का पता लगाया है जिससे ट्रांसमेम्ब्रेन एमिनोपेप्टाइड्स क्यू (टैक्पेप) नामक जीन में एक परिवर्तन से बाघ काला नजर आता है। एनसीबीएस में प्रोफेसर रामकृष्णन ने पीटीआई-भाषा को बताया, इस फेनोटाइप के लिए जीन के आधार का पता लगाने का यह हमारा पहला और इकलौता अध्ययन है। चूंकि फेनोटाइप के बारे में पहले भी बात की गई और लिखा गया है तो यह पहली बार है जब उसके जीन के आधार की वैज्ञानिक रूप से जांच की गई है। अनुसंधानकर्ताओं ने यह दिखाने के लिए भारत की अन्य बाघ आबादी की जीन का विश्लेषण और कम्प्यूटर अनुरूपण के आंकड़े एकत्रित किए कि सिमलिपाल के काले बाघ बाघों की बहुत कम आबादी से बढ़ सकते हैं और जन्मजात होते हैं।

मुंबई : बार्क के वैज्ञानिक ने परिसर में फंदे से लटककर आत्महत्या की

मुंबई। मुंबई के मानखुर्द में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के एक वैज्ञानिक ने परिसर के अंदर हीलियम संयंत्र में फंदे से लटककर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। ट्रॉम्बे पुलिस थाना के एक अधिकारी ने बताया कि तकनीकी भौतिकी विभाग के वैज्ञानिक अधिकारी जी चम्पालाल प्रजापति (44) ने शुक्रवार को आत्महत्या कर ली।

अधिकारी ने बताया कि वह राजस्थान के सुजानगढ़ के रहने वाले थे और सुपरकंडक्टर्स में विशेषज्ञता रखते थे। घटना के दिन उनकी पत्नी ने समय से घर नहीं पहुंचने पर उनके सहयोगियों को फोन किया, जिन्होंने कुछ समय बाद वैज्ञानिक को फंदे से लटका पाया।

PUBLIC NOTICE

My Client Fakir Chand S/O Raiyat Singh R/o H.No- A -276,Gymkhana Club, Gotampuri, Badarpur, New Delhi – 110044 has disowned his daughter Pooja from all his Movable and immovable properties due to her bad behaviour, any one dealing with her at his own risk and consequences

Akhil Rexwal (Advocate)
D/5021/ 2017
J- 9, Ayush Enclave, Badarpur, New Delhi – 110044
Phone: 9540737777

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है की मेरा पक्षकार रामबाबू तिवारी, मकान नं. 254, खेवत नं. 108, खतौनी नं. 126 मिन, मुस्ततील नंबर 21, किला नं. 2 और 3, सूर्य विहार, पार्ट - II, गली नं 4, सेहतपुर, फरीदाबाद को अखिलेश कुमार से खरीदने जा रहे है तथा डी एम आइ हाउसिंग फाइनान्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ बंधक रख रहे है. तथा अखिलेश कुमार ने उक्त संपत्ति जी पी ए नं 7039 दिनांक 28.06.2021 से खरीदी थी, जो की गाजियाबाद उ.प. मे पंजीकृत है जबकि संपत्ति हरयाणा की है, यदि उक्त दस्तावेजो पर किसी प्रकार की कोई भी इकरार, बिक्री, बंधक आदि सिवाय रामबाबू तिवारी अखिलेश कुमार और उक्त संस्था के बीच, मान्या नही होगा. अगर कोई व्यक्ति उक्त संपति मे किसी प्रकार का अधिकार या दावा करना चाहता है तो वह नीचे लिखे न . पर इस प्रकाशन के 8 दिन के अंदर संपर्क कर अपने अधिकार या आपत्ति की जानकारी दे दे

एडरेंम लिगल सल्यूशन
चेंबर न. ७६०, द्वारका कोर्ट,
सेक्टर-१०, द्वारका, नई देल्ही.-७५.
म:- ९८९९०१३९१८

PUBLIC NOTICE

General public is hereby informed that Jugal Kishore Khurana son of late Sita Ram Khurana has retired from the Partnership Firm M/s Venus Industries, registered office at WZ-1, Basai, Najafgarh Road, New Delhi -110015, from 31 August 2020. The firm or its continuing partners, Parveen Khurana and Seema Khurana, shall not be held responsible for any of his dealing on behalf of the firm or if any member of public deals with him for firm's business from that date. He has transferred his entire share in the partnership to continuing partners on the date of his retirement.

For Venus Industries
sd/- Authorised Signatory

Lost & Found

Notice here by given Tejpal Singh Kohli S/o Kulbir Singh Kohli R/o L-7 Rajouri Garden, New Delhi-27,a member of The Panchsheel Cooperative House Building Society office at House no.107, Telephone exchange colony Zirakpur Distt Mohali Punjab membership no.7, Plot no. 84 The Panchsheel Cooperative House Building Society Ltd Ajitgarh, Distt Mohali Punjab declare that I have lost original receipts Rs 3000 and Rs 5110 and share certificate in my favour and I have applied for duplicate share certificate, receipt of payment and allotment letter. If anyone have objection please contact within 15 days to secretary of the society.

सेंसेक्स, निफ्टी का नया रिकॉर्ड

● दूरसंचार, वाहन कंपनियों के शेयरों में जबर्दस्त लिवाली

भाषा। मुंबई

दूरसंचार और वाहन कंपनियों के शेयरों में जबर्दस्त लिवाली के बीच बुधवार को सेंसेक्स 476 अंक की छलांग के साथ अपने नए सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गया। सरकार ने दूरसंचार और वाहन उद्योग के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है जिससे इन क्षेत्रों की कंपनियों में निवेशकों ने जमकर खरीदारी की। कारोबारियों ने कहा कि इसके अलावा रुपए में मजबूती तथा विदेशी कोषों के सतत प्रवाह से भी बाजार धारणा मजबूत हुई।

बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 476.11 अंक यानी 0.82 प्रतिशत के लाभ के साथ 58,723.20 अंक पर बंद हुआ। यह इसका नया रिकॉर्ड है। दिन में कारोबार के दौरान सेंसेक्स ने 58,777.06 अंक के अपने नए सर्वकालिक उच्चस्तर को भी छुआ। सेंसेक्स में लगातार दूसरे दिन तेजी आई। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 139.45 अंक या 0.80 प्रतिशत की बढ़त के साथ 17,519.45 अंक पर पहुंच गया। निफ्टी का भी यह नया रिकॉर्ड है। दिन में कारोबार के दौरान निफ्टी 17,532.70 अंक के अपने सर्वकालिक उच्चस्तर तक गया। सेंसेक्स की कंपनियों में एनटीपीसी का शेयर सबसे अधिक 7.16 प्रतिशत चढ़ गया। भारती एयरटेल के शेयर में 4.53 प्रतिशत का लाभ रहा। एचसीएल टेक, टाइटन, एसबीआई, पावरग्रिड, टीसीएस इंडसइंड बैंक के शेयर भी लाभ में रहे। वहीं दूसरी ओर एक्सिस बैंक, एशियन पेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, नेस्ले इंडिया, सनफार्मा और एचडीएफसी बैंक के शेयर 0.38 प्रतिशत तक टूट गए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को दूरसंचार क्षेत्र के लिए राहत पैकेज को मंजूरी दी। इसके तहत दूरसंचार कंपनियों पर सांविधिक बकाए के भुगतान की चार साल की छूट दी गई है। इसके अलावा क्षेत्र में स्वत: मंजूर मार्ग से 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। साथ ही मंत्रिमंडल ने वाहन, वाहन कलपुर्जा क्षेत्र और ड्रोन उद्योग के लिए 26,058 करोड़ रुपए की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को भी मंजूरी दी है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के मुख्य निवेश रणनीतिकार वी के विजयकुमार ने कहा, दूरसंचार और वाहन उद्योग के लिए जिन उपायों की घोषणा की गई है उनका व्यापक लाभ मिलेगा। दूरसंचार क्षेत्र को एजीआर, स्पेक्ट्रम बकाया और ब्याज भुगतान के लिए चार साल की मोहलत दी गई है। इससे नकदी संकट से जूझ रहे क्षेत्र को काफी राहत मिलेगी। यह बैंकों की दृष्टि से भी सकारात्मक है। बैंकों का भी इन कंपनियों को ऋण में उल्लेखनीय कमी आएगी। बीएसई मिडकैप और स्मॉलकैप 0.86 प्रतिशत तक चढ़ गए। अन्य एशियाई बाजारों में चीन के शंघाई कम्पोजिट, जापान के निक्की तथा हांगकांग के हैंगसेंग में नुकसान रहा। वहीं दक्षिण कोरिया का कॉस्पी लाभ में रहा। दोपहर के कारोबार में यूरोपीय बाजारों में मिलाजुला रुख था। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट कच्चा तेल 1.05 प्रतिशत की बढ़त के साथ 74.37 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 18 पैसे की बढ़त के साथ 73.50 प्रति डॉलर पर बंद हुआ।

टॉप गेनर		टॉप लूजर	
एनटीपीसी	7.16	एक्सिस बैंक	-0.38
भारती एयरटेल	4.53	एशियन पेन्ट्स	-0.31
एचसीएल टेक	2.86	अल्ट्रा टेक सीमेन्ट	-0.27
टाइटन	2.83	नेस्ले	-0.16
स्टेट बैंक	2.49	सन फार्मा	-0.15

पीटीआई ग्राफिक

टॉप गेनर		टॉप लूजर	
एनटीपीसी	7.46	Tata Consumer	-0.95
भारती एयरटेल	4.80	नेस्ले	-0.55
कोल इंडिया	3.98	ग्रासिम	-0.49
ओएनजीसी	3.87	बीपीसीएल	-0.38
टाइटन	3.03	एशियन पेन्ट्स	-0.37

एनसीएलएटी के कार्यकारी अध्यक्ष की जल्दबाजी में नियुक्ति पर नाखुशी जताई

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति एम वेणुगोपाल की नियुक्ति में जल्दबाजी पर नाराजगी जताई। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि बृहस्पतिवार को इस मुद्दे पर सुनवाई होगी और अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल से इस मुद्दे पर जवाब देने के लिए भी कहा। पीठ में न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव भी शामिल हैं। पीठ ने वेणुगोपाल से कहा, हम आपको कल पेश होने के लिए पहले से बता रहे हैं, यह मामला एनसीएलएटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति चीमा की समयपूर्व सेवानिवृत्ति के बारे में है। ऐसा लगता है कि उन्हें हटा दिया गया है। इसमें कहा गया है कि एनसीएलएटी के अध्यक्ष श्री चीमा की सेवानिवृत्ति से 10 दिन पहले श्री वेणुगोपाल को नियुक्त किया गया। हमें नहीं पता कि यह कैसे हो रहा है। केंद्र ने शनिवार को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण में आठ न्यायिक सदस्यों और 10 तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

पिछली तारीख से कराधान खत्म करने से सरकार और उद्योग के बीच भरोसा बढ़ा: राजनाथ सिंह

भाषा। नई दिल्ली

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा कि पिछली तारीख से कराधान व्यवस्था को खत्म करने के बाद सरकार और उद्योग के बीच भरोसा बढ़ा है। एक प्रमुख उद्योग मंडल द्वारा आयोजित भारत-अमेरिका आर्थिक शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए सिंह ने आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार द्वारा किए गए कई फैसलों का जिक्र किया और कहा कि वैश्विक निवेशकों का अब भारत में लालफीताशाही की जगह लाल कालीन से स्वागत हो रहा है। उन्होंने कहा, हमने प्रगतिशील और निवेशकों के अनुकूल कर नीतियां तैयार की हैं। हमने पिछली तारीख से कराधान को विदा कर दिया है। सिंह ने कहा, पिछली तारीख से कराधान को खत्म करने के बाद सरकार और उद्योग के बीच भरोसा बढ़ा है। ऐसा करके हमने पिछली सरकार (संप्रग) की गलती को सुधारा है। उन्होंने कहा कि सरकार इस पूरे दशक में गतिशील वृद्धि की तैयारी कर रही है और अमेरिकी तथा भारतीय रक्षा फर्मों के बीच सैन्य उपकरणों के साझा-उत्पादन और साझा-विकास की बहुत गुंजाइश है। रक्षा मंत्री ने कहा, कोरोना वायरस महामारी ने आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान, औद्योगिक गतिविधियों में मंदी, यात्रा और पर्यटन उद्योग में नकारात्मक वृद्धि के मामले में नई चुनौतियां पेश की हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है कि सामान्य स्थिति को बहाल करने और आगे का सफर तय करने में भारत-अमेरिका सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। भारत-अमेरिका चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित शिखर सम्मेलन में प्रमुख अमेरिकी रक्षा कंपनियों के कई शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया।

एप्पल 24 सितंबर से भारत में आईफोन 13 की पेशकश करेगी, कीमत 69,900 रुपए से शुरू

नई दिल्ली। भारत में प्रीमियम मोबाइल फोन एप्पल के दीवाने 24 सितंबर से आईफोन 13, आईफोन 13 मिनी, आईफोन 13 प्रो और आईफोन 13 प्रो मैक्स हासिल कर सकेंगे, जिनकी शुरुआती कीमत 69,900 रुपए से शुरू है। एप्पल ने एक बयान में कहा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, जर्मनी, भारत, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और 30 से अधिक अन्य देशों तथा क्षेत्रों के ग्राहक आईफोन 13 प्रो और आईफोन 13 प्रो मैक्स का प्री-ऑर्डर दे सकते हैं, जिसकी आपूर्ति 24 सितंबर शुक्रवार से शुरू होगी। एप्पल ने कहा कि ग्राहक आईफोन 13 प्रो को I,19,900 रुपए (से लेकर) में और आईफोन 13 प्रो मैक्स को I,29,900 रुपए (से लेकर) में ऐपल के ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हैं। आईफोन 13 की कीमत 79,900 रुपए और आईफोन 13 मिनी की कीमत 69,900 रुपए है।

अगस्त में खाद्य तेलों का आयात 22 प्रतिशत घटकर 10.16 लाख टन हुआ

भाषा। नई दिल्ली

भारत का खाद्य तेल आयात अगस्त में 22 प्रतिशत घटकर 10,16,370 टन रह गया। आयात घटने का मुख्य कारण इस साल जून-जुलाई में हुए अधिक स्टॉक के बचे अधिशेष स्टॉक के साथ-साथ खाद्यतेलों की खुदरा कीमतों में उछाल के कारण उपभोक्ता मांग का कम होना था। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एसईए) ने एक बयान में कहा कि अखाद्य तेल का आयात भी अगस्त में घटकर 37,440 टन रह गया, जो पिछले साल इसी महीने में 62,052 टन का हुआ था।

अगस्त, 2021 के दौरान वनस्पति तेलों (खाद्य और अखाद्य तेलों) का आयात 10,53,810 टन रहा, जो पिछले साल इसी महीने में 13,70,457 टन था, जो 23 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है। संपर्क करने पर, एसईए के कार्यकारी निदेशक बी वी मेहता ने कहा, जून और जुलाई में अधिक आयात के कारण अगस्त में आयात में गिरावट आई है। अतिरिक्त स्टॉक की खपत हो गई है। इसके अलावा खाद्य तेलों की उंची कीमतों के कारण मांग में कमी आई है। अक्टूबर को समाप्त होने वाले तेल विपणन वर्ष 2020-21 के पहले 10 महीनों के दौरान खाद्य तेल का आयात पिछले वर्ष की इसी अवधि में 109,06,259 टन से गिरकर 103,86,517 टन रह गया। अखाद्य तेल का आयात 2,89,631 टन से बढ़कर 3,21,929 टन हो गया। नवंबर, 2020 से अगस्त, 2021 के दौरान वनस्पति तेलों (खाद्य और अखाद्य तेल दोनों शामिल) का कुल आयात I,07,08,446 टन रहा, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में I,11,95,890 टन के कुल आयात से चार प्रतिशत कम है।

पश्चिम बंगाल में मालदा जिले के गाजोल में 'दुआरे राशन' सरकारी योजना के तहत राशन लेते लाभार्थी

क्विक न्यूज

वित्त मंत्रालय का आईबीए से अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान में अहम भूमिका निभाने का आह्वान

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को भारतीय बैंक संघ (आईबीए) से भारत की आजादी के 75वें वर्ष में अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान में अहम भूमिका निभाने का आह्वान किया। वित्तीय सेवा सचिव देवाशीष पांडा ने कहा, इस समय मै आईबीए के अध्यक्ष से पूंजीकरण के लिए अच्छे सक्षम संसाधनों और प्रौद्योगिकी को अपनाने की अपील करूंगा। आईबीए केवल एक संघ नही होना चाहिए जो रिजर्व बैंक के पास बैंकिंग से जुड़े मुद्दे भेजता है, बल्कि उसे वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सुधारों के साथ एकीकरण की भी कोशिश करनी चाहिए। सचिव ने आईबीए के दिल्ली कार्यालय का उद्घाटन करते हुए सुझाव दिया कि वह मध्यम प्रबंधन वाले बैंकिंग पेशेवरों को प्रशिक्षण और कौशल प्रदान करने पर भी विचार कर सकता है ताकि बैंकों का एक ही काम से जुड़ा बोझ कम किया जा सके। उन्होंने कहा, आईबीए की अनुसंधान और बैंकिंग से जुड़े प्रमुख मुद्दों के लिहाज से एक अहम भूमिका है और उसे भारत की आजादी के 75वें वर्ष में अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।

2021-22 की पहली तिमाही में घरेलू ऋण घटकर 34 प्रतिशत रह सकता है: एसबीआई रिपोर्ट

मुंबई। भारतीय स्टेट बैंक की शोध रिपोर्ट इकोरैप के एक अनुमान के मुताबिक 2021-22 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में घरेलू ऋण घटकर 34 प्रतिशत रह सकता है। कोविड-19 महामारी के चलते घरेलू ऋण - जीडीपी दर अनुपात बढ़ गया है। बुधवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार यह 2020-21 में तेजी से बढ़कर 37.3 प्रतिशत हो गया, जो 2019-20 में 32.5 प्रतिशत था। शोध रिपोर्ट में कहा गया है, हमारा अनुमान है कि वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में घरेलू ऋण पहली तिमाही में घटकर 34 प्रतिशत रह गया है, हालांकि निरपेक्ष रूप से यह बढ़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक निरपेक्ष रूप से वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में घरेलू ऋण बढ़कर 75 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो 2020-21 की पहली तिमाही में 73.59 लाख करोड़ रुपए था। हाल में 2018 के लिए जारी भारत ऋण और निवेश सर्वेक्षण (एआईडीआईएस) रिपोर्ट में कहा गया कि 2012 से 2018 के बीच ग्रामीण और शहरी परिवारों का कर्ज बढ़ा।

मंत्रिमंडल ने दूरसंचार क्षेत्र में बड़े सुधारों को मंजूरी दी, 100 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति

नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को दूरसंचार क्षेत्र में बड़े सुधारों की घोषणा की। इसके तहत दूरसंचार क्षेत्र के लिए राहत पैकेज को मंजूरी देने के साथ स्वतः मंजूर मार्ग से 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति दी गई है। राहत पैकेज में दूरसंचार कंपनियों के ऊपर सांविधिक बकाए के भुगतान पर चार साल के लिए रोक यानी मोहलत दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद निर्णय की जानकारी देते हुए दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि दूरसंचार क्षेत्र के लिए नौ संरचनात्मक सुधारों को मंजूरी दी गई है। सकल समायोजित राजस्व (एजीआर) की परिभाषा को युक्तिसंगत बनाते हुए इसमें से दूरसंचार क्षेत्र से इतर होने वाली आय को हटा दिया गया है। दूरसंचार क्षेत्र में दबाव का एक प्रमुख कारण एजीआर का मुद्दा था। मंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल ने स्वतः मंजूर मार्ग से 100 प्रतिशत एफडीआई की भी अनुमति दी है।

मास्टरकार्ड प्रतिबंध: आरबीएल बैंक ने वीजा के साथ क्रेडिट कार्ड जारी करना शुरू किया

मुंबई। अमेरिकी भुगतान कंपनी मास्टरकार्ड पर नियामक प्रतिबंध लगने के दो महीने बाद निजी क्षेत्र के ऋणदाता आरबीएल बैंक ने बुधवार को प्रतिद्वंद्वी वीजा के भुगतान नेटवर्क पर क्रेडिट कार्ड जारी करना फिर से शुरू कर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस साल 14 जुलाई को डेटा स्थानीयकरण संबंधी आवश्यकताओं का पालन नही करने पर मास्टरकार्ड को कोई भी नया कार्ड जारी करने से प्रतिबंधित कर दिया था। इस कदम से आरबीएल बैंक सहित कई उधारदाताओं को झटका लगा था, जो अपने क्रेडिट कार्ड व्यवसाय के लिए पूरी तरह से अमेरिकी भुगतान कंपनी पर निर्भर थे। आरबीएल बैंक ने कहा कि उसने 14 जुलाई को ही वीज़ा के साथ साझेदारी की थी और फिर से नए कार्ड जारी करने के लिए रिकॉर्ड समय में प्रौद्योगिकी एकीकरण किया।

रत्न, आभूषण क्षेत्र में सुधारों से 43.75 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य हासिल हो सकेगा: अनुप्रिया पटेल

नई दिल्ली। रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए सुधारों से चालू वित्त वर्ष 2021-22 में क्षेत्र का 43.75 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य हासिल हो सकेगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने बुधवार को यह बात कही। पटेल ने कहा कि क्षेत्र के लिए कई सुधार मसलन पुनगर्ठित स्वर्ण मौद्रिकरण योजना, सोने पर आयात शुल्क की कटौती तथा हॉलमार्किंग आदि लागू किए गए हैं, जिससे क्षेत्र का निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी।

देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में रत्न एवं आभूषण क्षेत्र का हिस्सा सात प्रतिशत है। वहीं देश के वस्तुओं के निर्यात में क्षेत्र की हिस्सेदारी 10 से 12 प्रतिशत की है। पटेल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में रत्न एवं आभूषणों का निर्यात 9.2 अरब डॉलर रहा है। उन्होंने कहा कि नीतिगत मोर्चे पर सरकार ने कई कदम उठाए हैं। स्वर्ण मौद्रिकरण योजना का पुनर्गठन किया गया है, सोने पर आयात शुल्क घटाया गया है तथा हॉलमार्किंग प्रणाली को लागू किया गया है। इससे उद्योग को अगले स्तर पर पहुंचने में मदद मिलेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि इन उपायों से न केवल उद्योग को बदलाव लाने में मदद मिलेगी बल्कि इससे निर्यात भी बढ़ेगा। पटेल ने कहा कि इन उपायों से उद्योग चालू वित्त वर्ष में 43.75 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य हासिल कर सकेगा। इसके अलावा वह आगामी वर्षों में रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्द्धन परिषद (जीजेईपीसी) के 75 अरब डॉलर के निर्यात लक्ष्य पर भी पहुंच पाएगा।

केयर्न, एयर इंडिया की न्यूयॉर्क की अदालत से कार्यवाही पर रोक लगाने अपील

भाषा। नई दिल्ली

केयर्न एनर्जी और एयर इंडिया ने संयुक्त रूप से न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत से ब्रिटिश कंपनी द्वारा अमेरिका में दायर मुकदमे में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने की अपील की है। इस मुकदमे में भारत सरकार के खिलाफ 1.2 अरब डॉलर के मध्यस्थता न्यायाधिकरण के आदेश को लागू करने के लिए एयरलाइन की संपत्ति जब्त करने की अपील की गई है। अदालती दस्तावेजों के अनुसार यह कदम सरकार द्वारा देश में पिछली तारीख से कराधान को समाप्त करने के लिए एक कानून बनाने के बाद उठाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप केयर्न पर 10,247 करोड़ रुपए की कर मांग वापस ले ली जाएगी।

गौरतलब है कि भारत सरकार ने 2012 के पिछली तिथि से कर लगाने संबंधी कानून के तहत केयर्न एनर्जी पर 10,247 करोड़ रुपए का कर लगाया था। ब्रिटिश ऊर्जा कंपनी ने फैसले को सिंगापुर के अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण में चुनौती दी जिसने पिछले साल दिसंबर में सरकार के कदम को गलत करार दिया और उसे कंपनी को पूरी राशि लौटाने का आदेश दिया। भारत के इस राशि का भुगतान न करने पर कंपनी ने अमेरिकी अदालतों का रुख किया। लेकिन भारत की संसद ने पिछले महीने एक संशोधित कानून पारित कर 2012 के पूर्व तिथि से कर लगाने संबंधी कानून के प्रावधान को निरस्त कर दिया। इस कानून के तहत सरकार को 50 साल पुराने मामले में भी कर लगाने का अधिकार दिया गया था। साथ ही सरकार केयर्न से जब्त किए गए 7,900 करोड़ रुपए लौटाने पर भी सहमत हो गई है। केयर्न ने संकेत दिया कि ब्याज और जुर्माने के बगैर किया जाने वाला रिफंड उसे मंजूर है। इस तरह से दोनों पक्षों के बीच सात साल से जारी विवाद का हल निकलता दिख रहा है। केयर्न और एयर इंडिया ने 13 सितंबर को अमेरिकी जिला न्यायाधीश पॉल गार्डेफे से एक संयुक्त अनुरोध में कहा कि कार्यवाही पर रोक से उन्हें पिछली तारीख से कर को निरस्त करने वाले कानून के प्रभावों और निहितार्थों का मूल्यांकन करने के लिए अतिरिक्त समयै मिलेगा। 7,900 करोड़ रुपए के रिफंड के बदले में केयर्न वे मुकदमे वापस ले लेगी जिनमें अदालत के आदेश पर विदेशों में स्थित भारत सरकार की संपत्तियों को जब्त करने की धमकी दी गई थी। केयर्न के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) साइमन थॉमसन ने इस महीने की शुरुआत में पीटीआई-भाषा से कहा था कि कंपनी को पिछली तारीख से कर मांग के प्रवर्तन के तहत जब्त राशि को लौटाने के बदले भारत सरकार के खिलाफ सभी मुकद्दमे वापस लेने की पेशकश मंजूर है।

सिंगापुर संसद ने भारत के साथ एफटीए के तहत रोजगार पर विपक्ष के प्रस्ताव को खारिज किया

सिंगापुर। सिंगापुर की संसद ने बुधवार को एक प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जिसमें भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की बात कही गई थी। इस प्रस्ताव का विरोध करने वालों ने आरोप लगाया कि इसके जरिए भारतीय पेशेवरों द्वारा देश के घरेलू कामगारों के रोजगार को छीनने का रास्ता खुल जाएगा। समाचार चैनल न्यूज एशिया की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार दोपहर को शुरू हुई और आधी रात तक चली एक बहस के बाद 2005 के सिंगापुर-भारत व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (सीईसीए) को संसद ने खारिज कर दिया। सत्तारूढ़ पीपुल्स एक्शन पार्टी (पीएपी) के पूर्ण बहुमत वाली संसद ने सिंगापुर के लोगों की नौकरी और आजीविका सुरक्षित करने वाले एक प्रस्ताव को भी पारित किया। विपक्षी प्रोग्रेस सिंगापुर पार्टी (पीएसपी) ने भारत के साथ सीईसीए का बार-बार जिक्र किया है कि कैसे सिंगापुर के लोग विदेशियों से हार गए हैं।

पेज एक का शेष

दिल्ली में...

पटाखों के भंडारण के बाद प्रदूषण की गंभीरता को देखत हुए देर से प्रतिबंध लगाया गया, जिससे व्यापारियों का भारी नुकसान हुआ था। इस साल सभी व्यापारियों से अनुरोध है कि वे इस बार पूर्ण प्रतिबंध को देखते हुए किसी भी तरह का भंडारण न करें। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार प्रदूषण को काबू करने को लेकर बेहद गंभीर है। आबोहवा दुरुस्त करने के मकसद से सरकार 10 बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसी के मद्देनजर विंटर एक्शन प्लान बना रही है। आने वाले दिनों में विंटर एक्शन प्लान के अनुसार विभिन्न गतिविधियों की जाएंगी, ताकि प्रदूषण पर काबू पाया जा सके। उन्होंने दिल्ली वालों से अपील करते हुए कहा कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सभी को जिम्मेदारी लेनी होगी। एनजीटी के अनुसार, दिल्ली उस जोन में है, जहां पर प्रदूषण काफी ज्यादा है। इसके अलावा, अभी लोग कोविड-19 महामारी का सामना भी कर रहे हैं। इसे देखते हुए सभी तरह के पटाखों के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।

तृणमूल कांग्रेस...

कहा था। घोष को मार्च, 2020 में तृणमूल कांग्रेस ने राज्यसभा के लिए नामित किया था। उससे पहले वह 2019 में बुलारघाट से लोकसभा चुनाव हार गई थीं।

न्यायाधिकरणों में...

के तहत सदस्यों का कार्यकाल केवल एक साल होगा और उन्होंने कहा, एक साल के लिए कौन सा न्यायाधीश यह काम करेगा? चयन समिति द्वारा अनुशंसित नामों को अस्वीकार किए जाने के मामले पर वेणुगोपाल ने कहा कि सरकार के पास सिफारिशों को स्वीकार नहीं करने का अधिकार है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, जहां कानून के शासन का पालन किया जाता है और हम संविधान के तहत काम कर रहे हैं। आप यह नहीं कह सकते कि मैं स्वीकार नहीं करता। पीठ ने कहा, यदि सरकार को ही अंतिम फैसला करना है, तो प्रक्रिया की शुचिता क्या है? चयन समिति नामों को चुनने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया का पालन करती है। विभिन्न प्रमुख न्यायाधिकरणों और अपीली न्यायाधिकरणों में लगभग 250 पद रिक्त हैं। शीर्ष अदालत न्यायाधिकरणों में रिक्तियों संबंधी याचिकाओं और अर्ध न्यायिक निकायों को नियंत्रित करने वाले नए कानून संबंधी मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

पाकिस्तान को...

भटकाने की कोशिशों से वाकिफ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जैसे नाकाम मुल्क से विश्व के सबसे बड़े व जीवंत लोकतंत्र भारत को कोई सबक सीखने की जरूरत नहीं है। भारतीय राजनयिक ने कहा कि पाकिस्तान सिख, हिंदू, ईसाई और अहमदिया सहित अपने अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने में नाकाम रहा है। बाधे ने एक बयान में कहा, पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले क्षेत्रों में हजारों की संख्या में महिलाओं व लड़कियों का अपहरण किया गया, जबरन शादियां कराई गई और धर्मांतरण कराया गया है। उन्होंने परिषद में कश्मीर मुद्दा उठाने को लेकर ओआईसी की भी निंदा करते हुए कहा कि इस किसी देश के अंदरूनी मामलों में टिप्पणी करने का उसका कोई हक नहीं बनता है।

सोनू सूद...

जाएगा। दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सूद के समर्थन में उतरते हुए ट्वीट में कहा, सच्चाई की राह पर लाखों मुश्किलें हैं, लेकिन सच्चाई की हमेशा जीत होती है। सच्चाई के रास्ते पर लाखों मुश्किलें आती हैं, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। सोनू जी के साथ भारत के उन लाखों परिवारों की दुआएं हैं, जिन्हें मुश्किल घड़ी में सोनू जी का साथ मिला था। आप नेता एवं पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने ट्वीट किया, यह कुछ और नहीं, बल्कि लाखों लोगों द्वारा मसीहा माने जाने वाले एक बड़े परोपकारी को असुरक्षित सरकार की ओर से चुनिंदा तरीके से निशाना बनाया जाना है। आप विधायक आतिशी ने आरोप लगाया कि अभिनेता एव परोपकारी सोनू सूद के खिलाफ आयकर विभाग का सर्वे भाजपा द्वारा यह स्पष्ट संदेश है कि वह देश में अच्छा काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को निशाना बनाएगी।

भारत में...

1,948 मामले दर्ज किए गए। दिल्ली में 2020 में हत्या के 472 मामले दर्ज किए गए। पिछले साल राष्ट्रीय राजधानी समेत पूरे भारत में कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगाया गया था। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल जिन लोगों की हत्या की गई थी उनमें से 38.5 प्रतिशत 30-45 वर्ष आयु समूह के थे जबकि 35.9 प्रतिशत 18-30 वर्ष आयु के समूह के थे। आंकड़े बताते हैं कि कत्ल किए गए लोगों में 16.4 फीसदी 45-60 वर्ष की आयु वर्ग के थे तथा चार प्रतिशत 60 वर्ष से अधिक उम्र के थे जबकि शेष नाबालिग थे। आंकड़ें बताते हैं कि 2020 में अपहरण के सबसे ज्यादा 12,913 मामले उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए। इसके बाद पश्चिम बंगाल में अपहरण के 9,309, महाराष्ट्र में 8,103, बिहार में 7,889, मध्य प्रदेश में 7,320 मामले दर्ज किए गए। आंकड़ों के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में अपहरण के 4,062 मामले दर्ज किए गए हैं।

दूरसंचार पैकेज से दबाव से जूझ रहे क्षेत्र को मिलेगी राहत: उद्योग संगठन सीओएआई

भाषा। नई दिल्ली

● सोनम चांदवानी ने कहा, इससे वोडाफोन आइडिया जैसी संकट में फंसी दूरसंचार कंपनी को राहत मिलेगी

दूरसंचार कंपनियों के संगठन सीओएआई (सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसएिश ऑफ इंडिया) ने बुधवार को घोषित दूरसंचार राहत पैकेज की सराहना करते हुए कहा कि इससे दबाव से जूझ रहे क्षेत्र को बड़ी राहत मिलेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार कंपनियों के लिए राहत पैकेज को मंजूरी दी।

इसमें अन्य बातों के अलावा समायोजित सकल राजस्व में केवल दूरसंचार सेवाओं से प्राप्त आय को शामिल करने की बात कही गई है। सीओएआई के महानिदेशक एस पी कोचर ने एक बयान में कहा, हम घोषित पैकेज का स्वागत करते हैं। यह हमारी लंबे समय से जारी मांग के अनुरूप है। इससे निश्चित रूप से आने वाले समय में दबाव से जूझ रहे क्षेत्र को राहत मिलेगी। कोचर ने कहा कि उद्योग इसे सरकार की सोच के एक संकेतक के रूप में लेता है और 5जी क्रियान्वयन से जुड़ी लागत और प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाने का उत्सुकता से इंतजार कर रहा है।

उन्होंने कहा कि पैकेज के विस्तार से विश्लेषण के बाद बयान जारी किया जाएगा। के एस लीगल एंड एसोसिएट्स की प्रबंध भागीदार सोनम चांदवानी ने कहा, इससे वोडाफोन आइडिया जैसी संकट में फंसी दूरसंचार कंपनी को राहत मिलेगी। क्योंकि ऐसा नहीं होने पर पिछले सांविधिक बकाया को लेकर करोड़ों रुपए देने पड़ते। देनदारी को कुछ समय के लिए टाला गया है, इसे पूरी तरह से बट्टे खाते में नहीं डाला गया है।

उन्होंने कहा कि इससे बैंकों को भी राहत मिलेगी क्योंकि उनके वोडाफोन आइडिया पर काफी राशि बकाया है। हालांकि अभी साफ नहीं है कि वोडाफोन कैसे बकाए का भुगतान करेगी, लेकिन अतिरिक्त समय मिलने से निश्चित रूप से उन्हें दबाव प्रबंधन में मदद मिलेगी। चांदवानी ने यह भी कहा, राहत समय पर आई है और दूरसंचार कंपनियों को इससे मदद मिलेगी। देनदारी को टाला गया है, समाप्त नहीं किया गया है। वोडाफोन की गंभीर वित्तीय स्थिति को देखते हुए, यह अभी साफ नहीं है कि कैसे वह कर्ज का भुगतान करेगी तथा कारोबार को कैसे व्यावहारिक बनाएगी।

अमेरिका के एक शीर्ष थिंक टैंक की रिपोर्ट में किया गया दावा

मजूबत हो रहा है पाकिस्तान समर्थित अलगाववादी खालिस्तानी संगठन

भाषा। वाशिंगटन

अमेरिका के एक शीर्ष थिंक टैंक ने कहा है कि पाकिस्तान समर्थित अलगाववादी खालिस्तानी समूह अमेरिका में धीरे-धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। उसने यह भी कहा कि अमेरिकी सरकार इन संगठनों की भारत विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए नई दिल्ली द्वारा की गई अपीलों के प्रति उदासीन रही है। हडसन इंस्टीट्यूट ने मंगलवार को प्रकाशित अपनी रिपोर्ट पाकिस्तान का अस्थिरता का षड्यंत्र : अमेरिका में खालिस्तान की सक्रियता में पाकिस्तान द्वारा इन संगठनों को दिए जा रहे समर्थन की जांच करने के लिए अमेरिका के भीतर खालिस्तान और कश्मीर अलगाववादी समूहों के आचरण को आंका है। रिपोर्ट में इन समूहों के भारत में उग्रवादी और आतंकवादी संगठनों के साथ संबंधों और दक्षिण एशिया में अमेरिकी विदेश नीति पर उनकी गतिविधियों के संभावित हानिकारक प्रभावों पर गौर किया गया है। रिपोर्ट दर्शाती है कि पाकिस्तान स्थित इस्लामी आतंकवादी संगठनों की तरह, खालिस्तानी संगठन नए नामों के साथ सामने आ सकते हैं।

इसमें कहा गया, दुर्भाग्य से, अमेरिकी सरकार ने खालिस्तानियों द्वारा की गई हिंसा में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है, जबकि खालिस्तान अभियान के सबसे कट्टर समर्थक ब्रिटेन, कनाडा और अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों में हैं। रिपोर्ट में कहा गया, जब तक अमेरिकी सरकार खालिस्तान से संबंधित उग्रवाद और आतंकवाद की निगरानी को प्राथमिकता नहीं देती, तब तक उन समूहों की पहचान होने की संभावना नहीं है जो वर्तमान में भारत में पंजाब में हिंसा में लिप्त हैं या ऐसा करने की तैयारी कर रहे हैं। हडसन इंस्टीट्यूट का कहना है कि पूर्वानुमान राष्ट्रीय सुरक्षा योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसलिए,उत्तरी अमेरिका में स्थित खालिस्तानी संगठनों की गतिविधियों की कानून द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर जांच करना 1980 के दशक में खालिस्तान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा फिर से न होने देने के लिए महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट में कहा गया कि महत्त्वपूर्ण यह भी है कि अमेरिका के भीतर खालिस्तान से संबंधित भारत विरोधी सक्रियता हाल में बढ़ी है और वह भी तब जब अमेरिका और भारत चीन के बढ़ते प्रभाव खासकर हिंद-प्रशांत में, उसका सामना करने के लिए सहयोग कर रहे हैं। रिपोर्ट अमेरिकी सरकार से भारत की चिंताओं को गंभीरता से लेने का आह्वान करती है और भारत को इन चिंताओं को दूर करने में मदद करने के लिए आवश्यक खुफिया और कानून प्रवर्तन संसाधनों को उपलब्ध कराने का आग्रह करती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी सरकार को भारत में आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार सभी संगठनों को वैश्विक आतंकवादी संगठनों की सूची में शामिल करना चाहिए और उन विभिन्न व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित करना चाहिए जिनकी भारत और अमेरिकी खुफिया और कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने आतंकवादी संस्थाओं से जुड़े होने के रूप में पहचान की है। इसने कहा, कश्मीरी और खालिस्तान अलगाववाद का समर्थन करने वाले विभिन्न संगठनों

ताइवान के राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से जारी की गई तस्वीर में राष्ट्रपति टी साइ इंग-वेन सैन्य अभ्यास के दौरान सैनिकों से मुलाकात करते हुए

कैलिफोर्निया के गवर्नर को हटाने की कोशिश नाकाम, गैविन न्यूसम पद पर बरकरार

एपी। सैक्रामेंटो (अमेरिका),

कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने कार्यकाल की समाप्ति से पहले उन्हें पद से हटाए जाने की कोशिश नाकाम कर दी। इसी के साथ न्यूसम अमेरिका के इतिहास में मंगलवार को ऐसे दूसरे गवर्नर बन गए, जो कार्यकाल की समाप्ति से पहले पद से हटाने के लिए कराए गए चुनाव में विजई रहे हैं। इससे पहले, विस्कॉनसिन के गवर्नर और रिपब्लिकन पार्टी के नेता स्कॉट वाल्कर ने 2012 में उन्हें समय से पूर्व पद से हटाए जाने की कोशिश नाकाम कर दी थी। इस जीत के साथ ही न्यूसम डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति में अहम नेता बनकर सामने आए हैं और उन्हें अमेरिका में भविष्य में राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार बनाए जाने की संभावना प्रबल हो गई है। न्यूसम ने इस मतदान को कोरोना वायरस वैश्विक महामारी और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विचारधारा के खिलाफ अपनी पार्टी के मूल्यों के लिए राष्ट्रीय लड़ाई के तौर पर पेश किया था। इस चुनाव में न्यूसम की जीत का अर्थ है कि देश में सबसे अधिक आबादी वाले इस राज्य में डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार रहेगी और यह आव्रजन, जलवायु परिवर्तन और असमानता जैसे मामलों पर पार्टी की प्रगतिशील नीतियों की प्रयोगशाला के तौर पर काम करेगा। मतदान से पहले देश के राष्ट्रपति जो बाइडन ने लोगों से अपील की थी कि वे कोविड-19 के मद्देनजर कड़े प्रतिबंध लागू करने और टीकाकरण की आवश्यकता संबंधी डेमोक्रेटिक पार्टी के दृष्टिकोण का समर्थन करें और देश को दिखा दें कि नेतृत्व मायने रखता है, विज्ञान मायने रखता है। यह मतदान इस बात की भी परीक्षा था कि क्या डोनाल्ड ट्रम्प और उनकी दक्षिणपंथी राजनीति का विरोध डेमोक्रेट और निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए अब भी एक प्रेरक शक्ति है। मतदान से पहले न्यूसम ने कहा था, हमने डोनाल्ड ट्रंप को तो हरा दिया है, लेकिन हमने उनकी विचारधारा को नहीं हराया है। ट्रंप की विचारधारा इस देश में अब भी जीवित है। इस मतदान के दौरान मतदाताओं से दो प्रश्न पूछे गए थे: क्या न्यूसम को पद की जिम्मेदारी से हटाया जाना चाहिए और यदि हां, तो उनकी जगह किसे यह जिम्मेदारी दी जानी चाहिए? लगभग 60 प्रतिशत मतपत्रों की गिनती के बाद न्यूसम को पद से हटाने के सवाल का नहीं में जवाब देने वाले मतदाताओं की संख्या हां में जवाब देने वालों से दोगुनी रही। यदि न्यूसम इस जनमत संग्रह पर चुनाव हार जाते, तो उनकी जगह गवर्नर बनने के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार रिपब्लिकन टॉक रेडियो मेजबान लैरी एल्डर होते।

काश सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए जादू की छड़ी होती : संरा महासभा अध्यक्ष

भाषा। संयुक्त राष्ट्र

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद ने कहा कि सुरक्षा परिषद में सुधार करने के लिए काश उनके पास जादू की छड़ी होती और उन्होंने उम्मीद जताई कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य इस प्रक्रिया को गंभीरता से लेंगे।मालदीव के विदेश मंत्री शाहिद को इस साल सात जुलाई को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया था। शाहिद ने कहा, काश मेरे पास सुरक्षा परिषद में बदलाव और सुधार करने के लिए जादू की छड़ी होती। 1979 में मालदीव सुरक्षा परिषद पर एक एजेंडा शामिल करने के उद्देश्य से 10 देशों के समूह में शामिल हुआ और मुझे काफी गर्व है कि मालदीव पहले 10 देशों में से एक है जिसने इसकी पहल की। उन्होंने एक सवाल के जवाब में पीटीआई-भाषा से कहा, हालांकि अध्यक्ष के तौर पर मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है, मैं उम्मीद करता हूं कि सदस्य इस प्रक्रिया को गंभीरता से लेंगे। उन्होंने कहा कि वह अंतर-सरकारी वार्ता (आईजीएन) के लिए सह-वार्ताकार नियुक्त करेंगे ताकि वे और संयुक्त राष्ट्र सदस्यों के पास इस पर काम करने के लिए और वक्त हो और मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई प्रतिनिधि टी एस तिरुमूर्ति ने कहा था, मैंने पहले भी कई बार कहा है कि आईजीएन को धुएं की परत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आज आईजीएन पर काम शुरू करने के संशोधित फैसले के साथ हम अगले सत्र की ओर इस उम्मीद के साथ बढ़ेंगे कि हम सुरक्षा परिषद में लंबे समय से अटके सुधार की ओर निर्णायक प्रगति कर सकें। महासभा के 76वें सत्र की अध्यक्षता संभालने के बाद शाहिद ने पत्रकारों से कहा कि उनकी उम्मीद की अध्यक्षता सभी के अधिकारों का सम्मान करने और संयुक्त राष्ट्र के पुन: नवीनीकरण के बारे में हैं।

चिर प्रतिद्वंद्वी कोरियाई देशों ने मिसाइल परीक्षण किए, फिर से तनाव बढ़ा

एपी। सियोल

चिर प्रतिद्वंद्वी दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया ने अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करते हुए बुधवार को बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण किए। यह घटनाक्रम अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ने के लिए उत्तर कोरिया पर कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिशों के बीच हुआ है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि उसने बुधवार दोपहर पानी के अंदर लक्ष्य को भेदने वाली अपनी पहली मिसाइल का परीक्षण किया है। उसने कहा कि एक स्वदेश निर्मित मिसाइल 3,000 टन श्रेणी की पनडुब्बी से दागी गई और इसने अपने निर्धारित लक्ष्य को भेदने से पहले पूर्व निर्धारित दूरी तय की।

बयान में कहा गया है कि इस मिसाइल से दक्षिण कोरिया को संभावित बाहरी खतरों को रोकने, अपनी आत्म रक्षा को मजबूत करने और कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति को बढ़ावा देने में मदद मिलने की उम्मीद है। इससे पहले दक्षिण कोरिया की सेना ने बुधवार को कहा कि उत्तर कोरिया ने छोटी दूरी की दो बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है। सोमवार को उत्तर कोरिया ने कहा था कि उसने छह महीनों में पहली बार नव विकसित क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया।

विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तर कोरिया द्वारा मिसाइलों का परीक्षण फिर से शुरू करने का मकसद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन पर परमाणु वार्ता को लेकर दबाव बनाना हो सकता है। दक्षिण कोरिया आम तौर पर अपने हाई-प्रोफाइल हथियारों के परीक्षण की जानकारी सार्वजनिक नहीं करता है क्योंकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इससे उत्तर कोरिया अनावश्यक रूप से भड़क सकता है। पर्यवेक्षकों का कहना है हो सकता है कि मून जेई इन की सरकार इस आलोचना का जवाब दे रही हो कि उसने उत्तर कोरियाई बहुत अधिक नरम रुख अपनाया हुआ है। उनकी सरकार उत्तर कोरिया के साथ सुलह पर सक्रियता से काम कर रही है।दक्षिण कोरिया की सेना ने बताया कि उत्तर कोरियाई मिसाइलें बुधवार को करीब 800 किलोमीटर की दूर तय करने के बाद कोरियाई प्रायद्वीप और जापान के बीच समुद्र में गिरी।

अमेरिका हिंद-प्रशांत कमान ने कहा कि इन परीक्षणों से अमेरिका या उसके सहयोगियों को निजी या क्षेत्रीय रूप से कोई निकटवर्ती खतरा नहीं है। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा, गोलीबारी से जापान और क्षेत्र की शांति एवं सुरक्षा को खतरा है तथा यह बिल्कुल घृणित है। जापान की सरकार किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अपनी निगरानी बढ़ाने को लेकर दृढ़ संकल्पित है। जापान के तटरक्षक बल ने बताया कि मिसाइलों से किसी भी जहाज या विमान को नुकसान नहीं पहुंचा है। उत्तर कोरिया ने मिसाइल परीक्षण ऐसे वक्त में किया है जब चीन के विदेश मंत्री वांग ई परमाणु वार्ता में गतिरोध पर दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा से करने के लिए सियोल में हैं।मून के कार्यालय ने बताया कि राष्ट्रपति ने वांग से कहा कि वह उत्तर कोरियाई परमाणु गतिरोध को हल करने में अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक कोशिशों में चीन की भूमिका की सराहना करते हैं और उन्होंने बीजिंग से सहयोग करते रहने को कहा। वांग ने कहा कि बीजिंग कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु निरस्त्रीकरण और दोनों कोरियाई देशों के बीच संबंधों में सुधार का समर्थन करता रहेगा।अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच परमाणु वार्ता 2019 से रुकी हुई है जब अमेरिका ने एक पुराने परमाणु केंद्र को नष्ट करने के बदले में प्रतिबंधों से बड़ी राहत देने की उत्तर कोरिया की मांग खारिज कर दी थी। किम जोंग उन की सरकार ने अमेरिका को निशाना बनाने वाले हाई-टेक हथियार बनाने की धमकी दी और जो बाइडन प्रशासन की संवाद की पहल को खारिज करते हुए सबसे पहले अमेरिका से अपनी शत्रुतापूर्ण नीतियों को छोड़ने को कहा था।

उत्तर कोरिया पर तनाव के बीच दक्षिण कोरिया और चीन के विदेश मंत्रियों ने की मुलाकात

सियोल। दक्षिण कोरिया और चीन के विदेश मंत्रियों ने बुधवार को मुलाकात की जिसमें उत्तर कोरिया और अन्य क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। यह बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब दो दिन पहले उत्तर कोरिया ने नई क्रूज मिसाइल का परीक्षण करने का दावा किया। उत्तर कोरिया ने सोमवार को कहा था कि उसने सप्ताहांत में मिसाइल का दो बार परीक्षण किया और इसने ।,500 किलोमीटर तक की दूरी तय की। इसके साथ ही यह मिसाइल जापान के सभी क्षेत्रों पर हमला करने में सक्षम हैं जिसमें वहां स्थित अमेरिकी सेना के अड्डे भी आते हैं। अमेरिका के साथ परमाणु कूटनीति में गतिरोध के बीच उत्तर कोरिया ने यह मिसाइल परीक्षण किया है। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चुंग इयू-योंग बुधवार को अपने चीनी समकक्ष वांग ई के साथ सियोल में बैठक के दौरान उत्तर कोरिया से परमाणु वार्ता फिर से शुरू करने के लिए उसको मनाने में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए कह सकते हैं। गौरतलब है कि चीन, उत्तर कोरिया का सबसे बड़ा सहयोगी और सहायक देश है। उत्तर कोरिया का 90 प्रतिशत से अधिक कारोबार चीन के जरिए होता है।कुछ पर्यवेक्षकों का मानना है कि बुधवार को बातचीत के दौरान वांग दक्षिण कोरिया के साथ संबंध मजबूत करना चाहेंगे ताकि उसे अमेरिका के प्रति बहुत अधिक झुकाव रखने से रोकने की कोशिश की जा सके। उनका कहना है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद चीन तथा रूस से बढ़ रही चुनौतियों को लेकर अमेरिका के अपनी विदेश नीति की समीक्षा करने की योजना को लेकर बीजिंग चिंतित है।

लाहौर में पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ के पदाधिकारियों ने अफगान महिला फुटबाल टीम के सदस्यों का सपरिवार पाकिस्ताान पहुचंने पर स्वागत किया

अफगान लोगों को आर्थिक मदद की जरूरतः संयुक्त राष्ट्र

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने कहा कि 40 लाख अफगान लोग एक खाद्य आपात स्थिति का सामना कर रहे हैं, जहां अधिकतर ग्रामीणों को शीतकाल में गेहूं की खेती और पशुओं के चारे के लिए वित्तीय मदद की तत्काल जरूरत है, साथ ही वंचित समूहों के परिवारों, बुजुर्गों तथा विकलांगों के लिए नकद सहायता की आवश्यकता है। खाद्य एवं कृषि संगठन के इमरजेंसी एंड रिसिलेंस कार्यालय के निदेशक रीन पॉलसन ने मंगलवार को काबुल से एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में बताया कि 70 प्रतिशत अफगान ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और कृषि अफगान आबादी के लिए बहुत जरूरी है। यह अफगानिस्तान के सकल घरेलू उत्पाद का 25 प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करती है, सीधे तौर पर 45 प्रतिशत कार्यबल को रोजगार देती है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह 80 प्रतिशत अफगान आबादी के लिए आजीविका का साधन है।

ताइवान जाएंगे पाक के प्रधानमंत्री इमरान खान

भाषा। इस्लामाबाद

प्रधानमंत्री इमरान खान शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ताजिकिस्तान की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा करेंगे और आपसी संबंधों पर वहां के नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। विदेश कार्यालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। खान दुशांबे में 20वें एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट (एससीओ-सीएचएस) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। विदेश कार्यालय (एफओ) ने कहा कि उन्हें ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान ने 16 - 17 सितंबर को यात्रा के लिए आमंत्रित किया है। खान के साथ मंत्रियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी जाएगा। उन्होंने इससे पहले 13-14 जून 2019 को किर्गिज गणराज्य के बिश्केक में आयोजित एससीओ-सीएचएस में भाग लिया और वीडियो-कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 10 नवंबर 2020 को रूस द्वारा आयोजित एससीओ-सीएचएस में हिस्सा लिया था। एससीओ को नाटो के प्रतिकार के रूप में देखा जाता है। यह आठ सदस्ईय आर्थिक और सुरक्षा गठजोड़ है और सबसे बड़े अंतर-क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में से एक के रूप में उभरा है। भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके स्थाई सदस्य बने थे। एससीओ की स्थापना 2001 में शंघाई में रूस, चीन, किर्गिज गणराज्य, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान के राष्ट्रपतियों द्वारा एक शिखर सम्मेलन में की गई थी।
एससीओ में चार पर्यवेक्षक देश- ईरान, मंगोलिया, बेलारूस और अफगानिस्तान- भी हैं और इसके अलावा इसके छह संवाद साझेदार- अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की और श्रीलंका- भी हैं।विदेश कार्यालय की तरफ से बताया गया है कि खान मुख्य कार्यक्रम से इतर अन्य सहभागी नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे।

इंडोनेशिया के पापुआ में दुर्घटनाग्रस्त हुआ विमान

जकार्ता (इंडोनेशिया)। इंडोनेशिया के पूर्व में स्थित पापुआ प्रान्त के पहाड़ी जंगलों में बुधवार को एक छोटा मालवाहक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हवाई तलाश में रिमबुन एयर के विमान का पता चलने के बाद अधिकारियों ने दुर्घटना की पुष्टि की।

तिमिका बचाव एजेंसी के प्रमुख जॉर्ज लियो मर्सी रनदंग ने बताया कि उड़ान दल के तीन सदस्यों की स्थिति का पता लगाने और उन्हें निकालने के लिए उस इलाके में एक खोजी और बचाव दल को भेजा गया है। इससे पहले परिवहन मंत्रालय ने कहा था कि विमान के उड़ान भरने के 50 मिनट बाद ही स्थानीय अधिकारियों का ट्विन ओट्टर 300 से संपर्क टूट गया था। विमान नाबरे जिले से जाया जिला की ओर जा रहा था और उस पर निर्माण सबंधी सामग्री लदी थी। रनदंग ने बताया कि सुबह मौसम साफ था लेकिन बाद में जब विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ तब आकाश में बादल छाए थे। हवाई मार्ग से की गई खोज से पता चला है कि विमान इंतन जाया में दुर्घटनग्रस्त हुआ।

तालिबान को मजबूत करने में पाक की भूमिका अहमः अमेरिकी सांसद

भाषा। वाशिंगटन

अमेरिका के एक शीर्ष सांसद ने कहा कि पाकिस्तान की तालिबान को मजबूत करने में भूमिका, पाकिस्तान सरकार में शामिल कट्टरपंथियों की जीत है। सांसद ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान में जो हालात पैदा हो रहे हैं और पाकिस्तान वहां जो भूमिका निभा रहा है, वह भारत के लिए अच्छा संदेश नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी से सांसद मार्को रुबियो ने अफगानिस्तान पर कांग्रेस की सुनवाई के दौरान कहा कि अमेरिका के कई प्रशासन तालिबान के फिर से संगठित होने में पाकिस्तान की भूमिका को अनदेखा करने के दोषी हैं। वहीं, अन्य अमेरिकी सांसदों ने पाकिस्तान के दोहरे व्यवहार पर चिंता व्यक्त की।

उन्होंने कहा, भारत....मुझे मालुम है कि आज एक घोषणा वहां हुई है कि क्वाड (चार देशों का समूह) की एक बैठक अति शीघ्र होगी, जो कि एक अच्छा कदम है......। सांसद ने विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन से कहा, मेरा मानना है कि अमेरिका के कई प्रशासन तालिबान के फिर से संगठित होने में पाकिस्तान की भूमिका को अनदेखा करने के दोषी हैं। पाकिस्तान की तालिबान को मजबूत करने में भूमिका, पाकिस्तान सरकार में शामिल तालिबान समर्थक कट्टरपंथियों की जीत है।

वहीं, सांसद माइक राउंड्स ने कहा कि पाकिस्तान तालिबान सरकार को भारत से निपटने के लिए एक साझेदार के तौर पर देख रहा है। वहीं, ईरान के राष्ट्रपति ने भी खुले आम इसे अमेरिकी सेना की हार करार दिया है और वह तालिबान के साथ मिल कर काम करने पर विचार कर रहे हैं। संसद की विदेश संबंधों की समिति के अध्यक्ष सांसद रॉबर्ट मेनेंडेज़ ने पाकिस्तान के दोहरे व्यवहार और तालिबान को सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराने के संबंध में बात की। सांसद जेम्स रिच ने ब्लिंकन से कहा कि अमेरिका को इस पूरे मामले में पाकिस्तान की भूमिका को समझना चाहिए।

पेरिस में अमीरात के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद का स्वागत करते फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों

सिनेमा जगत में एक नया चेहरा

अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म 'चेहरे' सिनेमाघरों में प्रदर्शित हो रही है। क्रिस्टी वर्गीज ने निर्देशक रूमी जाफरी से मुलाकात की।

पिछले एक हफ्ते से चेहरे काफी चर्चा में हैं, और सभी सही कारणों से। मूल रूप से जून 2020 में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, महामारी की चपेट में आने से पहले, चेहर के पीछे की टीम ने ओटीटी मार्ग नहीं लेने का विकल्प चुना और इसके बजाय अपना समय बिताया। इस साल की शुरुआत में, अप्रैल में, एक बार फिर यह घोषणा की गई थी कि फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। हालाँकि, वह तब था जब कोविड सकारात्मक मामलों की लगातार बढ़ती संख्या के साथ दूसरी लहर आई। और यहां हम हैं, मगर आखिरकार यह 27 अगस्त को देश भर के सिनेमाघरों में प्रसारित हो गई।

निर्देशक रूमी जाफरी ने चेहरे के निर्माता आनंद पंडित को अपने सबसे अच्छे धैर्य और परियोजना में विश्वास करने का श्रेय दिया। उन्होंने कहा, ''मैं आपको बताना चाहता हूं कि बतौर निर्देशक यह फिल्म सिनेमाघरों में दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। मुझे लगातार उन चीजों को करते रहने की ललक है जो मैंने पहले कभी नहीं की हैं। एक थ्रिलर पर काम करने के लिए मैंने जो कारण चुना उसका एक कारण यह भी है कि इसका दायरा असीम है। मैं लाइटिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक और शॉट्स वगैरह के साथ खेल सकता हूं। इस समय में उपलब्ध तकनीक और उपकरणों को ध्यान में रखते हुए, हम रेसुल पुकुट्टी जैसे सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ लाए, ताकि हमारे पास एक उपयुक्त अंत उत्पाद हो। मुझे ओटीटी से कोई आपत्ति नहीं है, इसने दर्शकों के साथ-साथ इंडस्ट्री के लोगों के लिए भी कई दिलचस्प रास्ते खोले हैं। लेकिन आनंद भाई स्थिति के बेहतर होने का इंतजार करने के लिए तैयार हो गए क्योंकि दर्शकों को एक संपूर्ण अनुभव के लिए सिनेमाघरों में इस अविश्वसनीय सिनेमा को देखने का अधिकार है। आनंद भाई को पूरा श्रेय, अपने सबसे अच्छे रोगी होने और चेहरे के मूल्य को पहचानने के लिए'', उन्होंने साझा किया।

स्पष्ट रूप से उत्साहित जाफरी फिल्म के बारे में बताना बंद नहीं कर सके और यह कैसे उनकी उम्मीद से बेहतर निकला। उन्होंने व्यक्त किया, ''ईमानदारी से, मुझे नहीं पता था कि क्या उम्मीद करनी है। और जब मैं ऐसा कहता हूं, मेरा मतलब यह नहीं है कि मैं दर्शकों की प्रतिक्रिया के बारे में चिंतित था, हालांकि कुछ सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करना हमेशा अच्छा होता है (हंसते हुए)। जब मैंने पहली बार उद्योग में कदम रखा, तो मुझे लोगों को एक निर्देशक के रूप में मेरी क्षमता पर भरोसा करने के लिए मनाने में तीन साल लग गए। और, ठीक है, मैं यहां हूं। लेकिन मुझे स्वीकार करना होगा, मुझे खुशी हुई जब लोग ट्रेलर की शानदार समीक्षा के साथ मेरे पास पहुंचे। इससे मुझे लगा कि मैं सही रास्ते पर हूं और मुझे खुद पर अधिक से अधिक विश्वास करना चाहिए। मैं फिल्म के रिलीज होने का इंतजार नहीं कर सकता।''

अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज के साथ काम करने के अपने अनुभव के बारे में बताते हुए जाफरी ने कहा, ''मैंने पहले भी उनके साथ दो प्रोजेक्ट्स में काम किया है और उनके साथ काम करना हमेशा खुशी की बात होती है। वह पूरी तरह से पेशेवर है, के माध्यम से और के माध्यम से; इतना अनुशासित, समर्पित और शामिल कि सेट पर निर्देशक के लिए

बिल्कुल कोई तनाव नहीं है, वास्तव में सेट पर मेरा काम आसान हो रहा है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपके सेट पर इतना वरिष्ठ अभिनेता, सुपरस्टार मौजूद है।''

उन्होंने खुलासा किया, ''हमने पोलैंड और स्लोवाकिया में फिल्म का एक बड़ा हिस्सा शूट किया, वह भी दिसंबर में। मेरे बहुत से साथियों ने मुझे आगाह कर दिया था, जब उन्हें पता चला कि मैं बच्चन जी के साथ पोलैंड में शूटिंग करूंगा। मुझे यह एक समय याद है जब तापमान 14 डिग्री था और कुछ असुविधा के बावजूद, उन्होंने बिना किसी उपद्रव के शूटिंग पूरी की।''

मैं आपको बताना चाहता हूं कि बतौर निर्देशक यह फिल्म सिनेमाघरों में दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। मुझे लगातार उन चीजों को करते रहने की ललक है जो मैंने पहले कभी नहीं की हैं। एक थ्रिलर पर काम करने के लिए मैंने जो कारण चुना उसका एक कारण यह भी है कि इसका दायरा असीम है। मैं लाइटिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक और शॉट्स वगैरह के साथ खेल सकता हूं। इस समय में उपलब्ध तकनीक और उपकरणों को ध्यान में रखते हुए, हम रेसुल पुकुट्टी जैसे सर्वश्रेष्ठ में से सर्वश्रेष्ठ लाए, ताकि हमारे पास एक उपयुक्त अंत उत्पाद हो।

जैसे-जैसे बातचीत आगे बढ़ रही थी, उत्साह का एक हिस्सा जाफरी ने अपने करियर में पहली बार किया था। ''मैं फिर से एक नवागंतुक की तरह महसूस करता हूं। मैंने अपने जीवन में पहली बार एक गीत लिखा था, और क्या आप इस पर विश्वास करेंगे यदि मैं कहूं कि यह फिल्म का शीर्षक ट्रैक है, जिसे बच्चन जी ने गाया था और विशाल और शेखर द्वारा संगीतबद्ध किया था'', उन्होंने एक विस्तृत मुस्कान के साथ साझा किया .

जब हमने उनसे उनके काम के फॉर्मूले के बारे में पूछा, तो उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया, ''मैंने तय किया है कि मैं खुद को कभी नहीं दोहराऊंगा। मैं दर्शकों को वही, उबाऊ चीजें परोसने से नफरत करूंगा। मैं दर्शकों के लिए और अधिक अविश्वसनीय सामग्री का पता लगाना और उसके साथ आना चाहता हूं। सच कहूं तो मेरे पास तीन प्रोजेक्ट तैयार हैं, सब कुछ के रखा है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि यह उद्योग कैसे काम करता है; मैं चीजों को एक बार में एक कदम उठाना चाहता हूं। मुझे यकीन है कि चेहरे और लोगों को मेरे विजन पर भरोसा दिलाएगा। देख लेना, चेहरे के बाद और अच्छी फिल्म बनाउंगा मैं।''

टेलीकथा

पुराने अंदाज़ में गणेशोत्सव

पिछले तीन दशकों में, ज़ी टीवी ने शानदार कहानियों के साथ अपने दर्शकों का मनोरंजन किया है, प्यारे पात्र, और झोंपड़ी तोड़ने वाले फिक्शन शो जो जनता के साथ जुड़े हुए हैं। महामारी के दौरान भी, इसने अपने दर्शकों को ऐसी सामग्री प्रदान करने का प्रयास किया है जो उन्हें प्रेरित करता है और उन्हें जोड़े रखता है।

कोने के आसपास उत्सव के साथ और भारत भर में समारोहों को सीमित करने वाले प्रतिबंध, ज़ी टीवी के लिए एक आश्चर्य प्रस्तुत हो रहा है। चैनल आपको गणेश चतुर्थी का लुक, फील और फ्लेवर देने के लिए पूरी तरह तैयार है और अपने घरों में सुविधाजनक रूप से यह एक विशेष के माध्यम से एक असाधारण उत्सव प्रस्तुत करता है।

'ज़ी टीवी के साथ गणेश उत्सव' का एपिसोड। यह विशेष एपिसोड 19 सितंबर को दोपहर 12 बजे प्रसारित होगा और यह निश्चित रूप से सभी को मंत्रमुग्ध कर देगा। ज़ी टीवी के दर्शक कुमकुम भाग्य की जोड़ी अभि (शब्बीर अलुवालिया) - प्रज्ञा (श्रीति झा) और प्राची (मुग्धा चापेकर) - रणबीर (कृष्णा कौल) जैसे टेली सितारों के कुछ प्रदर्शनों को देखेंगे।

अभिषेक कपूर- मनित जौरा और अंकिता लोखंडे जैसे कलाकार भी प्रस्तुति देंगे। कुमकुम भाग्य के सितारों मुग्धा चापेकर और कृष्णा कौल ने हमने तुमको देखा, एक मैं और एक तू और खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे जैसे बॉलीवुड गानों पर रेट्रो एक्टिंग की है।

अपने अभिनय के बारे में बात करते हुए, मुग्धा ने कहा, ''पिछले साल, महामारी के कारण, हम सभी त्योहारों को नहीं मना सके जैसे हम आमतौर पर करते हैं।

एक महाराष्ट्रियन होने के नाते, मैं वास्तव में गणेश चतुर्थी मनाने से चूक गई। गणेश चतुर्थी मेरे लिए सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह एक भावना है। बेशक, हमने सभी दिशा-निर्देशों का पालन किया, सभी आवश्यक सावधानियां बरतीं, जब हम शूटिंग नहीं कर रहे थे तब अपने मास्क पहने और सब कुछ साफ कर दिया, हम यह नहीं भूलते। लेकिन यह मज़ेदार था, और हमने पुराने अंदाज़ के इन सभी कपड़ों को पहनकर और 70 के दशक के गानों पर परफॉर्म करते हुए, एक पुराण अंदाज़ में समारोहों का प्रदर्शन किया। वास्तव में, कृष्णा और मैंने अपने प्रिय आकर्षक दिवंगत अभिनेता ऋषि जी को भी यह अभिनय समर्पित किया और हमने उनके अधिकांश गीतों पर प्रदर्शन किया।''

बालिका वधू की आनंदी

कलर्स के बालिका वधू के लॉन्च के बाद से, अभिनेत्री श्रेया पटेल द्वारा अभिनीत नई आनंदी को पूरे भारत में दर्शकों से अपार प्यार और सराहना मिल रही है। दर्शक शो से जुड़े हुए हैं और मासूमियत और आनंद से भरे उनके प्यारे बचपन को देखना पसंद करते हैं। शो में आनंदी का अब तक

का सफर आसान और हल्का रहा है, लेकिन जैसे ही कहानी का अगला चरण शुरू होगा, यह तेजी से बदलेगा। आने वाले एपिसोड में दर्शकों को कुछ हाई-एंड ड्रामा देखने को मिलेगा, जिससे हर कोई अपनी सीट से किनारा कर लेगा। .

अपने जीवन की कड़वी सच्चाई से बेखबर, जो उन्हें जल्द ही प्रभावित करेगी, छोटी आनंदी को शो में अपने प्यारे और मासूम बचपन का आनंद लेते हुए देखा गया है। दर्शकों ने अब तक आनंदी की प्रतिक्रिया देखी है जब उसे जिगर से अपनी शादी के बारे में पता चला जब वह सिर्फ एक शिशु थी। वह अब गौना समारोह के दौरान अपने भाग्य के साथ आमने-सामने आएगी जब उसे अपने माता-पिता के घर से बाहर जाना होगा। जब उसे जिगर के घर में बहू के रूप में रहने के लिए मजबूर किया जाता है, तो उसका जीवन काफी बदल जाएगा।

ट्विस्ट के बारे में बात करते हुए, आनंदी की भूमिका निभाने वाली श्रेया पटेल ने खुलासा किया, ''आनंदी के जीवन में एक बड़ा पल आने वाला है, और यह उसकी दुनिया को पूरी तरह से उलट देगा। गौना सीक्वेंस शो के लिए एक महत्वपूर्ण प्लॉट टि्वस्ट होगा क्योंकि आने वाले एपिसोड में हर कोई आनंदी को असंख्य भावनाओं से गुजरते हुए देखेगा।''

खिमजी की भूमिका निभाने वाले अंशुल त्रिवेदी ने कहा, ''आनंदी कई चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है क्योंकि कहानी एक महत्वपूर्ण मोड़ लेती है जो उसे उसके जीवन की कठोर वास्तविकता के सामने लाएगी। हम सब 'बालिका वधू' के इस नए चरण के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, जो दर्शकों को बांधे रखने के लिए निश्चित है!''

जबकि गौना सीक्वेंस उसकी दुनिया को उल्टा कर देता है, क्या आनंदी व्यवस्था और परंपराओं के खिलाफ लड़ेगी ? या वह इसके आगे झुक जाएगी ?

वापस लौट आया यूफोरिया

जैसे ही पलाश ने कू पर पोस्टर साझा किया, प्रशंसकों ने अपना प्यार दिखाने और शुभकामनाएं व्यक्त करने के लिए संदेश देना शुरू कर दिया। कुछ टिप्पणियों को नीचे दिए गए ग्रैब में देखा जा सकता है। गायक, जो एक योग्य डॉक्टर भी हैं, जून में कू में शामिल हुए और अब मंच पर उनके करीब 8,000 अनुयायी हैं।

सेल भारतीय इंडी बैंड 'यूफोरिया' का आठवां एल्बम है। 7-ट्रैक तमाशा आपको शैलियों, ध्वनियों, शैलियों, भावनाओं और जीवन के अनुभवों की सवारी पर ले जाएगा। पलाश के करियर के विभिन्न बिंदुओं पर लिखा गया, प्रत्येक गीत एक वास्तविक जीवन की कहानी के लिए खड़ा है जिसे उन्होंने और बैंड ने देखा या महसूस किया है। एक ऐसी दुनिया में जहां सब कुछ एक कीमत के साथ आता है, यह एल्बम एक ऐसी चीज के बारे में बोलता है जिसे खरीदा नहीं जा सकता - लव ऑर इज़ इट ?

सेल 10 सितंबर को सीमित एनएफटी के रूप में और 14 सितंबर को दुनिया भर के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी।

यह एल्बम लॉन्च कू हिंदी फेस्ट के उद्घाटन संस्करण के आधिकारिक उद्घाटन का भी प्रतीक है, देश भर में हिंदी रचनाकारों का सम्मान और जश्न मनाने और उन्हें खुद को व्यक्त करने और खुद को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करने वाला एक 7 दिवसीय कार्यक्रम, जो इस 14 वें हिंदी दिवस को तैयार करता है। सितंबर। इस उत्सव का उद्देश्य भारत के हिंदी रचनाकारों और प्रभावितों को खुद को सोशल मीडिया निर्माता और प्रभावित करने वालों के रूप में स्थापित करने के लिए एक समान मंच प्रदान करना है और साहित्यिक (रचनात्मक लेखन, कविता, वाद-विवाद) और सांस्कृतिक गतिविधियु (संगीत, अभिनय, फोटोग्राफी, ब्लॉगिंग)। यह बिल्कुल सही है कि पलाश और यूफोरिया, भारत की विरासत इंडी क्रिएटर्स में से एक होने के नाते, इस तरह के पहले डिजिटल फेस्टिवल का उद्घाटन कर रहे हैं।

यूफोरिया को 'मेरी' और 'धूम' जैसे असाधारण संगीत हिट के लिए जाना जाता है जो 90 के दशक में बड़े पैमाने पर हिट हुए थे। तब से, बैंड पूरे देश में संगीत प्रेमियों की पसंदीदा सूची में है।

आज़ाद के ओरिजिनल - मेरी डोली, मेरे अंगना एवं पवित्र भरोसे का सफर

यह बिगिनन मीडिया के पहले उपभोक्ता विशिष्ट मनोरंजन चैनल, आज़ाद के साथ शो का समय है, जो विशेष रूप से ग्रामीण मानसिकता के लिए अपनी मूल सामग्री की पेशकश की घोषणा करता है। आज़ाद भारत का पहला प्रीमियम हिंदी ग्रामीण मनोरंजन चैनल है। मेरी डोली मेरे अंगना और पवित्र भरोसा का सफर शीर्षक वाले पहले दो शो, दोनों शो को समय-समय पर सिंडिकेटेड शोध के माध्यम से ग्रामीण व्यक्ति की गहरी समझ के बाद बनाया गया है। हमारी मिट्टी हमारा आसमान के ब्रांड प्रस्ताव पर खरा उतरते हुए, शो की थीम को विशेष रूप से इस सुपर मास के साथ आकर्षित करने, संलग्न करने और कनेक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 14 सितंबर 2021 से, मेरी डोली मेरे अंगना रात 9 बजे और पवित्र भरोसा का सफर 9 30 बजे, आज़ाद पर और साथ ही एमएक्स प्लेयर (डिजिटल पार्टनर) पर प्रसारित होगा।

पहले आज़ाद मूल का शीर्षक मेरी डोली मेरे अंगना है। टेल-ए-टेल मीडिया के प्रसिद्ध निर्माताओं, जितेंद्र गुप्ता और महेश तगड़े द्वारा निर्मित शीर्षक जो तत्काल जिज्ञासा पैदा करता है। यह शो बिठूर पर आधारित है, जहां पूरा सिंह परिवार, खासकर उनके पिता बेटी को अपनी आंखों का तारा मानते हैं। यह आज के ग्रामीण परिवार की कहानी है जो परिवार के भीतर संबंधों की सुंदरता और जटिलताओं को चित्रित करती है।

कुछ परिस्थितियों के कारण ये रिश्ते बदल जाते हैं और यह हमारी नायिका के जीवन को काफी प्रभावित करता है। अपनी शादी के बाद, उसे पता चलता है कि पुराने सामाजिक मानदंड जहां वे एक बेटी और बहू के बीच अंतर करते हैं, अभी भी मौजूद है। यह शो जानकी की एक अनुभवी और मासूम बेटी से एक अनुभवी बहू बनने तक की यात्रा को दर्शाता है जो अपनी शादी के बाद जटिल परिस्थितियों और बदलती गतिशीलता के साथ संबंधों को प्रबंधित करना सीखती है। आस्था अभय ने मुख्य किरदार जानकी और सुरेंद्र पाल, रुद्राक्षी गुप्ता और अंकित रायजादा ने शो में प्रमुख किरदार निभाए हैं।

दूसरी आज़ाद ओरिजिनल का शीर्षक पवित्रा भरोसा का सफर है और इसे पार्थ प्रोडक्शन के जाने-माने प्रोड्यूसर संतोष सिंह, रोशेल सिंह और पर्ल ग्रे ने प्रोड्यूस किया है। मेरठ की पृष्ठभूमि पर आधारित यह पारिवारिक ड्रामा, ग्रामीण मानसिकता के साथ प्रतिध्वनित होता है क्योंकि यह महिला सशक्तिकरण को प्रोत्साहित करने, सामाजिक मुद्दों से जूझने के विषयों पर केंद्रित है और यह दो विविध व्यक्तित्वों की एक भावुक प्रेम कहानी भी है। यह शो आज के ग्रामीण युवाओं की आकांक्षाओं और आशाओं को छूता है क्योंकि उनमें से अधिकांश उच्च शिक्षा के बाद बेहतर नौकरी चाहते हैं और अपने जीवन के विकल्प तय करने की स्वतंत्रता भी चाहते हैं। यह शो आज के ग्रामीण युवाओं की आकांक्षाओं और आशाओं को छूता है क्योंकि उनमें से अधिकांश उच्च शिक्षा के बाद बेहतर नौकरी चाहते हैं और अपने जीवन के विकल्प तय करने की स्वतंत्रता भी चाहते हैं। यह शो पवित्रा नामक एक युवा लड़की की यात्रा को दर्शाता है जो एक वंचित टैक्सी ड्राइवर की बेटी है और अपनी शिक्षा पूरी करने और आत्मनिर्भर बनने की इच्छा रखती है। वह अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाती है, उन सभी प्रतिबंधों के खिलाफ लड़ती है जो उसके विकास, लिंग भेदभाव और सामाजिक कलंक के खिलाफ लड़ती हैं और अंतत: एक सफल उद्यमी बन जाती हैं जो अन्य महिलाओं को अपने परिवार और खुद की हर तरह से देखभाल करने में सक्षम बनने में मदद करती हैं। पवित्रा की भूमिका शैली प्रिया ने निभाई है और कलाकारों की टुकड़ी में नीलू वाघेला शामिल हैं। साथ में कुमार राजपूत और शीजान मोहम्मद।

फिर एक साथ दिखेंगे मनोज वाजपेयी और प्रियामणि

इस साल की सबसे चर्चित जोड़ी मनोज बाजपेयी और प्रियामणि, जिन्होंने द फैमिली मैन में मध्यवर्गीय भारत की आकांक्षाओं को पूरी तरह से प्रदर्शित किया, इस बार रुपेक के लिए एक दिल को छू लेने वाले विज्ञापन अभियान में वापस आ गए हैं। अभियान के माध्यम से, रुपेक का लक्ष्य आम आदमी और महिला को सुरक्षित, व्यक्तिगत और तनाव मुक्त तरीके से क्रेडिट तक पहुंचने के लिए अपने सोने का उपयोग करने में गर्व महसूस करने के लिए प्रेरित करना है। उधार देने वाले भागीदारों के साथ अपने भरोसेमंद संबंधों के माध्यम से, रुपेक अपने ग्राहकों को न्यूनतम दस्तावेजीकरण और 0.69 प्रतिशत प्रति माह की न्यूनतम ब्याज दर के साथ ऑनलाइन गोल्ड लोन प्रदान करता है।

भारत में, जहां सुरक्षित ऋण तक पहुंच अभी भी दुर्लभ है, रुपेक, एक नए युग का, अभिनव फिनटेक ब्रांड विघटनकारी प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित पेशकशों को डिजाइन कर रहा है जिसका उद्देश्य एक अरब भारतीयों के लिए विकास को अनलॉक करने वाले क्रेडिट दर्द बिंदुओं को हल करना है। रूपेक का अब तक का पहला ब्रांड अभियान, जिसमें मनोज बाजपेयी और प्रियामणि ने अभिनय किया है, सबसे कम ब्याज दरों पर परेशानी मुक्त डोरस्टेप गोल्ड लोन की पेशकश को प्रदर्शित करता है। ब्रांड सहयोग पर बोलते हुए, अभिनेता मनोज बाजपेयी ने कहा, ''मैं रुपेक के साथ जुड़ने और आम आदमी के लिए क्रेडिट उपलब्ध कराने के इसके मूल मूल्य को लेकर उत्साहित हूं। यह देखना अद्भुत है कि कैसे युवा उद्यमी और कम्पनियां उन मुद्दों को संबोधित कर रही हैं जो हमारे समाज में गहराई से घुसे हुए हैं। इस फिल्म के माध्यम से, हमने गोल्ड लोन से जुड़े कलंक को तोड़ने और लोगों को चुनौतीपूर्ण समय के दौरान सशक्त महसूस कराने के लिए गोल्ड लोन की क्षमता पर एक गहरा संदेश देने की कोशिश की है।''

आईपीएल में सीमित दर्शकों को ही अनुमति

● स्टेडियम में दर्शकों की क्षमता का 50 प्रतिशत होगी

भाषा। नई दिल्ली

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के आयोजकों ने बुधवार को घोषणा की कि संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में रविवार से बहाल होने वाले टी-20 टूर्नामेंट के दौरान सीमित दर्शकों को स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। आईपीएल को मई में बायो-बबल में कई कोविड-19 पॉजिटिव मामले मिलने के बाद निलंबित कर दिया गया था जो अब रविवार से बहाल हो रहा है। रविवार को दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में गत चैम्पियन मुंबई इंडियंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा।

आईपीएल के बयान के अनुसार, यह मैच महत्वपूर्ण मौका होगा क्योंकि कोविड-19 हालात से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण एक संक्षिप्त अंतराल के बाद आईपीएल स्टेडियमों में दर्शकों की वापसी का स्वागत करेगा। इसके अनुसार, मैच दुबई, शारजाह और अबुधाबी में खेले जाएंगे जिसमें कोविड-19 प्रोटोकॉल और यूएई सरकार के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए बैठने के लिए सीमित सीट उपलब्ध होंगी। वर्ष 2019 के बाद पहली बार आईपीएल दर्शकों के सामने खेला जाएगा। पिछले साल लीग यूएई में दर्शकों के बिना खेली गई थी जबकि 2021 चरण का पहला हाफ भी कड़े बायो-बबल में खेला गया था। लीग के आयोजकों ने हालांकि प्रवेश के लिए दर्शकों की सही संख्या का जिक्र नहीं किया लेकिन सूत्रों ने कहा कि उनकी उपस्थिति स्टेडियम में दर्शकों की क्षमता का 50 प्रतिशत होगी। लीग के आयोजकों ने कहा, प्रशसंक आधिकारिक वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट आईपीएल टी-20 डॉट कॉम पर बचे हुए टूर्नामेंट के लिए 16 सितंबर से टिकट खरीद सकते हैं। टिकट प्लेटिनमलिस्ट डॉट नेट से भी खरीदे जा सकते हैं। पिछले साल कोविड-19 महामारी के कारण पूरी दुनिया में खेल प्रतियोगिताएं स्थगित हो गई थीं। जिसके बाद प्रतिस्पर्धी प्रतियोगिताएं धीरे धीरे कड़े बायो-बबल में बहाल हुईं। मार्च 2020 में कोरोना वायरस के फैलने के बाद पिछले साल नवंबर से जनवरी तक भारत और आस्ट्रेलिया के बीच श्रृंखला के दौरान पहली बार पुरूष क्रिकेट में दर्शकों को स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति दी गई। पिछले साल आस्ट्रेलियाई महिला टीम और न्यूजीलैंड महिला टीम के बीच सीमित ओवरों की श्रृंखला भी आस्ट्रेलिया में दर्शकों की उपस्थिति में खेली गई।

दुबई में दिल्ली कैपिटल्स के सहायक कोच मोहम्मद कैफ (आर) एक अभ्यास सत्र के दौरान

पहले मैच के प्रदर्शन से ही लय बनेगी: कैफ

दुबई। दिल्ली कैपिटल्स के सहायक कोच मोहम्मद कैफ ने कहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग के दूसरे चरण में पहले मैच के प्रदर्शन से ही शीर्ष पर काबिज उनकी टीम की लय बनेगी। भारत में बढते कोरोना मामलों के कारण मई में स्थगित आईपीएल का दूसरा चरण 19 सितंबर से यूएई में खेला जाएगा। दिल्ली इस समय आठ मैचों में 12 अंक लेकर शीर्ष पर है। कैफ ने एक विज्ञप्ति में कहा , आईपीएल के पहले चरण के बाद लंबा ब्रेक हो गया लेकिन हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे अधिकांश खिलाड़ी लगातार अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलते रहे हैं। उन्होंने कहा , हमारे पास संतुलित टीम है क्योंकि इसमें अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट का अनुभव रखने वाले खिलाड़ी हैं। पहला मैच काफी अहम होगा। इससे हमारी लय बनेगी। कैफ ने कहा कि लीग यूएई में होने से कई खिलाड़ियों की भूमिका बदल सकती है। उन्होंने कहा, हमने भारत में अच्छा खेला और अब उस प्रदर्शन को यूएई में बरकरार रखना है ।कुछ खिलाड़ियों की भूमिका बदल सकती है क्योंकि यहां हालात अलग हैं। हमें नए सिरे से शुरूआत करनी होगी और हालात के अनुकूल ढलना होगा। कंधे की चोट के कारण पहले चरण से बाहर रहे श्रेयस अय्यर की टीम में वापसी हुई है।

आईसीसी टी-20 रैंकिंग में विराट चौथे, राहुल छठे स्थान पर बरकरार

भाषा। दुबई

भारतीय कप्तान विराट कोहली और स्टार बल्लेबाज लोकेश राहुल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की नवीनतम टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में बल्लेबाजी सूची में क्रमश: चौथा और छठा स्थान बरकरार रखा है जबकि गेंदबाजी सूची में कोई भारतीय शीर्ष 10 में शामिल नहीं है। इंग्लैंड के डेविड मलान बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर चल रहे हैं। शीर्ष सात बल्लेबाजों की रैंकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक आठवें स्थान पर पहुंच गए हैं जबकि वेस्टइंडीज के एविन लुईस एक स्थान के नुकसान से नौवें स्थान पर हैं। गेंदबाजों की सूची में तबरेज शम्सी शीर्ष पर कायम हैं जबकि उनके बाद वानिंदु हसारंगा और राशिद खान का नंबर आता है। गेंदबाजी रैंकिंग में भारत के शीर्ष गेंदबाज अनुभवी भुवनेश्वर कुमार हैं जो 12वें स्थान पर चल रहे हैं। चोटिल आफ स्पिनर वाशिंगटन सुंदर 18वें स्थान के साथ शीर्ष 20 में शामिल एक अन्य भारतीय गेंदबाज हैं। युजवेंद्र चहल एकमात्र गेंदबाज हैं जिनकी रैंकिंग में सुधार हुआ है। वह अब 25वें स्थान पर हैं। उन्हें हालांकि टी-20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं दी गई है। आलराउंडरों की सूची में हार्दिक पंड्या शीर्ष 20 में शामिल एकमात्र भारतीय हैं। वह 98 अंक के साथ सूची में जगह बनाने में सफल रहे हैं। भारत ने पिछली टी20 श्रृंखला श्रीलंका में खेली थी और इसके बाद से टीम ने सबसे छोटे प्रारूप में कोई मुकाबला नहीं खेला है। बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान दो स्थान के फायदे से आठवें स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ श्रृंखला में आठ विकेट चटकाए। नासुम अहमद 25 स्थान के फायदे से 15वें जबकि मेहदी हसन चार स्थान के फायदे से 20 स्थान पर पहुंच गए हैं। बांग्लादेश के शाकिब अल हसन ने हालांक आलराउंडरों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी को गंवा दिया है। बल्लेबाजों की एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में अमेरिका के जसकरण मल्होत्रा 169 स्थानों की लंबी छलांग के साथ 132वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

तीनों प्रारूपों में रोहित शर्मा की तरह प्रदर्शन करना चाहती हैं एलिसा हीली

भाषा। ब्रिसबेन

आस्ट्रेलिया की शीर्ष महिला क्रिकेटर एलिसा हीली ने कहा कि वह रोहित शर्मा से प्रेरणा लेकर इस भारतीय स्टार सलामी बल्लेबाज की तरह खेल के तीनों प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन करना चाहती हैं। विकेटकीपर बल्लेबाज हीली भारत के खिलाफ 21 सितंबर से शुरू हो रही श्रृंखला की तैयारियों में जुटी हैं। आस्ट्रेलियाई महिला टीम भारत के खिलाफ तीन वनडे, एक दिन रात्रि टेस्ट और तीन टी20 मैचों की श्रृंखला खेलेगी। हीली ने अभी तक केवल चार टेस्ट मैच खेले हैं और उनका कहना है कि वह गुलाबी गेंद के मुकाबले को वनडे की तरह ही खेलना चाहेंगी जो कैनबरा में 30 सितंबर से तीन अक्टूबर तक खेला जाएगा। हीली ने श्रृंखला के लांच फाक्स क्रिकेट कार्यक्रम में कहा, यह (गुलाबी गेंद का टेस्ट) पेचीदा होगा क्योंकि मैंने सिर्फ चार टेस्ट मैच ही खेले हैं इसलिए मैं यह नहीं कहूंगी कि मैं टेस्ट मैच में खेलने के लिए सहज हूं। उन्होंने कहा, जहां तक मेरी बात है तो इस टेस्ट में मेरी वनडे बल्लेबाजी से ज्यादा कुछ बदलाव नहीं होने वाला है। मुझे लगता है कि खुद को और ज्यादा समय देना (बल्लेबाजी के लिए) शानदार है। उन्होंने कहा, आधुनिक टेस्ट मैच को देखें तो यह काफी बदल गया है।

तालिबान से बचकर पाकिस्तान पहुंची अफगानिस्तानी 32 महिला फुटबॉलर

भाषा। इस्लामाबाद

अफगानिस्तान की 32 महिला फुटबॉल खिलाड़ी अपने परिवारों के साथ पाकिस्तान पहुंच गई हैं जिन्हें तालिबान से धमकियों का सामना करना पड़ रहा था। बुधवार को एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उन्हें निकालने के लिए सरकार द्वारा आपात मानवीय वीजा जारी किए जाने के बाद ए फुटबॉलर पाकिस्तान पहुंची। राष्ट्रीय जूनियर बालिका टीम की इन खिलाड़ियों को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कतर जाना था जहां अफगान शरणार्थियों को 2022 फीफा विश्व कप के एक स्टेडियम में रखा गया है। लेकिन काबुल हवाईअड्डे पर 26 अगस्त को हुए एक बम धमाके के कारण वे ऐसा नहीं कर सकीं जिसमें 13 अमेरिकी और कम से कम 170 अफगान नागरिकों की मौत हो गई थी। डॉन अखबार की रिपोर्ट के अनुसार इन महिला खिलाड़ियों को फुटबॉल खेलने के लिए तालिबान से धमकियों का सामना करना पड़ रहा था। इस रिपोर्ट के अनुसार अगस्त में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता पर काबिज होने के बाद ए खिलाड़ी तालिबान से बचने के लिए छुपती फिर रही थीं। ब्रिटेन के एक गैर सरकारी संगठन फुटबॉल फॉर पीस ने सरकार और पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ (जो फीफा से मान्यता प्राप्त नहीं है) की मदद ने इन 32 खिलाड़ियों को पाकिस्तान लाने की शुरूआत की। फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फैनटिनो पिछले हफ्ते दोहा यात्रा के दौरान अफगानिस्तानी शरणार्थियों से मिले थे। लेकिन फीफा की इस बात के लिए आलोचना की गई थी कि उसने अफगानिस्तान में इन महिला फुटबॉलरों की मदद के लिए कोई कदम नहीं उठाया था। ए महिला फुटबॉलर पेशावर से लाहौर जाएंगी जहां उन्हें पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ के मुख्यालय में रखा जाएगा।

अभिषेक और पारुल ने 5000 मीटर दौड़ जीती

भाषा। वारंगल

रेलवे के धावकों अभिषेक पॉल और पारूल चौधरी ने बुधवार को यहां जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में 60वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन क्रमश: पुरुष और महिला 5000 मीटर दौड़ के खिताब जीते। फेडरेशन कप के 5000 मीटर के चैंपियन अमित जांगीड़ बुधवार को रेस में हिस्सा नहीं ले रहे थे और ऐसे में मुकाबला मुख्य रूप से रेलवे के 24 साल के अभिषेक और सेना के धावकों के बीच था। अभिषेक हालांकि 14 मिनट 16.35 सेकेंड के समय के साथ 5000 मीटर में अपना पहला राष्ट्रीय खिताब जीतने में सफल रहे। अभिषेक दौड़ में अधिकतर समय तीसरे स्थान पर थे लेकिन अंतिम 300 मीटर में उन्होंने काफी तेजी दिखाई और सबसे आगे चल रहे धर्मेंद्र को पछाड़ दिया जो 14 मिनट 17.20 सेकेंड के समय के साथ दूसरे स्थान पर रहे। अजय कुमार ने 14 मिनट 20.98 सेकेंड के समय के साथ कांस्य पदक जीता। महिला 5000 मीटर दौड़ में पारूल ने 15 मिनट 59.69 सेकेंड के समय के साथ खिताब जीता। वह अधिकांश समय कोमल चंद्रकांत जगदाले से पीछे थी लेकिन अंतिम 250 मीटर में उन्हें पछाड़ने में सफल रही। महाराष्ट्र की 22 साल की कोमल ने 16 मिनट 1.43 सेकेंड के समय के अपने निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। महाराष्ट्र की ही संजीवनी बाबर जाधव ने 16 मिनट 19.18 सेकेंड के समय से कांस्य पदक जीता। महिला पोल वॉल्ट में तमिलनाडु की पवित्रा वेंकटेश ने 3.90 मीटर के प्रयास के साथ स्वर्ण पदक जीता। रेलवे की मारिया जेसन (3.80 मीटर) ने दूसरा जबकि कृष्णा राचन (3.60 मीटर) ने तीसरा स्थान हासिल किया।